an>

Title : Discussion on Price Rise

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 20.

श्री विनायक भाउराव राऊत – उपस्थित नहीं ।

श्री मनीष तिवारी जी ।

श्री मनीष तिवारी **(आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष जी, आज महंगाई जैसे विषय से सारा देश पीड़ित है, आपने मुझे उस विषय पर चर्चा आरंभ करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । जो महंगाई पर चर्चा है, यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रही है और मैं उस परिप्रेक्ष्य का इस सदन के समक्ष जिक्र करना जरूरी समझता हूं ।**

अध्यक्ष जी, कोई भी अर्थव्यवस्था पांच बिन्दुओं के ऊपर खड़ी है । पांच मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है । सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार है । अंग्रेजी में इसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंज्प्शन और इम्प्लॉयमेंट । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले आठ वर्षों में ये जो पांचों मूलभूत आधार हैं, इनके परखच्चे उड़ गए हैं । वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, तब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया । ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी । उस रिपोर्ट के मार्फत यह पता लगा कि दोबारा से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं ।

14.20 hrs **(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)**

सभापति महोदय, अनूप सतपथी समिति कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपये प्रतिदिन की बैंचमार्क पर है और वे उससे नीचे चले गए हैं । इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश का जो 77 प्रतिशत धन है, वह सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के हाथ में है । इन वर्षों में भारत के जो बिलेनियर्स हैं, वे 100 से बढ़कर 142 तो हो गए हैं, लेकिन जो सबसे नीचे का तबका है, उस तबके की जो आय है, वह दिन-ब-दिन घटती चली जा रही है । सबसे अमीर जो 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है, जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है । इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती है ।

इन सबकी शुरूआत 8 नवम्बर, 2016 को हुई थी, जब भाजपा की सरकार ने बगैर सोचे-समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी । 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये डिमोनेटाइज हुए थे और उनमें से 99 प्रतिशत यानी 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे । आज तक इस बात की जानकारी न तो सदन को दी गई है और

यहां तक की यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह मामला पिछले आठ वर्षों से उच्चतम न्यायालय में लंबिंत है कि यह फैसला क्यों लिया गया और उस फैसले का इस देश के ऊपर क्या असर पड़ा । सभापति महादेय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका असर यह पड़ा है कि जीडीपी की जो वृद्धि दर थी, वह वर्ष 2017-18 में 6.8 प्रतिशत थी । वर्ष 2018-19 में गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई । वर्ष 2019-20 में गिरकर 3.7 प्रतिशत हो गई । वर्ष 2021-22 में यह माइनस 6.6 प्रतिशत हो गई, जिसमें कोविड का बहुत बड़ा असर रहा और वर्ष 2021-22 में यह दर 8.9 प्रतिशत पर आई, लेकिन यह आँकड़ा एक मिथ्य है, क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.3 प्रतिशत की थी । मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ, वह सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ । कोविड उसमें एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वर्ष 2018-19 से पहले के जो 6 महीने थे, उस समय कमर्शियल सेक्टर में जो फंड फ्लो था, वह 7 लाख 36 हजार 87 करोड़ रुपये से गिरकर सिर्फ 90 हजार 995 करोड़ रुपये रह गया । उसमें 87.6 प्रतिशत की गिरावट आ गई । इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी को लागू किया । उस जीएसटी का सीधा-सीधा असर यह हुआ कि 2 लाख 30 हजार जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे, वे छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वे आज भी उस मार से उभर नहीं पाए हैं ।

सभापति महोदय, आज की तारीख में जो एमएसएमई सेक्टर है, उनका 10.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है । यह सरकारी बकाया नहीं है but they have outstanding of Rs. 10.6 lakh crore. अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, इस सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि जो लघु क्षेत्र है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, अगर उसकी पेमेंट्स टू दी एक्सटेंट ऑफ 10.6 लाख करोड़ रुपये डिले होगी तो वह क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा । इस नोटबंदी और जीएसटी का असर सिर्फ लघु उद्योग पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका असर रोजगार पर भी पड़ा है । वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 4.77 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 7 प्रतिशत, 2019 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत, 2020 में बढ़कर 9.1 प्रतिशत, 2021 में 7.9 हो गई और जून, 2022 में यह 7.8 प्रतिशत है । सभापति महोदय, किसी भी विकसित देश में जो मापदण्ड है, वह यह है कि दो-तिहाई लोगों को रोजगार मिलना चाहिए । आज की तारीख में, भारत में लगभग 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है । अगर हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेकर जाना जरूरी है । मैं यह दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इसे 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेकर जाने के लिए कोई रणनीति नहीं है । आज मनरेगा की जिस तरह से डिमाण्ड बढ़ी है, वह रोजगार की समस्या का जीता-जागता प्रमाण है । अप्रैल, 2022 में 2.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा, मई, 2022 में 3.7 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा और जून, 2022 में यह संख्या बढ़कर 3.17 करोड़ हो गई । वर्ष 2006 में जब से यह स्कीम शुरू हुई थी, यह उन लोगों का

हाइएस्ट नम्बर है, जो मनरेगा के सहारे अपनी जिन्दगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं । मैं इस सदन में इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब आठ वर्ष पहले यह सरकार बनी थी, तब इसी मनरेगा को उन्होंने 'गड्ढे खोदने की स्कीम' का अलंकरण दिया था ।

आज उसी स्कीम के सहारे करोड़ों परिवारों की गुजर-बसर हो रही है, इसलिए सरकार को अपने शब्द वापस लेने चाहिए । इस सारे संकट से उबारने के लिए जब लोगों की जेब में पैसा डालना जरूरी था, तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने पूंजीपतियों की जेब में पैसा डाल दिया । वर्ष 2019 में 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के कन्सेशन्स कॉरपोरेट सेक्टर को दिए गए और वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच 4 लाख 32 हजार करोड़ रुपये के कन्सेशन्स पूंजीपतियों को इस सरकार ने दिए । अगर उससे भारत की अर्थव्यवस्था किक-स्टार्ट हो जाती, if the engines of the economy would have started firing, I would have had no difficulty with it. But the fact is, despite what the Government thought was a targeted strategy, it did not work और भारत की अर्थव्यवस्था नीचे ही बैठती गई और लोग गरीब होते गए ।

महोदय, अब मैं पेट्रोल और डीजल पर आता हूं । मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो आज हुआ है, उसका कारण आज नहीं है, उसका कारण पिछले आठ वर्षों की इकोनोमिक मिसमैनेजमेंट है । वर्ष 2014-15 से लेकर 2021-22 तक इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपये एक्साइज, टैक्स और डिविडेंड के मार्फत पेट्रोलियम सेक्टर से इकट्ठा किए है । उसमें से 23 लाख 625 करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी के मार्फत और 4 लाख 23 हजार 775 करोड़ रुपये डिविडेंड और इनकम टैक्स के मार्फत इकट्ठा किए गए । अचम्भे वाली बात यह है कि सरकार अपना खजाना तो भरती रही, लेकिन लोगों की जेबें खाली करती रही । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । अप्रैल, 2011 में जब कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर थी, तब पेट्रोल 58 रुपये 56 पैसे में बिकता था और जुलाई, 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत 98.94 डॉलर हो गई, तब पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे में बिक रहा है । 1 मार्च, 2014 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी और 1 अगस्त, 2022 को वह कीमत बढ़कर 1003 रूपये हो गई । अगर आप गरीब लोगों के ऊपर, भारत के मध्यम वर्ग के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालेंगे तो सारा मुल्क महंगाई से त्राहि-त्राहि करेगा ।

अब इन्फ्लेशन, महंगाई पर आ जाइए । इस देश में पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है, जो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है । अप्रैल, 2022 में 15.8 प्रतिशत थी, जुलाई में थोड़ा कम हुई है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स आसमान छू रहा है । इसके अलावा आपने रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया है । उसमें आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, स्याही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर और आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा । इसमें हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कलछियों पर भी बढ़ा दिया है । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है,

जिससे मेरा मन आहत हुआ है कि जो शमशान घाट है, उसके निर्माण के ऊपर भी आपको 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई । आप किस तरह का मुल्क बना रहे हैं? क्या लोगों को हम बिल्कुल जमीन पर लिटा देना चाहते हैं? मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, लेकिन इस देश में जो 25 करोड़ गृहस्थियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है । जब माननीया सुषमा स्वराज जी यहां बैठती थीं, वह कभी कहा करती थीं कि ग्रहणी के आंसू बह रहे हैं ।

आज सही में हर ग्रहणी के आंसू बह रहे हैं, आपने इतनी कमरतोड़ महंगाई कर दी है । मैं आखिर में पंजाबी के एक शायर की तीन लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । पंजाबी में कहते हैं –

पहले तो मूँछ की लड़ाई ने मार दिया, दूसरा, यार की जुदाई ने मार दिया,

तीसरा, रब की खुदाई ने मार दिया और बाकी जो बचा वो महंगाई ने मार दिया ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद । बहुत दिन के बाद आज पार्लियामेंट चली है और जो अपोज़िशन का दर्द था, वह सामने आया । मुझे लग रहा था कि शायद प्राइस राइज इतना बड़ा विषय है कि उसके बारे में पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में, दुनिया की इकोनॉमी के बारे में कांग्रेस पार्टी देश को बताएगी । मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जब दिल और दिमाग का द्वंद्व हो तो अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है, आज पहली बार देखने को मिला । वह उस तरफ बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि किस हालात में वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी है । वर्ष 2015-16 में जब यहां पर अरुण जेटली जी बजट पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक अच्छी शायरी कही थी । मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात हैं? उन्होंने कहा था कि :-

कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में आता है, दरिया करना पार हमें ।

सभापति महोदय, कल मैं अपने क्षेत्र में था । जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से दो-तीन बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, जो बहुत न्यूट्रल हैं । वह हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं । मैंने उनको कहा कि शायद कल पार्लियामेंट चलेगी, प्राइस राइज पर चर्चा है तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, यह बेटे को राइज कराने का चक्कर है ।

आज पूरी दुनिया कोविड के कारण तबाह है । आप अमेरिका, यूरोप को देख लीजिए, आस-पास के पड़ोसी देशों को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर, दुबई को देख लीजिए । सभी देशों में रोजगार छिने जा रहे हैं । सभी देशों में इनफ्लेशन बढ़ रहा है । उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि चाइना में बैंकों के सामने टैंक लगे हुए हैं । उस हालात में, यदि हमारे यहाँ गरीबों को दो वक्त का खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उनको जो दो वक्त की रोटी मिल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसी पार्लियामेंट में हम और आप सांसद थे, प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? पिछले आठ वर्षों में अपोजिशन ने एक बार भी किसानों की आत्महत्या के ऊपर क्या चर्चा की है? यदि नहीं की है, तो इसका मतलब है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं । हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहे हैं । आज किसानों की क्या स्थिति है? आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, हमने किसानों को इस तरह से मजबूत किया कि वह साल भर तक आन्दोलन करता रहा, लेकिन किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की ।

हमने उसको इतनी ताकत दी कि वह सरकार के खिलाफ भी दो-दो हाथ करने को तैयार है । आपके यहाँ तो वे भीख मांग रहे थे । आप तो उनको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे । आप उनका कर्जा वापस नहीं करवा पा रहे थे । यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे । क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए?

अभी गैस सिलेंडर की बात हुई । ज़ुबेर साहब हैं अल्ट न्यूज़ के, कांग्रेस वाले उनको बहुत मदद करते हैं, कहा जाता है कि वे बहुत बड़े फैक्ट चेकर हैं । हम लोग जो ट्विटर, फेसबुक आदि चलाते हैं, वे उनके फैक्ट चेकर हैं । माननीय सभापति जी, आपको पता है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के 139 सांसद थे और केवल कांग्रेस के 141 सांसद थे । वर्ष 2009 में हम लोग 120 सांसद थे । लेकिन हम लोगों ने स्पीकर के सामने कभी भी प्लेकार्ड्स नहीं लाए, कभी चेयर की बदनामी नहीं की, कभी हमने उनकी इज्ज़त से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की । लेकिन आप करते रहे । हम लोग हमेशा वेल में आते रहे, मैं यह नहीं कहता कि हम लोग वेल में नहीं आए, लेकिन हम लोग कभी भी प्लेकार्ड्स लेकर नहीं आते थे ।... (व्यवधान) मुझे यह लगा कि यदि मैं कोई बात कहूँगा, ... (व्यवधान)

यह जो सरकार थी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 'ज्यादा जोगी मठ उजाड़ ।' श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे । चिदम्बरम साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, श्री प्रणब बाबू

बाद में माननीय राष्ट्रपति हो गए, लेकिन वे तत्कालीन वित्त मंत्री थे । वे वर्ष 1980 में भी वित्त मंत्री थे । श्री रंगराजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया उनके एडवाइजर थे । रघुराम राजन, कौशिक बसु साहब आ गए, इतने इकोनॉमिस्ट्स लोग थे कि आप बात करिए और आपको लगेगा कि बस दो मिनट में ही सब खत्म हो जाएगा । इसके बाद कमेटी पर कमेटी बनती थी । कैसे एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की प्राइस ठीक करनी है, कैसे एपीएम के दायरे से उसे मार्केट में ले जाना है, इन्होंने वर्ष 2006 में एक रंगराजन कमेटी बना दी, उससे इनका कोई वास्ता नहीं हुआ, उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो वर्ष 2010 में इन्होंने एक पारिख कमेटी बना दी, वर्ष 2011 में नंदन नीलकेनी कमेटी बना दी और वर्ष 2012 में केलकर कमेटी बना दी । आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जनता के साथ करती रही । हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जिसने वर्ष 1952 में शिलान्यास किया, वर्ष 1957 में कहा कि इसका लैंड एक्विजिशन हो रहा है, वर्ष 1962 में कहा कि अब हमने इसमें पैसे दे दिए हैं, वर्ष 1967 में उन्होंने कहा कि अब रेल की पटरी बिछाना शुरू कर दी गई है और वर्ष 1980 में एक-एक प्रोजेक्ट जिस तरह से तीस-चालीस साल में इस देश में बने, उसका उदाहरण एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की प्राइसिंग है ।

सर, मैं यही कह रहा था, मुझे यह लगा कि यदि मैं ये बातें कहूंगा, तो शायद मेरी बातों को ये लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़े समाजवादी हैं, सोशलिस्ट्स हैं । ये सब लोग मोदीफोबिया से ग्रसित हैं । कुछ भी होगा, तो ये कहेंगे कि यह मोदी ने कर दिया, मोदी को यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था । मोदी जी के प्रति इन लोगों को इतनी एलर्जी है कि अच्छी बात भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं हैं ।

इसलिए मैं Alt News के जुबैर की बात का विषय लेकर आया । उसने लिखा है कि जुलाई, 2011 में 710 रुपये नॉन-सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत थी और जो सब्सिडी हम दे रहे थे, वह 400 रुपये दे रहे थे । इसका मतलब यह था कि वर्ष 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1,110 रुपये थी । ... (व्यवधान) मैं इसे ऑन-रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा । ... (व्यवधान) वर्ष 2012 में सिलेंडर की जो कीमत थी, वह 922 रुपये थी । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब आप बोल रहे थे, तो सबने सुना है । अब आपको भी सुनना पड़ेगा ।

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे : उसमें जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी, वह 410 रुपये दे रही थी । कितना हो गया? आप मुझे जोड़कर बता दीजिए, मैं गांव का आदमी हूं, इसलिए मुझे जोड़ना नहीं आता । आप जरा जोड़कर बता दीजिए । वर्ष 2013 में नॉन-सब्सिडी सिलेंडर

की कीमत 1,021 थी और उसमें हम 410 रुपये की सब्सिडी दे रहे थे । ... (व्यवधान) वर्ष 2014 में सिलेंडर की कीमत 1,241 थी और उसमें 414 की सब्सिडी दे रहे थे । ... (व्यवधान) यह 1 जनवरी, 2014 की बात है । ... (व्यवधान) इसके बाद जब हमारी सरकार आई, तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी । ... (व्यवधान) आज आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं? मैंने पिछली बार कहा कि क्या करें? आप कहते हैं कि आठ साल से हम सरकार चला रहे हैं । मैंने पिछली बार बताया था कि इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, जिससे ये जो हमेशा दावा करते हैं कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस, सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए । मैंने उस दिन भी कहा कि आपकी सरकार कैसी कॉरपोरेट सरकार है, इसके लिए मैं सारे डिबेट्स लेकर आया हूं और मैं इस पर पूरी बहस करना चाहता हूं । मैं श्री एस. ए. डान्गे का भाषण लेकर आया हूं, मीनू मसानी जी का भाषाण लेकर आया हूं, मैं नाथ पई जी का भाषण लेकर आया हूं । वर्ष 1958 से लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि यह जो कांग्रेस है, यह कॉरपोरेट की सरकार है । यह टाटा का समर्थन करती है, बिड़ला का समर्थन करती है, डालमिया का समर्थन करती है और अंबानी और अडानी का समर्थन करती है । ... (व्यवधान) 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, और आज वर्ष 2020 के बाद से, वह भारत सरकार का दस साल का बॉन्ड था, वर्ष 2011 के बाद से जितने भी बॉन्ड्स हुए, आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये, जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए, कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं, आज 3.5 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार को लौटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार कन्टिन्युइटी है । ... (व्यवधान) वे सभी बड़े कॉरपोरेट्स हैं । जिन्होंने ऑयल बॉन्ड्स लिए हैं, वे सारे बड़े कॉरपोरेट्स हैं और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन हैं, उनसे पूछें कि किस अमीर को फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया? देश के लोगों के साथ धोखा किया, जिसके कारण प्रत्येक साल भारत सरकार को 20-25 हजार करोड़ रुपये लौटाने पड़ रहे हैं । ... (व्यवधान)

सर, फूड प्राइस की बात हो रही है, यह अच्छी बात है । एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, जिसके लिए एमएसपी की कमेटी बनी है । हमारी सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई और हमारी सरकार कमिटेड है कि जो एमएसपी है, उससे कैसे आपकी आय दोगुनी होगी, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है । लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया में क्या हालात हैं? आप यह समझिए कि वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया के आज जो हालात हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं ।

महोदय, मनीष तिवारी जी जीडीपी की बात कर रहे थे । वर्ष 1950 से लेकर 1990 तक हमारी जीडीपी, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, मोरारजी देसाई के समय केवल दो-ढाई साल के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस समय के दौरान जीडीपी 3.3 परसेंट से 3.5 परसेंट थी । मैक्सीमम जीडीपी 4 परसेंट पर गई । उस समय सहारा जैसी जो छोटी कंट्री थी, उसका जीडीपी ग्रोथ 5.5 परसेंट था । उस समय से निकल कर आज के समय कोविड के बाद दुनिया में आज आप हमारी जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं । मैं प्राइस इंफ्लेशन की बात करूंगा और सदन को बताना चाहता हूं कि क्यों आज प्राइस बढ़ रहे हैं । आज व्हीट का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एक परसेंट घट गया है । पूरी दुनिया में राइस का प्रोडक्शन 0.5 परसेंट कम हो गया है । शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया है । यूक्रेन और रशिया दुनिया को एक तिहाई गेहूं सप्लाई करते हैं । 75 परसेंट सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन और रशिया सप्लाई करते हैं । क्या हमने यह लड़ाई करा दी और दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम कर? इस स्थिति के बाद भी यदि हमारे प्रधान मंत्री 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं हैं? क्या हमें प्रधान मंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए?... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है । जब मनीष जी बोल रहे थे, तब हमने उनकी बात सुनी । With rapt attention, hon. Finance Minister has also listened to him. … (*Interruptions*). Everybody should speak with all seriousness. … (*Interruptions*) Why crosstalk? … (*Interruptions*) No need, you can speak when your turn comes … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : जब आपकी पार्टी के वक्ता मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, तब एक बार भी टोका-टाकी नहीं हुई ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : अधीर जी, आप नेता हैं, आप बैठ जाएं । आपको माननीय सदस्य की बात सुननी पड़ेगी । जब आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा ।

निशिकांत जी, आप बोलिए ।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति जी, यदि 'फंड' शब्द से आपत्ति है, तो मैं कहूंगा कि हम फ्री में दे रहे हैं, मतलब आप समझिए कि हम उन्हें सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं । यह बात तो अच्छी है । पूरी दुनिया के कोविड के बाद के जो हालात हैं और हमारे जो हालात हैं, उन्हें सदन को जानने की आवश्यकता है । यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है । वर्ल्ड बैंक ने फूड

सिक्योरिटी के लिए इजिप्ट जैसी कंट्री जो कि बड़ी कंट्री है, उसे 500 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी फंड दिया है । ट्यूनेशिया को वर्ल्ड ने 130 मिलियन डॉलर का सपोर्ट फंड दिया है । 2.3 बिलियन डॉलर सदर्न अफ्रीका को वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है । बांग्लादेश जैसी कंट्री को 87.8 मिलियन डॉलर फंड फूड सिक्योरिटी के लिए दिया है । भूटान को 0.5 बिलियन डॉलर दिया है । चाड जैसी छोटी कंट्री को 30 मिलियन डॉलर दिए हैं । ग्वाटेमाला को वर्ल्ड बैंक ने 40 मिलियन डॉलर का फंड दिया है । मैं पूरी दुनिया के देशों के आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश है कि आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं । हम चावल दुनिया को दे रहे हैं । हम गेहूं दुनिया को दे रहे हैं । शुगर दुनिया को दे रहे हैं और यदि किस्मत ने साथ दिया तो ऑयल भी कुछ दिनों के बाद दुनिया को देंगे, हमारी इस तरह की पालिसी है और आप प्राइस राइज की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो । मैं देख रहा था कि मार्च, 2022 में टमाटर का कितना दाम था, आलू का दाम कितना था और आज जुलाई में टमाटर और आलू का कितना दाम है । यदि आप मार्केट जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मार्च में जितना दाम था, उससे कम दाम टमाटर, आलू और प्याज का आज है । क्या इसके लिए हमें सरकार को बधाई नहीं देनी चाहिए?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग कृपया बीच में टिप्पणी मत कीजिए । जब आपका समय आए, तब बोलें ।

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नूर जी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि–

'सच घटे या बढ़े, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती ।'

सच यदि कम बोलें, तो भी वह झूठ हो जाता है और यदि ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बोलें, तो भी वह सच नहीं रहता है, लेकिन झूठ चाहे जितना मर्जी उतना बोलते रहिए । कांग्रेस का तो यही इतिहास रहा है । किसी चीज पर वह बहस ही नहीं करना चाहती है । श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में श्री जयशंकर जी उस दिन बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि उनको श्रीलंका के बारे में बताना चाहिए था और वह फ्री बीज के बारे में बताने लगे । मनीष तिवारी जी, जिन्होंने अपना भाषण कहा, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज पंजाब के क्या हालात हैं? बैंक उसे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है । पैसा कहां से आएगा? एफआरबीएम एक्ट का इन लोगों ने बाजा बजा दिया है । चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वे कहां से पैसा लाएंगे? कर्जा आप लें और उसके बाद आप कहें कि मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, मोदी जी के कारण बढ़ रहा है ।

आज अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स चाहे तेलंगाना हो, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देने के लिए तैयार नहीं है । आज सारे सदन को और पूरे देश को यह देखने की आवश्यकता है । एलपीजी सिलेंडर की बात यदि हम करते हैं, तो इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम अपनी सब्सिडी छोड़ दें, तो देश के सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी । आज 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से हम लोगों ने फायदा पहुंचाया है । प्रत्येक साल वे 3 सिलेंडर ले रहे हैं । कोई भी सिलेंडर खाली नहीं है, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं । फ्री बीज़ के बाद इस देश की क्या इकोनॉमी होनी है, यह सोचने का सवाल है । क्या केवल वोट ही जीतते रहोगे, 5 सालों के लिए शासन करोगे या अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर स्थिति छोड़कर जाओगे, क्या यह सोचने का सवाल नहीं है? क्या हम सरकार नहीं चला रहे हैं? बिहार में हमारी सरकार है । क्या असम में हम सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या राजस्थान में हम सरकार नहीं चला रहे थे? क्या हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या हमें वोट नहीं चाहिए? हम फ्री बीज़ की बात नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है कि यह देश हमारा है । एक चुनाव हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है । यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही कारण है कि बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप गए थे, तो आपने पूरे के पूरे बैंक्स को एनपीए कर दिया था । आप केवल फोन बैंकिंग के आधार पर लोगों को कर्ज दिया करते थे । आपने बैंकों की स्थिति खराब कर दी, आपने इकोनॉमी की स्थिति खराब कर दी । आप 3 परसेंट जीडीपी पर हमें छोड़कर गए और आज आप हमसे हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं । आप ब्लैक मनी की बात करते हैं ।

सर, मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक ब्लैक मनी है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में अभी 55 करोड़ रुपये पार्थो या उनके दोस्त के यहां पकड़ा गया । ... (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि यह पैसा मेरा नहीं है । झारखंड का एमएलए कैश लेकर बंगाल में पकड़ा गया, लेकिन वह कहता है कि यह मेरा पैसा नहीं है । झारखंड के मुख्य मंत्री के सचिव, माइनिंग सेक्रेट्री के यहां रेड हो गयी और उनके यहां 20 करोड़ रुपये पकड़े गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरा पैसा नहीं है ।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सदीक (फरीदकोट): जो लाखों करोड़ रुपये लेकर भाग गये, उनका क्या हुआ? ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, विधायक प्रतिनिधि के यहां 20 करोड़ रुपये पकड़े गए, लेकिन वह कहता है कि यह मेरा पैसा नहीं है । कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, मैं बताता हूं । वह ब्लैक मनी की बात करती है, लेकिन ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उसके पास है । सरकार बचाने के लिए इसी पार्लियामेंट में नरसिंह राव जी की सरकार में हमारे ही झारखंड के शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, शैलेंद्र महतो जी, सिमोन मरांडी जी, इन सभी को पैसा

दिया गया और इनके पैसे बैंक अकाउंट चेकिंग के माध्यम से पकड़े गए । ब्लैक मनी आप रखते हैं । वर्ष 2008 में आडवाणी जी ने इसी सदन में कहा कि आप पैसे से हमारे एमपी को खरीद रहे हैं । पैसा जमा करें आप, हूटिंग करें आप, बोफोर्स का पैसा लेकर क्वात्रोची आपके समय में भाग जाए, मुद्रा कांड आप करें, लेकिन ब्लैक मनी का हिसाब आप हमसे मांगें । सुखराम जी आपके मंत्री थे, जिनके घर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए ।

इतना कैश यदि कांग्रेस के नेताओं के पास और उनके यूपीए के पास रहता है तो किस मुँह से आप ब्लैक मनी की बात करते हो ।... (व्यवधान) आप किस मुहँ से ब्लैक मनी लाने की बात करते हो? ... (व्यवधान) स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन करो आप, स्विट्जरलैंड के साथ वर्ष 2011 में एग्रीमेंट साइन करो आप... (व्यवधान) और कहो कि वर्ष 2016 से आपको समझ में आएगा ।... (व्यवधान) इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो ।... (व्यवधान) आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो ।... (व्यवधान) फिस्कल डेफिसिट क्या है? ... (व्यवधान)

आप यह समझिए कि वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1965 तक देश की स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी । वर्ष 1965 के समय जीडीपी का केवल चार परसेंट हम बाहर से कर्ज ले रहे थे । वर्ष 1965 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी । इसके बाद यह कर्ज, बाहर से जो कर्जा है, आज वे कहते हैं कि कैश टू जीडीपी रेश्यो क्या हो गया, कर्ज का रेश्यो हमारे जीडीपी के साथ कैसे हो गया? पॉलिसी किसने बदली? आपने केवल जनता को गुमराह करने के लिए और टैक्स का परसेंटेज आज 72-73 परसेंट करने के लिए वर्ष 1965 के बाद कांग्रेस ने 10 परसेंट, 15 परसेंट, 20 परसेंट, ऐसी सिचुएशन हो गई कि पूरा का पूरा उन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ी थी, हमारे जैसे जो युवा आने वाले थे, जो बच्चे पैदा होने वाले थे, उसके ऊपर कैसे कर्ज बढ़े, वर्ष 1965 से लेकर वर्ष 1990 तक, यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि पूरे देश को, क्योंकि इस देश की याददाश्त बहुत कम रहती है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि जीडीपी, मतलब किस तरह से इन्होंने कर्ज लेने का काम चालू किया और उसके कारण हमारी पीढ़ी को आज कितने घाटे में जाना पड़ रहा है । यदि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं तो उसमें किस तरह की दिक्कत है और फिस्कल डेफिसिट में किस तरह से, एफआरबीएम एक्ट माननीय अटल जी लेकर आए, लेकिन उसके पहले जो फिस्कल डेफिसिट था और जिसके कारण दबादब नोट छापे जा रहे थे बिना कोलैटरल के, उसके कारण भारत को कितना नुकसान हुआ है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इसे देश के सामने लेकर आएं । महोदय, मैं अपनी बात खत्म करते हुए अंत में यही कहूँगा कि इन लोगों को न आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, न जनता से मतलब है । यहाँ कांग्रेस बैठी हुई है । कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ सरकार बनाई ।... (व्यवधान) जब वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी तो उस

वक्त माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने, जो उस वक्त शिव सेना के प्रमुख थे, वे हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने खुलेआम कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी ।... (व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): पीडीपी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? ... (व्यवधान)

*m11 डॉ. निशिकांत दुबे: मैं उस पर भी आऊँगा ।... (व्यवधान) पीडीपी के साथ मिलकर सरकार इसीलिए बनाई, क्योंकि उसने यासीन मलिक को... (व्यवधान) हमारा यह फायदा हो गया कि जिस आतंकवादी के साथ आपके प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचाया, उसी आतंकवादी को उसने कहा, रूबैया सईद जी ने कहा कि मेरा अपहरण इसी आदमी ने किया था ।

आप अपने प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी से पूछो ।... (व्यवधान) मैं आपको यह बता रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे साहब ने यह कहा ।... (व्यवधान) शिव सेना एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी । आपका सेक्युलरिज्म खत्म, आपकी इकोनॉमी खत्म, आपने देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया और इसीलिए मैंने जो आपको कहा कि यह प्राइस राइज नहीं है, यह बेटे को बढ़ाने का चक्कर है ।... (व्यवधान) आप मोदी फोबिया से ऊपर उठिए ।... (व्यवधान) देश के बारे में सोचिए ।... (व्यवधान) कबीर का एक दोहा है कि 'धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय', आप उसका इंतजार कीजिए ।... (व्यवधान) यह देश बदल रहा है, गाँव, गरीब, किसान, आदिवासी को सम्मान मिल रहा है और यह देश खुश है ।... (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द-जय भारत ।

*SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon Chairman Sir, Thank you. Hon Member from BJP Shri Nishikant Dubey while speaking in this august House mentioned about black money. He stated that crores and crores of black money was seized from the non-BJP government ruled States of the country. I have a doubt. When you brought demonetization in the year 2016, it was announced by you that black money will not be anywhere in this country after this demonetization. You should explain to us how this black money is found in this country after demonetization. If you explain it will be helpful to me. I should say that India has seen a major decline in its economy after demonetization. AIADMK, the ally of BJP, when they were ruling Tamil Nadu, stated in their Government's policy note, that too in the State Assembly that demonetization has led to closure of as many as 50000

MSMEs in Tamil Nadu. At the time of demonetization, many persons died while standing in long queues for hours together to exchange old currency notes. This nation had faced several difficulties. The nation with all patience bore the brunt for one reason given by them that there will be no black money in this country after demonetization. But now you are saying that black money is found in this country. If that is so, why we faced lots of difficulties during demonetization. They have to explain this to us. This can only give justice to the people who lost their lives due to demonetization. A child has written a letter to Hon Prime Minister Modi in Hindi. This child is from Kannauj district. It goes like this. "My name is Kriti Dubey. I am studying in I standard. Yes it is Dubey. Modi Ji, You have caused immense price rise. Even my pencil and rubber have got costlier. The price of maggi has increased too. Now my mother beats me for asking for a pencil. What shall I do?" The other kids. I think they don't have pencil. They can't afford to buy the pencil. So, they steal it from her. So, what answer do we have to give. (Interruptions). I don't know.

<u>15.00hrs</u>

"My name is Kriti Dubey. I study in class 1. Modi ji, you have caused immense price rise. Even my pencil and rubber have got costlier and the price of Maggi has been increased too. Now my mother beats me for asking for a pencil. What shall I do? Other kids steal my pencil."

If you don't fulfill any of your promises, what can we do. Just some time ago, Hon Minister said that while you speak, we should be silent. Similarly, when we speak you should be hearing patiently. If you don't follow that assurance as well, what can we do? In this way each and every action of yours is affecting the people belonging to the lower strata of our society. They are facing hardships every day. Life has become a struggle for them. The credit goes to this Union Government. Every now and then the prices of petrol are going up. Before this Government came to power, in the year 2014 price of petrol per litre was Rs 71 and Diesel per litre was Rs 53. The cost of LPG cylinder was Rs 414. But today the cost of LPG cylinder is above Rs.1000. It is Rs 1200 per cylinder. The price of petrol has gone above Rs.100 per litre. The price of diesel per litre is about to touch Rs 100. The two-wheelers are used by people belonging to the lower strata,

Aam Aadmi, which is the Hindi word I learnt from here. If they want to go to work they may need atleast one to three litres of petrol for their two-wheelers everyday. They have to spend Rs 300 per day for petrol if they want to go to work. This comes to Rs 15000 per month. During Covid, this government reduced the salary paid to Hon MPs. Private companies will go beyond this. I don't say what you did was wrong. We accepted happily. But do you know how many private companies reduced the salaries of their employees by 50 per cent. Many of them have lost their jobs even. If a person earns Rs 30000 per month. He has to go to work. If he has to go to work he has to spend Rs 15000 for putting fuel to his two-wheeler. If he has to spend more than Rs 1000 for LPG cylinder, how his family can survive. Prices of essential commodities and food items have gone up as well. In 2014 palm oil was sold for Rs 68 per litre. But now it is sold at Rs. 160. Vanaspathi oil was sold for Rs 70 in the year 2014 but now it is being sold at Rs 170. Groundnut oil was sold for RS 116 in the year 2014 and now it is being sold at Rs 188 per litre. Cooking oil being used by every house hold has also seen the price rise. Hon Member Shri Nishikant Dubey while speaking said that the prices of onion and tomato have come down. Can every family prepare chutney and eat all three times a day. The prices have gone up. A mother in a family is unable to provide food to her children. Her husband has to go to work. He has to spend much on fuel. LPG cylinder cost should have to be borne by the family. Believing your words many have given up their subsidy for LPG. LPG subsidy which has to be credited into the bank accounts of beneficiaries are not reaching them. This is the truth and ground reality. Asim Premji University has prepared a Report. This Report says that, in an unprecedented manner, 23 Crore Indians are pushed below the poverty line. As much as 3.2 Crore Indians of middle class are being forced to become poor. They have been pushed from middle class to poverty. This is the sorry state of affairs in our country. But all is not bleak and blank. Because in India, an Industrialist has become the fourth richest in the world. He even moved ahead of Bill Gates. The corporates are being given tax rebates. I am not against industrial growth. This Government which shows reluctance to help the people of the lower strata, is continuously helping the corporate companies of this country. This Government is run so as to help and encourage these corporate giants. After 45 years of Independence, we witnessed such a pathetic unemployment condition in our country. The unemployment situation has further

worsened in last October 2021 leaving 5 million persons jobless. If this is the situation just think of the future of our youth. This is a big question mark threatening us like anything. Youth of this country is asking us about their uncertain future. We should not forget this. Without having this duty-bound commitment we cannot run this Government only with political motif or to look for winning or loosing or to have grudges against others. We should understand that this may not bring good to us. We have created so many memorials. The Statue of unity is one. We are boasting our achievements of creating such memorials like statue of unity. But in the name of language, caste and religion, you are trying to divide the people of this country. How this can be justified? You should ponder over this. During UPA Government's rule when the prices of petrol and LPG cylinders were raised, Shri Narendra Modi strongly opposed those moves of the then Government. I quote. "Massive hike in petrol prices is a prime example of failure of Congress led UPA Government. Unquote.This will put burden on hundreds of Crores on Gujarat." He stated this when he was the Hon Chief Minister of Gujarat. Today, you are in a position where you can reduce price of petrol. The prices of petrol and diesel have come down in the international market. It is a matter of great concern that this reduction in international crude oil prices have not reached the common man of this country.

If you see GST, it has been increased for the essential items used by the common and ordinary people. Pre-packed and labeled meat, eggs, frozen fish, curd, paneer, honey, dried leguminous vegetables, dried makhana, wheat, cereal flours, jaggery, compressed air, etc. which are being used by common and ordinary people are at 5 per cent GST. On one side the prices are rising up. On the other side there is unemployment besides no way to increase one's income. If you continue to increase the prices of essential commodities everyday and if you do not take any action for reducing the prices, this Government should answer as to how the people can survive with all these difficulties. Shri Dubey while speaking here said that RBI is not ready to give loans to the States ruled by opposition or non-BJP parties. My appeal to you is that this Union Government should immediately release the GST compensation that is due to the non-BJP ruled States or Opposition ruled States of this country. You need not give any other loan to us. If you give GST compensation that is due to us, we can create our State a prosperous one on our own. Thank you.

माननीय सभापति : डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी ।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात): सभापति महोदय, प्रणाम ।

मैं अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Excuse me; एक मिनट रुकिए ।

निशिकांत जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इनका नाम बोला गया था ।

... (व्यवधान)

*m13 डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ।... (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा कि ऑपोजीशन-रूल्ड स्टेट्स को आर.बी.आई. पैसे नहीं देना चाहती है, बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि फ्रीबिज़ के कारण आपकी इकोनॉमी जो डाउन है, आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट का जो एस्केलेशन कर दिया है, इसके कारण आर.बी.आई. आपको पैसे देने को तैयार नहीं है ।... (व्यवधान) आप अच्छे से इकोनॉमी चलाओ, सभी आपको पैसे देंगे ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम दस्तीदार जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी ।

... (व्यवधान) ...*

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : सभापति महोदय, प्रणाम । मैं अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि देर आयद, पर दुरुस्त आयद । महँगाई एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसने आज भारतवर्ष की हर जनता और हम सभी को बहुत चिंतित करके रखा है । आज महँगाई जिस जगह पर है, उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । महँगाई पर चर्चा करने के लिए और मुझे इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय

की शुक्रगुज़ार हूँ । आज के दिन आम जनता पर क्या गुज़र रही है, यह सरकार को समझना चाहिए । मैं सहमत थी, आज वह मंत्री महोदया यहाँ नहीं है । जब आप सत्ता में नहीं थे, तब मंत्री महोदया ने एलपीजी सिलिंडर लेकर बहुत शोर-शराबा किया, यहाँ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ । अभी मैं जानना चाहती हूँ कि उस मंत्री महोदया की क्या राय है? अभी भी गाँवों में लाखों औरतें चूल्हा फूँकते हुए दिखती हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में उनको जो सिलिंडर मिला था, अभी ईंधन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लाखों सिलिंडर खाली पड़े हुए हैं । अभी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईंधन में आग लगी हुई है ।

कभी-कभी मेरे मन में विचार आता है कि क्या यह सरकार हमें कच्चा खाने की आदत दिलाना चाहती है । कच्चा खाने का आप कोई दूसरा मतलब नहीं समझें कि इसका कोई दूसरा मतलब है । मैं कहती हूँ कि आज लोग सब्जी कच्ची खा जाते हैं, क्योंकि उनको ईंधन नहीं मिलता है । मैं कच्चा खाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलिंडर का चंद महीनों में चार बार दाम बढ़ा है । तीन-चार साल पहले इसका भाव 600 रुपये था, लेकिन आज इसका भाव 1100 रुपये हो गया । आप समझिए कि जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, वे कैसे 1100 रुपये देकर सिलिंडर खरीदेंगे । इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए । आप लोग हमें कच्चा खाने की आदत डलवाना चाहते हैं, इसे आप बंद कीजिए । आप एलपीजी सिलिंडर का भाव जरूर कम कीजिए, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है । इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए ।

वह मंत्री महोदया कितना शोर-शराबा करके सत्ता में आ गई, लेकिन अब आज जनता को भूल गई । वह कहाँ है? वह सिलिंडर लेकर जुलुस निकालती थी, महँगाई की बात करती थी, लेकिन आज यहाँ नहीं है । मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ । इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो जी.एस.टी. लगा है, टैक्स लगा है, इससे पेट्रोल व डीजल का भाव बढ़ने से सब के ऊपर असर आता है । सब चीजों का भाव बढ़ जाता है ।

We have to agree that increase in the prices of petrol and diesel, which are skyrocketing at the moment, is largely because of the tax that the Central Government is levying on them. West Bengal is amongst the first few States which took an immediate step for the benefit of the common man, through the hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, and announced reduction of tax by Rs.1 per litre on petrol and diesel. The lion's share of taxes on fuel comes to the Central Government. The Centre imposes both flat and ad valorem taxes on fuel. The Centre has been levying Excise Duty and also cess on fuel. So, the Centre took tax and cess of Rs 32.90 per litre on petrol and Rs.31.80 per litre on

diesel. In 2020, the Excise Duty on petrol was hiked from Rs 19.98 per litre to Rs 32.9 per litre. So, indirectly, this is increasing the cost of all edible oils, all kinds of consumables, and everything which is required for daily life.

In spite of the fact that the international oil prices have plunged to a multiyear low due to the pandemic in 2020 and in spite of the fact that the price of crude oil per barrel was so low, the tax was being increased by the Central Government which is not desirable for the good of the economy. The economy has been totally shattered.

The excise revenue from petrol and diesel has increased by over 94 per cent from about Rs. 1720 billion to Rs. 3343 billion from 2014 to 2020. The Government's collection from levy of excise duty on petroleum products has risen to 33 per cent in the first six months of this current fiscal year. The central taxes on petrol and diesel rose by over 307 per cent in the last six years, allowing the Union Government to mop up a sum of Rs. 2.94 lakh crore through taxes on fuel between April, 2020 and January, 2021. In the last three years, under the Central Excise Taxes, a whopping Rs. 14 lakh crore has been collected by the Centre and the States combined. However, the Centre has changed the way these taxes are shared with the States and the States are not getting their share. The Central Government is getting a larger part of it and therefore, the States find themselves fiscally cornered. The States are not getting the share of this tax structure. This is against the federal structure. The Finance Commission says that the States should get as much as 41 per cent of their excise share but due to the cess levied by the Centre, the Centre gets a bigger share of taxes leaving the States with little option.

If we look at the Wholesale Price Index, we depend a lot on agriculture. The backbone of agriculture is fertiliser and urea. In the fiscal year 2013-14, the Wholesale Price Index of urea was 104.7. In the last fiscal year, the Wholesale Price Index of urea was 110.1. You are not looking at it properly to help the farmers. Through the farm laws that had been brought and had been withdrawn later on, we know that you are not pro-farmers. But unless the farmers are helped and agriculture is helped, the country and the people will suffer. In 2013-14, the Wholesale Price Index of cereals was 126.6 and today, it is 160.7. The Wholesale Price Index of vegetables -- like the one that I just ate -- was 163.6. But today, it is 204.5. For milk, it was 116 and today, it is 156.9. Milk is consumed by little

children and elderly for their well-being. Now, the children and elderly cannot even thrive because milk is increasing so much in its cost. People cannot afford it. … (*Interruptions*)

Now, I come to the essential medicines. The essential medicines are life-saving. They are becoming dearer every day. Tax has also been put on the equipment used by specially-abled persons. The Government should be ashamed that it is not giving chance to specially-abled persons to take care of themselves. … (*Interruptions*)

My hon. Friend, I was not just talking about pencils and rubbers. That is for the better education of young people. You are not taking care of the infants by increasing the price of milk. You are not taking care of the children in their education by increasing the price of pencils and rubbers.

You are not even taking care of the economy at all. You should put more attention on the economic condition of the country rather than putting advertisements or अपना ढोल पीटना The retail inflation has remained at seven per cent which is above the Reserve Bank of India's tolerance level of six per cent. A lot of people in the country take *moori and chudva.* मुरमुरा कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, दही कहते हैं, पैकेज्ड फूड तो भी सही, गरीब लोग उतना नहीं लेते हैं, लेकिन मुरमुरा जिसे कहते हैं, चूड़ा जिसे कहते हैं । मरीज अगर हॉस्पिटल गया तो बेड्स के ऊपर जीएसटी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी इस देश का ऐसा हाल हुआ है कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया । Today, the price of cooking oil stands at an average of Rs. 180 per litre whereas in 2014, it was only Rs. 105. आप बोल रहे थे, यूपीए के समय को मैं याद करना चाहती हूं, मैं बहुत इज्जत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं हैं, सुषमा स्वराज जी लीडर थीं । उन्होंने 2004 में कहा था जब हम छोड़ कर गए थे तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर था और चंद महीनों में यूपीए ने आकर उसे 67 रुपये बना दिया, तब उन्होंने खड़े होकर यहां अपनी बात रखी थी । अभी आप पेट्रोल के बारे में सोचिए, 100 रुपये से भी ज्यादा 110 रुपये के बराबर हो गया है, गाड़ी नहीं चलती है । … (व्यवधान) महंगाई इस जगह पर पहुंच गई है कि आम जनता का जीना हराम हो गया है । यहां बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, सभी ठीक ठाक बात करेंगे, मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगी कि इतना टैक्स मत लगाइए कि सिर्फ आप ही को मुनाफा हो और गरीब मरता रहे । गरीब की तरफ थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कम कीजिए ताकि वह भी जी सके । नमस्कार, थैंक्यू ।

माननीय सभापति : श्री कौशलेन्द्र कुमार जी ।

... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आज महंगाई के मुद्दे पर ... (व्यवधान)

*m15 डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, सुषमा जी जिंदा नहीं हैं । सुषमा जी वर्ष 2004 में सदस्य नहीं थीं । वह 2009 में सदस्य बनीं । सुषमा जी यहां नहीं हैं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कौशलेन्द्र कुमार जी । सिर्फ कौशलेन्द्र कुमार जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा ।

*... (Interruptions) ...**

श्री कौशलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आपने मुझे महंगाई पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । आज महंगाई पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे । जब-जब सरकार बनती है या चुनाव आता है तो उसके पहले भी महंगाई पर चर्चा होती है । आज जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से लगातार उनका प्रयास है चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको खुशहाल करें, इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं । आज उसी की देन है कि जब हम गांव में जाते हैं तो सड़क है, बिजली मिल रही है, पीने का पानी नल से मिल रहा है । यह इंतजाम अभी यूपीए के कुछ साथी बता रहे थे, उस दिन को भी याद रखना चाहिए । आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं और 50 साल आपने शासन किया है । उस समय देश में गरीबों की संख्या कितनी थी और आज आप खाता दिखा रहे हैं । गांव में पहले मिट्टी का मकान था । गांवों में चले जाएं, अब मिट्टी के मकान ही नहीं हैं । मैं देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं ।

महोदय, जब हम गांवों में रहते हैं, घूमते हैं, गांवों में खुशहाली है । कोविड में लगातार माननीय प्रधान मंत्री जी बोलते रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है । हम भी उनका साथ दे रहे थे । कोविड में उन्होंने जो इंतजाम किए, जो व्यवस्था की, उसमें गरीब, जो बाहर रह रहे थे, उनको गांवों तक पहुंचाया और मुफ्त में लगभग 180 करोड़ गरीबों को भोजन दिया और यह आज तक भी दिया जा रहा है । हमें यह भी सोचना चाहिए ।

महोदय, आज अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए हम चिल्ला रहे हैं कि राशन, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल में सब्सिडी नहीं दी जा रही है । यह भी देखना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि देश के गरीब, चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में घूमेंगे । आज देश में गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है, कश्मीर जा रहा है । यह है मोदी जी का कमाल ।

महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई । उस समय हम एयर इंडिया से पटना जाते थे तो 32,000 रुपये टिकट थी और आज हवाई जहाज से 4,000-5,000 रुपये में पटना चले जाते हैं । महंगाई कहां बढ़ी? अगर महंगाई कुछ चीजों पर बढ़ी है तो लगातार सरकार का प्रयास भी है कि गांवों में गरीब, किसान की स्थिति को मजबूत किया जाए । उनकी पहल है कि किसान की आमदनी दुगुनी हो ।

महोदय, हम वर्ष 2009 में चुनकर आए थे, उस समय यूपीए सरकार थी । यूपीए सरकार में लगातार हम लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते थे, चाहे कोयला घोटाला हो, खेल घोटाला हो या कोई और हो । जब से माननीय मोदी जी आए हैं, विपक्ष से कोई बता दे कि क्या किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा उठा है? आज पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त है । जहां एनडीए सरकार है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है ।

महोदय, आज महंगाई पर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ गए हैं । तेल का दाम बढ़ गया है तो राज्य सरकारों को बिहार की तरफ देखना चाहिए, बिहार के मुख्य मंत्री जी ने अकाल को देखते हुए अभी डीजल पर 60 रुपये सब्सिडी दी है ।

महोदय, हर चीज भारत सरकार करती है और राज्य सरकार भी करती है । आज महंगाई पर चर्चा हो रही है । इसमें यह भी देखना चाहिए कि देश के हालात सुधर रहे हैं या नहीं । देश में बिजली मिल रही है, सड़कें बन रही हैं, गांवों में गली-नाली पक्की हो रही हैं, गांवों के किसानों के काम हो रहे हैं । इन चीजों पर भी ध्यान देने की आज जरूरत है ।

मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि महंगाई पर चर्चा हो रही है, इसे माननीय प्रधान मंत्री जी खुद सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विपक्ष की बात को सुनकर चीजों पर ध्यान दें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m18 श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय सभापति जी, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं अपनी बात प्रसिद्ध वाक्य से शुरू करना चाहूंगी –'सखी, सईंया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है ।'

महोदय, महंगाई की मार से आज वही व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है । खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सबसे ज्यादा महंगाई की मार को झेल रहे हैं । सरकार का दावा था कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी से तिगुनी हो गई है ।

इसी महंगाई में आपने बच्चों की पेंसिल, रबर, शार्पनर और अन्य जरूरी सुविधाओं और चीजों पर जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है । इस कारण एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ रही है । उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर दूर बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि वे अपने परिवार का ख्याल रख सकें ।

इसी बीच, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है । भारतीय बाजारों में विदेशी निवशकों द्वारा भारी बिकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा एफपीआई निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है । 29 जून, 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड था, जहां एक डॉलर की कीमत 69.03 रुपये हो गई थी । क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है? सरकार के वे कौन-कौन से प्रयास हैं, जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो? मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूंगी ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2021 में 13.11 प्रतिशत से बढ़कर 15.88 प्रतिशत हो गई है । एमपीसी के अनुसार मुद्रास्फीति की उच्च दर बने रहने से मुद्रास्फीति संबंधी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और उसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी । अत: मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी और उपाय किए जाने की आवश्यकता है । अर्थव्यवस्था में आ रहे निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण भारत में सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं । उसके कारण वस्तुओं के आयातकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । मार्च, 2022 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है । उसके कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है । सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ढेर सारे सिलेंडर बांटे और कई सारे दावे किए थे । लेकिन, आज गांव में यह हालत है कि लोग अपने सिलेंडर को भूसे में रख रहे हैं । उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वे सिलेंडर को दोबारा भरवा सकें ।

फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी आज आसमान छू रहे हैं । पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से जनता त्राही-त्राही कर रही है । जनता के हितों का ध्यान न रखकर दोबारा जीएसटी की दरों में सरकार ने वृद्धि की है । इससे महंगाई की आग में और घी डालने का काम किया जा रहा है । आज आम आदमी की थाली से दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूँ, मुरमुरे और अन्य अनाज पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगा दी गई है । एक ओर हमारे देश में नौकरियों की भारी कमी है और दूसरी

ओर आय का कोई अन्य जरिया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस स्थिति में जीएसटी लगाना बहुत दु:खद है । अभी कोविड-19 का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है । दूसरी तरफ, मंकीपॉक्स का वायरस हमारे देश में अपना पैर तेजी से फैला रहा है । सरकार ने अस्पताल और उपचार क्षेत्रों में जीएसटी लगाकर आम आदमी को और परेशान करने का काम किया है । डायलिसिस पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है । पेस मेकर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है । लेंस और आई ट्रीटमेंट पर जीएसटी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है । कैंसर ट्रीटमेंट पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है । इससे लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में और उनकी देखभाल में भारी कमी आएगी ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे बताए हुए बिन्दुओं पर पुन: विचार करें और देश के गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से दबे-कुचले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सभी क्षेत्रों में बढ़ी हुई जीएसटी दर पर पुन: विचार करें तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई-गैस तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए दामों में कमी करें । साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि श्मशान और शव गृह पर जो जीएसटी लगाई है, उसे एकदम खत्म करें । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द ।

*m19 श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, आपने मुझे मूल्य वृद्धि पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, आज मूल्य वृद्धि पर पार्लियामेंट में क्या बात होगी, उसके बाद सरकार क्या रिप्लाई देगी, उसके बारे में देश की जनता सोच रही है । अभी यहां पर कुछ लोगों ने बताया है कि वे हमारे अच्छे मित्र हैं । वे मेरे साथ पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अभी भी हैं । मेरे साथ के साथियों ने भी बताया है । जब ये लोग अपने संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे, जो लोग आज पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मूल्य वृद्धि नहीं हैं, जब आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, तब आपको आम आदमी की कुछ न कुछ बात जरूर सुननी पड़ेगी । पूरे देश में मूल्य वृद्धि है । मूल्य वृद्धि की वजह से आम आदमी काफी प्रभावित हुआ है । गरीब और गरीब बनता जा रहा है । ये लोग हाउस में बोल रहे हैं कि कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई है । यह बात ठीक नहीं है ।

महोदय, सरकार की तरफ के एक माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूं । अभी पूरे विश्व में गेहूं का उत्पादन 1 प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन

हमारे देश में काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है । उसी तरह से चावल के बारे में कहा है कि पूरे विश्व में चावल का उत्पादन पाइंट 5 प्रतिशत कम हो गया है, मगर हमारे देश में 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है । जो 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है, उसको तेलंगाना राज्य ने बढ़ाया है । जो 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है, आप लोग उसको तो नहीं खरीद रहे हैं । किसानों से चावल नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी वजह से तेलंगाना के किसान काफी चिंतित हैं । वे काफी दुख में हैं । एक तरफ तो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि भारत में उसका उत्पादन तो 100 प्रतिशत बढ़ गया है । अगर पूरे विश्व में किसी को भोजन देने की कैपेसिटी है, तो केवल भारत के किसानों में है और किसी के पास नहीं है । ऐसे किसानों को प्रोटक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

इसी के साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बोली है । उन्होंने अपोजिशन रूल्ड राज्यों में तेलंगाना के बारे में भी बोला है । ये कहा गया कि हम लोग एफआरबीएम से ज्यादा लोन ले रहे हैं । इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर रिप्लाई देना चाहिए । आज तक तेलंगाना राज्य ने जितना भी लोन लिया है, उससे एसेट्स क्रिएट किए हैं । उससे डैम्स बनाए हैं, पावर प्लांट्स बनाए हैं, हर गांव में पीने का पानी दिया है । उसी तरह से इरिगेशन के लिए एसेट्स क्रिएट किए हैं । जो हमारा गरीब तेलंगाना राज्य था, वहां पीने के लिए पानी नहीं था । इसी हाउस में कम से कम 100 बार सवाल यह आया था कि ऐसा कौन सा राज्य है, जहां पर 100 प्रतिशत पीने का पानी मिलेगा, उसमें नंबर एक पर तेलंगाना राज्य है । हमें सरकार से काफी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं । पूरे देश में सबसे अच्छे गांव कहां हैं, तो 20 में से 19 गांव तेलंगाना राज्य में हैं । तेलंगाना के 10 राज्य अच्छी तरह से डेवलेप हुए हैं । अभी तेलंगाना के बारे में इस तरह से कहा गया है । आज तक हमारे यहां एक रुपये का भी डिफॉल्ट नहीं है । जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, हम लोग उसके अनुसार यह कर रहे हैं ।

महोदय, अभी मूल्य वृद्धि के बारे में बोलना है । पिछले 8 सालों से मुद्रास्फीति काफी अधिक है । कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस काफी बढ़ गया है, फूड प्राइस भी काफी बढ़ गया है, फ्यूल प्राइसेज़ भी काफी बढ़ गए हैं । इन सबके बढ़ने की जवह से गरीब आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है । आज की तारीख में गरीब आदमी काफी दिक्कत में है । उसको क्वोट करने के लिए आप मुझे इतना समय तो नहीं देंगे, लेकिन मैं दो-तीन पाइंट्स के बारे में बोलना चाहता हूं । सिलेंडर का दाम 414 रुपये था, आज की तारीख में एक सिलेंडर का दाम 1,053 रुपये हो गया है । आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है । डीजल-पेट्रोल के बढ़े हुए दाम किसानों के ऊपर पड़ रहे हैं । आज के दिन एक एकड़ की खेती पर किसानों को 2,000 रुपये अधिक लग रहे हैं । उसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर, बल्कि जो हैंडलूम्स चलता है, हाथ से जो लोग कपड़े बनाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया गया है । बच्चों की पेंसिल, रबड़, दूध, दही के ऊपर भी जीएसटी

लगाया गया है । अस्पतालों में जो मरीज एडमिट होते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है, उस पर टैक्स लगाया गया है । कम से कम इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए और इसको कम करना चाहिए । मैं इसके साथ ही साथ एक-दो बातें जरूर बोलना चाहता हूं । आपने अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के बारे में बताया है । मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन 56 लाख करोड़ रुपये का था और आज की तारीख में वह लोन 100 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 156 लाख करोड़ रुपये हो गया है, आपने देश में कौन सी एसेट्स बनाई है, देश में कौन सा डैम बनाया है? आपने एसेट्स नहीं बनाई है, बल्कि आपने एसेट्स को सेल किया है । आप पूरे देश की एसेट्स को सेल कर रहे हैं ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात को समाप्त कीजिए । आप कंक्लूड कीजिए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री नामा नागेश्वर राव : मैं इसी के साथ-साथ यह बोलना चाहता हूँ कि इस देश में प्राइस राइस है । प्राइस राइस को कम करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर रहती है ।... (व्यवधान) हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं कि यह डिबेट अच्छी हुई है । पार्लियामेंट में प्राइस राइस पर बात हुई है और अगर गवर्नमेंट प्राइस राइस को कम करेगी तो हम भी उसके लिए ताली बजा देंगे ।... (व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, hon. Chairperson ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please take your seat.

... (*Interruptions*)

***m20 SHRI PINAKI MISRA: Hon. Minister is here. She will give us a spirited reply. Why do you need to give such a spirited reply? ... (*Interruptions*)**

Hon. Chairperson, thank you very much for permitting me to participate in this very important discussion today under Rule 193 on price rise. We have all been very keen for a very long time that we discuss this in the House, and we hear from the hon. Finance Minister what the reasons are. Many reasons have already been given for it. But what are her plans or how does she propose going forward to ensure that the two major lynchpins of this price rise, which is food inflation as well as fuel inflation are dealt with. These are trying times, and I quite understand the Finance Minister's predicament. She has got a hard job on her

hands. The conditions around the world make it very difficult for any Finance Minister today to deal with the current situation.

But I think, some amount of serious introspection is also required as to whether the course that we have followed over the past four or five years, has borne fruit or not. I have had the occasion to say this earlier in my role as a Member of the Standing Committee on Finance. The demonetisation issue was raised by one of my colleagues. This continues to remain a bugbear. The Government has to seriously, seriously introspect that if Rs. 15,90,000 odd crore was the cash in circulation in 2016, and the idea was to take India to a cashless economy to make into a digital economy, how is it that in 2022 , the cash in circulation today is Rs. 30 lakh crore? It has almost doubled.

Therefore, are there some seminal mistakes being made? I understand that the Governor, RBI will immediately tell us that 'a part of it is because of COVID; there were massive withdrawals at that point.' But it still does not mean that people wanted to hold cash etc., etc. These do not really touch the central nerve. There are mountains of cash being found. I am sorry, from all shades of political sides, there are mountains of cash that we see on television. One in UP was Rs. 140 odd crore; one was somewhere else amounting to Rs. 50 odd crore. I mean, there are mountains of cash which is being hoarded and which is being generated, and which is obviously escaping the tax system.

Why is it continuing to escape the tax system, is something that we need to seriously introspect because unless in this country, you expand the tax base in a big way, things will not improve much. I know, the Finance Minister has told us that it has gone up enormously -- nine crore people now paying tax. But how many of them are paying how much tax, is the point. By merely becoming an assessee and by merely filing a tax return, does not make it a productive tax return.

Mr. Nishikant Dubey trotted out a familiar argument which everybody from the Government Benches trots out that we are victim today of the oil bonds that the UPA Government floated and these fuel prices are a result of that and, therefore, we have to keep increasing the fuel prices. I do not know if the actual figures are at your knowledge because if they are at your knowledge, a man of

your erudition and your objectivity would not raise this. Let me give you some actual figures. The actual figures are that from 2014 to 2022, as Mr. Manish Tewari said, Rs. 27,27,000 crore has been generated by way of oil revenues. Mr. Dubey, you would be astonished to know that both, interest and principal, taken together, between 2014 and 2022, which has been repaid by way of oil bonds, is only Rs. 93,600 crore. So, if we take Rs. 27,00,000 crore and Rs. 93,000 crore, the total payment made towards oil bonds from the revenue collected is 3.4 per cent. Therefore, please, do not keep telling us that oil prices are going up because we have to service oil bonds. That is not an accurate description.

The fact of the matter is that oil prices are going up because you have to balance your budget. I can understand that it is very hard job for the Finance Minister to balance the budget. I can understand that there is a massive amount that is going out towards your MGNREGA bills and towards your free food that you are giving out to the poor. There is no question as they are laudable objectives and any Government would be called upon to do it. But it calls for a more prudent economics rather than what I have always said and pardon my saying so, Madam Finance Minister, that it is a lazy taxation. You, basically, are engaging, what is ranked in, lazy taxation. This is something that can easily be plucked; it is a low hanging fruit, let us keeping plucking it; and let us keep torturing. The youth and women of this country are in a serious dire strait.

अभी मनीष जी ने कहा कि सुषमा स्वराज जी ने यहां खड़े होकर बोला था कि गृहणी के आंसू बहते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन आज गृहणी के सिर्फ आंसू नहीं बह रहे हैं, बल्कि खून के आंसू बह रहे हैं । युवक लोगों के भी आज खून के आंसू बह रहे हैं, जब वे रोज सुबह जाकर पेट्रोल पम्प पर देखते हैं, I mean, 39 times, the price of petrol has increased in 2021-22 and before that, the price of petrol has been increased 76 times between 2020-21. Every morning, you went there, it was 50 paise or 75 paise or one rupee up. These young boys today, who work as courier boys or delivery boys, for them it is their lifeline. They cannot do anything without those motorcycles. Everyday, they go back with less money in their pockets because you continue to raise fuel prices rampantly because you have no other way of garnering your revenue.

Therefore, Madam Finance Minister, I urge you once again that please do not heed the advice of bureaucrats who are giving you, with great respect, lazy advice

for your revenue generation. I will give you one example straightaway. There is a big *brouhaha* in the country that steel prices are going up and, therefore, put an export duty on iron ore. There is no difficulty. You put an export duty on finished steel. You put an export duty on over 58 iron ore which is used in steel production. But, why have you put an export duty on under 58 iron ore when not a gram of under 58 grade ore is sold in this country or will ever be sold in this country? Nobody uses it. A State like Odisha, today, is liable to lose Rs. 15000 crore this year apart from the foreign exchange, Madam, Finance Minister, that the Government of India will lose. We will lose by way of our revenues, Rs. 15,000 crore. We have been crying from pillar to post that this is a needless cess. It is an environmental hazard. It is because you cannot stop mining under 58 grade iron ore. If you mine over 58 grade iron ore, you would also mine under 58. That is piling up needlessly. It can easily be exported but you put such a countervailing duty on it that it becomes uneconomical. But nobody is willing to listen that there is no rationale to this. So, there must be some rationality and for that, I believe, the political guidance is the only way going forward. This cannot be in the hands of bureaucrats. With great respect, I would say, they have a tunnel vision which they will never get out of in this country. That is a fact.

Hon. Chairperson Sir, there is one other astounding fact which needs to be brought to the knowledge of this House. Is this House aware that in 2019, about 1,44,017 Indians gave up their citizenship? This has been told to the Lok Sabha on 19th July. During COVID pandemic, this number came down to 85,256. But now, in 2021, the number of people, who are giving up Indian citizenship and taking up citizenships of Saint Kitts, Belize, Portugal and the other countries around the world, is 1,63,370. It is all very well for us to say 'good riddance'.

आप बोल सकते हैं कि ठीक है कि तुम्हें भारतीय सिटीजनशिप नहीं चाहिए तो निकल जाइए । But the fact of the matter is, these are all high-net-worth individuals who are wealth creators.

Let us not kick them in the face and say "Get out, we do not need you." Let us ask them that what their problem is, and why they are giving up Indian citizenship and taking up citizenship of tax havens abroad. … (*Interruptions*) I am sorry, this is all we need to reflect upon. This is a matter for collective reflection in this House. It is because after all, the Indian Passport is a matter of great pride

for all of us. So, if people are giving up the Indian Passport, Madam Finance Minister, you have to look within your Ministry whether the CBDT, the Enforcement Directorate, the CBI, or all these agencies together are making the lives so difficult today for the high-net-worth individuals in this country. You are not making it easy for them to be happily tax-compliant. You should tax them at such rates and in such a manner that they will be proud and happy tax payers. Today, they are not happy tax payers which is why they are running away from this country. This is number one. … (*Interruptions*)

Two, give them such an atmosphere and an environment in this country. The hon. Prime Minister has repeatedly said that he respects wealth creators and wealth generators. So, give them a feeling that if they are wealth creators or wealth generators, they are not sinners and that they will not be punished. … (*Interruptions*) If we all reflect on this and our policies are in consonance with some progressive thinking, I believe that these are issues that can be easily resolved. It is a large country. Despite the Ukraine-Russia war, I think, we have enormous internal resources, and this 130 crore population of this country is capable of collectively generating massive wealth, and becoming great wealth creators. But for that, we have to unshackle what are known as the animal spirits of this country and its people.

Madam Finance Minister, I appeal to you to kindly pay heed to what I have said in right earnest, and I say this in the best spirit of bi-partisanship. Thank you very much.

***m21 SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me a chance to participate in the discussion under Rule 193 relating to price rise. I appreciate all the points made by my several colleagues because it is a very important issue. Everybody has endlessly and repeatedly talked about Sushma*ji.* सुषमा जी, यहां खड़ी होती थीं, जब महंगाई पर चर्चा करते थे और हम वहां बैठते थे । मुझे अभी भी उनका उस समय का एक-एक शब्द याद है । वह यहां पर महंगाई पर टीका-टिप्पणी करती थीं, हम बहुत शांति से सुनते थे, क्योंकि हमको लगता था कि वह कुछ फीडबैक दें । हमेशा उनके भाषण में कुछ सुझाव होते थे । हम उनके सुझाव सुनते थे और उन पर अमल करने की कोशिश हमारी यूपीए की**

सरकार करती थी । आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे तो उन्होंने बड़े-बड़े नंबर्स और 60 सालों का बहुत अच्छा हिस्ट्री लैक्चर सुनाया । उन्होंने बहुत सारी बातें 60 सालों की बोलीं । उनको भी वहां बैठे आठ साल हो गए हैं । मैंने पिछली बार एक बार बोला था, मैं फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन इनका 60 साल का हिस्ट्री का लैक्चर इतना लम्बा चला, मुझे सिर्फ उनको एक बार याद दिलाना है कि आठ साल बहुत होते हैं । जब नई बहू भी शादी होकर घर आती है तो आठ साल के बाद शादी में कोई नहीं सुनता कि यह लिगेसी इश्यूज हैं, मेरी सास के टाइम से चल रहा है । आठ साल में वह बहू उस घर की फुल-फ्लैप्ड मैम्बर हो जाती है । यही महंगाई की प्रॉब्लम है । मुझे सुषमा जी के शब्द याद हैं, जो आज इनके भाषण पर पूरे लागू होते हैं, "फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता है, आम आदमी केवल वह भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है ।"

16.00 hrs

मेरी दोस्त और सहकर्मी श्रीमती कनिमोझी जी ने एक बच्चे के बारे में कहा । वह बात सही है । आज कीर्ति दुबे, जो छः साल की है, उसने जो खत लिखा है, के बारे में सारे पेपरों में छपा है । उसने सुन्दर अक्षरों में खत लिखा है । मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक छः साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है । इनका ही नारा है- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ।' भारत की यह बेटी पेंसिल के लिए खत लिख रही है । माननीय अटल जी जो 'सर्व शिक्षा अभियान' प्रोग्राम लाये थे, वह एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था । जब हमारी सरकार थी, तब हमने भी किया था । इन्होंने किन-किन चीजों पर जीएसटी लगाया है, मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूँ । हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, उसे पढ़कर मैं जीएसटी के बारे में बताऊँगी । जब हम बच्चे थे, तो हमें सिखाया गया था- "दत्ता-दत्ता, आप जानते होंगे दत्ता भगवान, दत्ता-दत्ता दत्ता ची गाय, मतलब दत्ता की गाय । गाय च दूध, मतलब गाय का दूध, दूधाची साय, दूध पर जो साय आती है वह, सायीचा दही, मतलब उस साय का दही बनता है, दहीचा ताक, मतलब दही का ताक बनता है, ताकाचा लोणी, यानी बटर, लोणया चा तूप, मतलब घी । इसलिए दत्ता-दत्ता, दत्ताची गाय, गायचा दूध, दूधाची साय, सायीचा दही, दहीचा ताक, ताकचा लोणी, लोणया चा तूप" ।

16.02 hrs **(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)**

ये सब कविताएं सुन-सुनकर हम बड़े हुए । इस पर दत्ता गुरु भगवान और गाय, इन दोनों को छोड़कर आपने सब पर जीएसटी लगा दिया ।... (व्यवधान) भगवान पर अभी तक नहीं लगाया है । ... (व्यवधान) आप सोचिए, paneer, curd, lassi, jaggery, sugar, natural puffed rice, murmura, हमारे कोलकाता के दोस्त कब से इसके बारे में बोल रहे

थे, rice, wheat, tender coconut, rice flower, etc. के बारे में बोल रहे थे । श्री निशिकांत जी गेहूँ के बारे में बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, मुझे उनकी बात सुनकर अच्छा लगा । वे कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, यह अच्छी बात है । जब देश का प्रधानमंत्री शोषित, पीड़ित, वंचित को खाना देता है, तो उसकी दुआएं लेकर जाता है । वह उसका हिसाब नहीं मांगता है । सरकार माई-बाप होती है । जब माँ रोज अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो वे उसका आभार नहीं मानते, वह उसका हक है । माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चे आशीर्वाद समझकर खाना खाते हैं । इस देश में इसको अन्नपूर्णा कहते हैं । श्री निशिकांत जी कह रहे थे कि क्या आप आभार नहीं मानेंगे? क्या इस देश का यह हाल हो गया है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले कि आपका आभार है, आपने मुझे दो टाइम का खाना दिया । क्या यह आपकी सोच है? आप श्रीमती सुषमा जी का पूरा डायलॉग भूल गए?

मैं जीएसटी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि जब इनका जवाब आएगा तो कहेंगे कि जीएसटी काउंसिल ने किया, इसे हर स्टेट के मंत्री ने किया है । मैं ऑन-रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ और खत को टेबल भी कर सकती हूँ कि जब महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इन्होंने नहीं तोड़ी थी, वह बहुत अच्छे से चल रही थी, तो तब की महा विकास अघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन-रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए । जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था । क्या ये कभी वोटिंग कराते हैं? बहुत सारी चीजें हैं । मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा था कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, या नहीं हैं, वह ऑन-रिकॉर्ड हाँ या न में जवाब दें । सारी चीजें, जो जीएसटी काउंसिल में पास होती हैं, क्या वे यूनैनिमस्ली पास होती हैं? यदि नहीं होती हैं, तो किस राज्य ने विरोध किया, यह बताइए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए । यह साफ हो जाए क्योंकि हम सुन-सुनकर थक गए हैं कि जीएसटी काउंसिल ने किया । इनको तो अच्छा मौका मिल गया क्योंकि मेजॉरिटी इनकी है, एक बहाना हो गया ।

डी-मॉनिटाइजेशन के बारे में बहुत-से लोगों ने कहा, मैं इनको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहती हूँ । श्री निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल के शासनकाल में यह पॉलिसी गलत हुई, ठीक है हमसे बहुत-सी गलतियाँ हुई होंगी, इसीलिए इधर बैठे हैं, नहीं तो उधर बैठे होते । जो काम करता है, वह गलतियाँ भी करता है, कोई बात नहीं । गलती तो हो गई । डी-मॉनिटाइजेशन की बात हो रही थी, मैं पहले यह नहीं बोलने वाली थी, लेकिन इस पर सिर्फ एक टिप्पणी कर रही हूँ । बांग्लादेश, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला । Bangladesh today is a an export remittance and agriculture driven economy, and we were doing well together. डी-मॉनिटाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ?

India grew at 3.7 per cent and Bangladesh grew at 8.2 per cent. The only reason was demonetisation. इससे क्या पाया? मैं दोहराना नहीं चाहती हूं, जो मेरे पहले के वक्ताओं ने बोला है, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है । You were absolutely right when you talked about it.

Even I want to ask the hon. Finance Minister how much currency is in circulation, the CiC. He quoted a lot of numbers. I am not a finance expert nor am I an economist, but I know this much little about finance that probably printing the money is the right thing when you need it because you want to raise demand. So, you need to bring in the cash. I appreciate that, but everybody knows that whenever you print extra notes, it leads to inflation. It is a very common economic knowledge. You do not need to be very smart for that. In that case, when you are looking at reducing moneys, why did you print so many notes? What is the exact amount of currency in circulation? You are at one level.

You keep telling people to go to banks. I want to bring this to your knowledge very quickly that you are encouraging the people to go to banks, which is a welcome thing. We all have worked very hard to make sure that everybody in our constituencies go to the bank. सर, आपको पता है कि कितना खर्चा होता है? अगर आप एटीएम से विद्ड्रॉल करें, many banks allow up to five free transactions and every time thereafter, कुछ बैंक्स में पांचवे ट्रांजेक्शन के बाद आप पैसा निकालने जाएंगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा । खुद के पैसे निकालने के लिए पैसा देना होगा? वाइट का पैसा, जो हम सरकार पर विश्वास करके बैंक्स में रख रहे हैं, उस खुद के पैसे को निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है । There is a debit card annual fee also. अगर किसी बेचारे का कार्ड कहीं गुम हो गया, तो उसे नया कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे । बैंक स्टेटमेंट, जो हमारा हक है, अगर आपको उसका प्रिंट चाहिए, तो 50 या 100 रुपए देने होंगे । There are charges for money transfer through RTGS and NEFT, service charges on basic bank transactions and cash withdrawal from banks and cheque book charges etc. The rate at which we are going, it is only like गाय का दत्ताच्या प्रॉब्लम, बैंक में भी वही प्रॉब्लम है । Only going to the bank and coming out of the bank is free. For all rest of the things, you have to pay for whatever you do. I really want to ask this Government what their thinking is.

Nishikantji talked extensively about LPG. I just want to ask him one small question. I will not repeat all the points which my colleagues who have spoken earlier raised.

He said that the price was the same, but he forgot to mention that the Government at that time was paying subsidy. The UPA Government never let the LPG cylinder price go above Rs. 300 or Rs. 400. Where is this magic number of Rs. 1,000 he is creating from? Only he knows this. Maybe, we will get a reply for it.

Somebody talked about the falling rupee. I still remember Sushmaji. It had pained me. So, I would like to quote her here: "जैसे-जैसे करेंसी गिरती है, वैसे-वैसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है ।" I just want to ask the hon. Minister two very small questions. I have never got a reply to the question of cess from this Government. This Government charges cess for primary education, secondary education, health, GST compensation and additional cess. So much cess gets collected. There are 12 ways in which you collect cess. Why do you not give this to the poor consumer? I think, they deserve to do it.

I want to raise two very small points about U-turn of the Government. The Government talked about wheat. Literally, these are my last two or three points. I will raise them in short.

HON. CHAIRPERSON: You may raise two points.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I will club them together.

Sir, this Government made a policy. He talked about wheat. What did this Government do about wheat? उन्होंने एक दिन पॉलिसी बनाई कि आप लोग बेच सकते हैं । Within three days, there was a U-turn on that policy and there was a complete ban. Why? On one day, you say that you have enough reserves. When two rupees extra are going into the kitty of the farmer, why did you stop it? I want to ask this Government: will you give me a White Paper on doubling of farmers' income? The other day, the Minister was saying अरे! दोगुना हो गया, दोगुना हो गया । You tell us how it has doubled.

HON. CHAIRPERSON: Supriyaji, please conclude now.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I will raise one last point only.

Sir, they are talking of GST on solar energy. They keep saying that they have a complete kitty of coal, hydrogen and everything together, and it is going to be a green country. By 2030, they want to get rid of petrol.

It is only eight years away. That is the commitment this Government is making, when they are taxing everything related to solar energy at 18 per cent. Is the poor Prime Minister, who has a great vision, confused by his own Ministers? About the policy that one *Mantralaya* is doing and the policy that the other *Mantralaya* is doing, they are misleading the Prime Minister of this country. In his speech, he keeps telling us that he is going to make sure that it is a green country, it is a safe country and it is going to be an affordable country to live in while each of his Department comes with a different story.

I am really concerned because what he says and what happens in reality are two different things. मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आज एक महिला वित्त मंत्री हैं । वे पीड़ा जानती हैं । मंत्री जी बहुत चतुर हैं, इन्होंने सिर्फ प्याज के बारे में कहा है, क्योंकि प्याज के दाम बहुत कम या ज्यादा होते रहते हैं ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद, आप बैठ जाएं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: आंकड़ों से पेट नहीं भरता है । गरीब आदमी को भी पेट भरने के लिए धान की जरूरत होती है । मैं वित्त मंत्री जी से विनती करती हूं ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद, आप बैठ जाएं ।

श्री मारगनी भरत ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: आप एक महिला हैं, आप भी घर चलाती हैं । आपके बीजेपी के एक प्रेजीडेंट ने मुझे कहा था कि आप घर जाइए । मुझे कहा था, आपको नहीं ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Supriya ji, nothing is going on record.

… (Interruptions) …*

***m22 SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I thank the Government for having brought this burning issue of price rise for discussion. If the Government would have done it earlier, the House would not have stalled for these many days and we would have had very good discussions in the House. I would like to add value-added points here. As we all are people's representatives,**

we are very much familiar with the perils faced by the common man due to the rise of prices, like cooking gas, pulses, grains, groceries and so on. Of course, we understand despite the pandemic and the war between Ukraine and Russia having affected and impacted the whole world, it shall be our priority to reduce the impact of inflation in the shortest possible time. We all know that prices of everyday necessaries of common man, like cooking gas, as I said earlier, has shot up in March 2022. It is shaking the monthly budget of the common man. For instance, I would like to quote here that the price of cooking gas has shot up by 25 per cent. How come the common man can survive from this? I would like to read out the analysis of the Department of Economic and Policy Research of RBI. The output losses of first pandemic year are round about Rs. 19.1 lakh crore. In the second pandemic year, it was round about Rs. 17.1 lakh crore. In the year 2022-23, the losses projected are round about Rs. 16.4 lakh crore. If you look at the GDP growth, it came down from 8.9 per cent. It is projected to come down to 7 per cent. The Government needs to focus more on this. As per the given analysis, it will take up till 2034-35 to overcome the losses during Covid and to revive GDP growth. What are the measures Government is taking to curtail the price rise? The Government should focus more on the alternative source of fuel. I would like to highlight some of the figures relating to imports. As per the statistics given, the imports of crude oil are round about USD 170 billion, which is 30 per cent of our total imports. For precious metals like gold and precious gems, it is round about USD 88 billion, which is 15 per cent of our imports. It roughly comes to round about USD 570 billion. The Indian rupee has dropped by 13.5 per cent against the US dollar recently. How can we overcome all this?

I would like to give some fine suggestions here. The Government should focus more on alternative source of fuel. I will give you an example of a hydroelectric power station, like the Three Gorges Dam in China. It produces about 22,500 MW of power. It saves around 110 billion units per day. So, it is producing so much of power for the consumption of whole of China. Likewise, Atal Bihari Ji, former Prime Minister, had conceived and dreamt of interlinking of rivers project. In that, we can create big dams, so that we can generate more power. In fact, our hon. Prime Minister is also planning for alternative source of power as Supriya Sule Ji has rightly mentioned here. By 2030, we are going to curtail burden on

petrol and diesel. How is it going to be possible in a span of eight years? The Government should give more focus on that.

I would like to add one more thing here. Our country is an agrarian country. Since 75 years of Independence, our country is more into the agricultural products. Even today, we are the major importers of palm oil, an edible oil. The duty on the import is much higher. Due to this war crisis, the price of edible oil has skyrocketed. So, the Government needs to promote local edible oils like coconut oil and mustard oil, and also should reduce duties for these edible oils. Even though the Government has given a lot of incentives for the fertilizer and subsidies are being offered by the Government, even then the fertilizer prices have creeped up and have skyrocketed. … (*Interruptions*). Sir, we have more time, at least three more minutes.

HON. CHAIRPERSON: The total time allotted for the discussion is just two hours.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, our number is 22. At least we should be allotted five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, you continue. But please conclude it within the allotted time.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: As per the hon. Speaker's direction, the allotted time is two hours and each party's time is well enunciated here. You continue.

… (*Interruptions*)

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, we need to ensure preventive measures for the farmers to earn more profits. I also suggest here that MSP should also be revised to keep pace with inflation.

The Government should focus and encourage farmers to go in for alternative crops. We have been importing cotton, we have been importing finished goods of cotton, even edible oil. So, instead of that, we need to encourage our farmers to produce more of what we are importing from the other countries.

I would like to give some suggestions here. The unpredictable monsoons have been one of the major factors for inflation. So, to keep it intact, I suggest that steps should be taken to diversify alternative crops, encourage farmers with incentives, rain water harvesting, re-use of organic waste, desalination of water and so on and so forth. The Government should focus more on the Free Trade Agreements for stabilizing export and import. India has seen some notable positives from FTAs in the recent past. As the data shows, there is significant increase in the exports to some countries. So, in that way, as I said earlier, the Government should focus more on alternative fuels; the Government should make the common man live with the limited budget that they have. In the long-term plan, the Government should focus on these issues in the coming couple of years. The Government should take preventive measures to control this.

With these words, I conclude my speech.

***m23 श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, धन्यवाद । आज लंबे समय के बाद यह सदन दोबारा से अपनी गति से चालू हुआ है । सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का और पूरे सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूरा हिन्दुस्तान बहुत आस भरी उम्मीदों के साथ हमें यहाँ भेजता है, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए, उनके निर्णय कराने के लिए ।**

महोदय, आज यहाँ महंगाई पर चर्चा स्थापित की गई है । आदरणीय मनीष तिवारी जी और विपक्ष में बैठी माननीय सांसद कनिमोझी आदि ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने रखी हैं । मुझे लगता है कि महंगाई के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें कई चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ी हैं, मैं अगर शब्द लगा रहा हूँ, अगर बढ़ी हैं तो उनके पीछे कारण क्या है? भारत में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो उसके प्रभाव कैसे हैं? कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कोविड-19 महामारी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, 2.5-3 वर्ष पूरी दुनिया ने संघर्ष किया और उसने क्या प्रभाव छोड़े? रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद पूरी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ेगा और क्या असर आज पड़ रहा है? चीन, जो एक अपनी आन्तरिक व्यवस्था के साथ संघर्ष कर रहा है । वहाँ पर माँग और आपूर्ति का एक असंतुलन हुआ है और जो बाहर से माँग बढ़ी है, उसके कारण दूसरे देशों से निर्यात की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की कमी आने के कारण जो कीमतों में वृद्धि हुई है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ।

मनीष तिवारी जी ने कहा था कि हम 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर ले गए थे और माननीय मोदी जी की सरकार में वे दोबारा से गरीब हो गए हैं । कनिमोझी जी ने कहा कि देश में गरीब बहुत संकट में है, उसे 300 रुपये मजदूरी मिलती है और उसका घर नहीं चलता है । मनीष तिवारी जी ने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान में 92 पूँजीपतियों के पास जितना धन है, उतना धन 55 करोड़ गरीब लोगों के पास है ।

महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, यही सब कारण तो हैं, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री जी इतनी संजीदगी के साथ इस देश को बनाने में लगे हैं । अगर ये सब कारण नहीं रहे होते तो मोदी जी ने यह नारा 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' क्यों दिया होता? सबको समान करना है, गरीब को ऊपर ले जाने का काम करना है, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग की तरफ ले जाना है । यही चुनौतियाँ तो थीं, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामने रखा और इन पर काम करना चालू किया । हम कैसे भूल सकते हैं कि लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया में हर चीज, जिसकी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति असंभव थी । उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को घर-घर भेजने का काम किया और हिन्दुस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों से पूरी दुनिया जूझ रही है । आज कम से कम हम इस स्थिति में हैं कि सामान्य रूप से इस देश को चला पा रहे हैं तो उसके लिए मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ । हमारे लगभग हर वक्ता ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कहा है । मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पैनिक नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में एक साथ 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की छूट का ऐलान एक दिन में क्यों करते? उनको इस बात की चिंता थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं न कहीं हमारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के सामने चुनौती के रूप में आ रहा है, तभी तो उन्होंने एक साथ इसको कम करने का काम किया था । इस पर शुल्क कम करने का काम किया था । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा शासित राज्यों ने भी उस समय 2 से 2.5 रुपये प्रति लीटर तक दाम कम करने का काम किया था । किसने मना किया था कि पश्चिम बंगाल में दाम कम नहीं करना है? किसने कहा था कि राजस्थान में ड्यूटी कम नहीं करनी है? आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान में सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो वह जयपुर के अंदर मिल रहा है । वहाँ सरकार किसकी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूपीए के 10 सालों में, हम 70 साल का हिसाब नहीं माँग रहे हैं, यूपीए के 10 वर्षों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं,

उनके बढ़ने की दर 116 फीसदी थी । शायद ये अतीत का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं या उसको जानबूझकर सदन के सामने नहीं रखना चाहते हैं । हमारी एनडीए सरकार के अभी 7-7.5 वर्ष के कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ने की गति केवल 16 से 17 फीसदी है । कहां 116 परसेंट और कहां 16 से 17 परसेंट, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं । मैं अर्थशास्त्र की व्यक्ति नहीं हूं, मैं इकोनॉस्टि नहीं हूं । लेकिन अपने अध्ययन व आंशिक ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूं कि ये बातें पब्लिक डोमेन में हैं और सब लोगों के सामने हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल और डीजल की इतनी चिंता है और जैसा अभी हमारे विपक्षी दल के कई सदस्यों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आड़ में वित्त मंत्री जी चीजों को छिपाने का काम करती हैं, तो एक बार अच्छे मन से जीएसटी काउंसिल में जाएं और वहां प्रस्ताव रखें कि इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, वे जीएसटी के दायरे में लाने हैं । भारत सरकार जिस तरह जीएसटी का वितरण राज्यों को राज्यवार करती है, उस तरह से जीएसटी से प्राप्त पैसे को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पैसे को पूरे देश में समान दर से वितरित किया जाएगा । यह तय क्यों नहीं कर लेते कि पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करें? जो राज्यवार कालाबाजारी होती है, एक राज्य में कीमत ज्यादा है और दूसरे में कम है, उस कालाबाजारी से भी मुक्ति मिलेगी तथा महंगाई व पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, उससे भी मुक्ति मिलेगी ।

अगर देश के आधे राज्यों में हमारी सरकार है तो आधे में विपक्षी दलों की सरकारें भी हैं । अगर विपक्षी दलों को देशवासियों की इतनी चिंता है तो यह कठिन निर्णय क्यों नहीं करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मुद्रास्फीति की बात हमारे कई साथियों ने की । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम मुद्रास्फीति के बहुत पुराने समय के आंकड़े निकालते हैं और आज माननीय मोदी जी की सरकार में उनका अध्ययन करते हैं तो वर्ष 1973 में प्रधान मंत्री स्व. गांधी जी के समय 16.9 परसेंट मुद्रास्फीति की दर थी, वर्ष 1974 में 28.6 परसेंट थी और वर्ष 1991 में आकर 14 परसेंट थी । माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय जाने वाली थी, उस समय मुद्रास्फीति की दर 11.6 प्रतिशत थी । बाद में प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 में इस देश की कमान संभाली तो वह घटकर 6.67 आ गई । वर्ष 2018-19 में तो 3.9 परसेंट थी । कोविड के समय पूरी दुनिया जब संघर्ष कर रही थी, तब यह दर हमारी बढ़ी है, वह 6.8 परसेंट हुई है । आज की तारीख में आरबीआई का मानना है कि अगर यह 5.5 परसेंट के आस-पास रहती है तो एक आइडियल दर इसको हम मानते हैं, जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है और लगभग उसी के आस-पास यह सरकार इस दर को नियंत्रित करने का काम कर रही है । जो आंशिक महंगाई है,

मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता । मैं यह नहीं कह रहा कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में जब अव्यवस्था होती है, तो कहीं न कहीं इन चीजों का सामना देश को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है । लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार किन चीजों की चिंता कर रही है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

आज स्टील की बात कही । स्टील और प्लास्टिक उद्योग में अगर कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी सरकार ने की है तो वह इस वजह से की है कि महंगा स्टील इस देश में न मिले । स्टील सही दरों पर मिले, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास में जो आवास बन रहा है, उसके लिए सही दाम पर स्टील मिले । उसके कारण ही तो आयात शुल्क में कमी की है । आज पूरा देश देख रहा है कि स्टील की कीमतों में लगातार गिरावट आई है । मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी आने के बाद हम फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे । आज स्टील के जो उत्पाद हैं, उत्पादों के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया गया है, जिससे चीजें बाहर न जाएं । हिन्दुस्तान का माल हिन्दुस्तान में रहे । आयात शुल्क में कमी की है । खाद्य तेलों में चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन का कच्चा तेल और सूर्यमुखी के कच्चे तेल के आयात में शुल्क मुक्त अनुमति प्रदान की है । यह इसलिए की है कि तेलों के दाम न बढ़ें ।

माननीय सभापति महोदय, हम आज उज्ज्वला गैस की बात करते हैं । अगर गैस में लग रहा है कि इसकी दर महंगी है तभी तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 200 रुपये की राज सहायता देने का काम किया है । अगर इसके दाम ठीक होते तो राज सहायता की आवश्यकता नहीं थी । जब प्रधान मंत्री जी को चिंता हुई, तभी तो उन्होंने राज सहायता यहां पर प्रदान की । जब यूपीए-2 में हम लोग यहां बैठते थे, अधीर रंजन जी, आपको याद होगा कि उस समय इस बात के लिए संघर्ष होता था कि सरकार ने घोषणा की कि हम एक साल में 6 से 8 सिलेंडर देंगे । सदन में जद्दोजहद चलती थी कि 6 से 8 नहीं, आप 12 सिलेंडर दीजिए । आखिर अचानक क्या हुआ कि यूपीए-2 में सिलेंडर की संख्या की बात करते थे और आज माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस बैरियर को खत्म किया है । पूरे हिन्दुस्तान में जिसको जितना सिलेंडर लगे, वह उसका उपयोग कर सकता है और इसके साथ 9 करोड़ गरीब महिलाओं के घरों में फ्री में गैस सिलेंडर, कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

महोदय, एक तरफ हम सिलेंडरों की संख्या बताते थे और आज नौ करोड़ महिलाओं को असीमित सिलेंडर मिल सकते हैं । सभापति महोदय, आज सबसे महत्वपूर्ण काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने सैल्फ डिक्लेरेशन का किया है कि जो महिलाएं छूट गई हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन गरीब परिस्थिति की हैं, उनको लगता है कि इन पेपर्स के कारण उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा कनेक्शन सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, प्रधान मंत्री जी ने ऐसी एक करोड़ महिलाओं के

लिए किया कि वे सेल्फ डिक्लेयरेशन के साथ कहें कि मैं गरीब परिस्थिति की हूँ, मुझे इस सहायता की आवश्यकता है, एक करोड़ महिलाओं के लिए अलग से यह प्रावधान किया है । इसके लिए मैं पैट्रोलियम मंत्री और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, चीनी की मंहगाई की बात की जा रही है । चीनी के निर्यात के संबंध में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 100 लाख टन की निर्यात की सीमा निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्टूबर में जब चीनी का सीजन शुरू होगा तो तीन महीने की खपत को कवर करने के लिए सरकार के पास भण्डारण रहे । इसके लिए 100 लाख टन की कैपिंग हमारी सरकार ने की है । यह केवल इसलिए कि हम कीमतों को नियंत्रित कर सकें ।

खाद्य सुरक्षा कम करने और कीमतों को कम करने के लिए गेहूं के निर्यात पर हमने प्रतिबंध लगाया है । चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त किसानों को उर्वरक पर 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सरकार ने तैयारी की है । अगर सरकार चिंतित नहीं होती तो देश की 65 से 70 फीसदी आबादी किसानों की है, उन किसानों की चिंता के कारण सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, आप देखिए कि वर्ष 2011-12 में हिंदुस्तान में चने का समर्थन मूल्य 2800 रुपये था । आज मोदी जी की सरकार ने उस समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 5200 रुपये अगर किया है तो उसी 65 फीसदी की आबादी की चिंता के कारण तो किया है । वर्ष 2011-12 में मसूर का समर्थन मूल्य 2700 रुपये था । ये लोग समर्थन मूल्य की बात करते हैं । सत्तर सालों में मसूर का समर्थन मूल्य 2700 रुपये पहुंचा था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने केवल वर्ष 2021-22 में उसको 5300 रुपये पर ला कर खड़ा किया है । लगभग दोगुने के बराबर किया है । वर्ष 2011-12 में अरहर का समर्थन मूल्य 3000 रुपये था, आज 7000 रुपये के आस-पास है ।

लोग गरीब की थाली से दाल गायब होने की बात करते हैं । इस देश की वह 65 फीसदी आबादी जो मूंग का उत्पादन करती है, उसके समर्थन मूल्य को 3000 रुपये से 7300 रुपये अगर किसी ने किया है तो हमारी एनडीए की, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है । यह बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान का जो अनाज महंगा होता है, मैं सदन के माध्यम से मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे ही अनाज मंहगा होता है, इस देश में एक साथ आवाज़ आती है कि गरीब के घर से आटा गायब हो गया, कोई कहता है कि गरीब की थाली से दाल गायब हो गई ।

मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जब इस देश की 65 फीसदी आबादी उत्पादक है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देश की 65 फीसदी आबादी जब खेती पर निर्भर करती है, 65 फीसदी आबादी किसानी पर निर्भर है तो उसका अनाज अगर मंहगा होता है तो इस पर हमारे पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? यह चिंता का विषय क्यों है? मैं इस बात

को हमेशा कहता हूँ कि अगर किसान की जेब में पैसा जाता है, वही पैसा निकल कर बाजार में जाता है । उसी पैसे से आदमी स्टील खरीदता है, उसी पैसे से दालें खरीदता है, आदमी उसी पैसे से आटा खरीदता है । उसी किसान के पास जो व्यक्ति मज़दूरी करता है, उसको मज़दूरी के माध्यम से पैसा जाएगा । सरकार की मनरेगा योजना के माध्यम से पैसा जाएगा । बाजार में पैसे का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए । अगर बाजार में पैसा घूमता रहेगा तो आंशिक मंहगाई भी व्यक्ति के लिए चुनौती नहीं होती है, अगर उसके पास पैसा है । सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि किसी भी सैक्टर में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए । इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सड़क बनेगी तो व्यापारी का स्टील बिकेगा, सड़क बनेगी, प्रधान मंत्री आवास बनेगा, सीमेंट उद्योग चलेगा । वह चलेगा तो हमारे कारपेंटर को काम मिलेगा । बिजली का सामान बिकेगा, कलर बिकेगा, मज़दूरी मिलेगी । मतलब कितनी चीज़ें है, जो इस रुपये के पीछे चलती हैं । सबसे महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है कि आम आदमी, किसान, जरूरतमंद और गरीब के पास पैसे की कमी न हो, बाजार में पैसा चलता रहे । इस चुनौती को अगर सरकार ने सहजता से पार किया है, तो मैं उसके लिए भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चुनौती, वर्ष 2013-14 के बाद इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की थी । इस चुनौती को अगर सफलतापूर्वक किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के जननायक माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है । उन्होंने हिन्दुस्तान में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है । आज चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हों, भष्ट्रचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है । जबकि दूसरी सरकारें चल रही हैं आप देख रहे हैं कि कहीं 50 करोड़ रुपये जब्त हो रहे हैं, कहीं 100 करोड़ रुपये जब्त हो रहे हैं । कहीं गाड़ी के अंदर से 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं । हम गाड़ी में पाँच हजार रुपये रखकर ले जाने में सोचते हैं कि ऐसा क्यों करें, कार्ड का उपयोग कर लेंगे और लोग 50-50 लाख रुपये लेकर गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं । यह चुनौती थी ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीब को घर देने का काम किया है । बड़ा आदमी अपने मकान और अपनी ज़मीन को मॉर्टगेज़ करके बैंक से पैसा ले सकता था, अपनी सम्पत्ति रख कर कर्ज़ ले सकता था, लेकिन गरीबों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता था । हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीब को, जिस जगह पर वह रह रहा है, उसे भू-अधिकार देने का काम किया है । उस अधिकार-पत्र को भी वह बैंक में रेहन रख सकता है, बैंक में उसे रखकर पैसे उठा सकता है । इसको भी एक मदद के रूप में हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के लिए इस देश में किया है ।

किसानों को एम.एस.पी. दिया है, सम्मान निधि दी है । सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा अति निम्न वर्ग है, जिसके लिए लोग चिंता कर रहे हैं, आज विपक्ष के लोग केवल भाषण देते

हैं, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, उन स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए भी काम किया है ।

विपरीत परिस्थितियों में अगर महँगाई बढ़ी है, कोविड के कारण अगर देश में थोड़ा-बहुत कुप्रबंधन हुआ है तो उसको दूर करने के लिए हमारे स्ट्रीट वेन्डर्स को भी सीधी मदद करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसे हमारे देश की सरकार ने किया है । माननीय सभापति महोदय, आज आयुष्मान भारत योजना लाई गई । देश में अगर गरीब की चिंता नहीं होगी, गरीब के पास पैसे की कमी है, इसीलिए तो आयुष्मान भारत योजना लेकर आए । दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम अगर किसी ने दिया है तो उसे हिन्दुस्तान के हमारे प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी ने दिया है । आज आयुष्मान योजना से इस देश के करोड़ों लोग कवर हुए हैं । माननीय सभापति महोदय, हम नौजवान की चिंता करते हैं । नौजवान की चिंता है, इसलिए तो स्टार्ट-अप चालू किया । एक नौजवान, जो नौकरी के लिए भागता था, स्टार्ट-अप योजना के माध्यम से सैंकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है । माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार काम कर रही है । भाजपा-शासित जो राज्य हैं, मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश के बारे में एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं । हमारे किसी साथी ने हमारे राज्य में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात की थी । हमारे यहां बेटी के जन्म पर 1,20,000 रुपये की एफ.डी. कराते हैं । बेटी की शिक्षा फ्री है । दसवीं कक्षा के बाद उसे गाड़ी देते हैं, बारहवीं के बाद उसे स्कूटी देते हैं । अगर बिटिया मेडिकल या किसी भी क्षेत्र में पढ़ने जाए तो उसकी फीस जमा करने का काम सरकार करती है । उसके विवाह में 51,000 रुपये खर्च करने का काम करती है । जब बिटिया प्रेग्नेंट होती है, तब उसे पैसे देने का काम हम करते हैं । जब वह बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म के बाद माँ को लड्डू खाने को मिले, इस बात के लिए सरकार पैसे देती है । जन्म से मृत्यु तक मदद करने वाली हमारी सरकारें हैं ।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में, मैं कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने लगातार गरीबों की, किसानों की मदद की है । मैं इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं । जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग है, वह हमारी सरकार की प्राथमिकता में है । वह निम्न मध्यम वर्ग जिस दिन इस देश में आर्थिक रूप से व्यवस्थित चलने लगेगा, मुझे लगता है कि उस दिन हमारी चुनौती खत्म हो जाएगी क्योंकि इस समय निम्न मध्यम वर्ग, सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीद रखता है । मैं भी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में हम निम्न मध्यम वर्ग के साथियों को और राहत देने का काम करेंगे, जिस तरह से हमने गरीबों और किसानों की मदद की है । अन्त में, हमारे मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी के मन में देश के लिए जो चिंता है, उसे मैं दो पंक्तियों में कहना चाहता हूं ।... (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, मोदी जी देश के लिए सोचते हैं । वे क्या सोचते हैं -

तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में,

मसला सिर्फ मोहब्बत का ही नहीं,

तेरी फिक्र का भी है,

देश की फिक्र का है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***m24 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, being a Member of Parliament, you would be following the proceedings of the two Houses of Parliament very well. We all know that from the 15th Lok Sabha to the 17th Lok Sabha, the issue of price hike was discussed nearly 70 times in Lok Sabha, and about 11 times in Rajya Sabha. However, the Central Government has been incapable of arresting the price hike during these regimes - the 15th, 16th and 17th Lak Sabhas.**

I was hearing the speech of one hon. Member saying that because of COVID-19, the price hike is there. May I ask a question to this House that before COVID-19 whether price hike was not there in the country? Has inflation not increased in the country? What did you do? Now, another *alibi* has come. The *alibi* is that because of Ukraine and Russia battle, the world market has gone down and price hike is there. Okay. Before Ukraine and Russia battle began, was there not a price hike? आपने कभी नहीं बोला । वर्ल्ड में सभी देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा देश अच्छा चलता है, यह आपने नहीं बोला । आपने बोला कि हमारे नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा देश अच्छा चला । आपने यह सब कभी नहीं बोला और अभी आप बोल रहे हैं कि **because of Ukraine and Russia battle, the market, the economy, everything has gone down.** वैसा आपने कभी नहीं बोला ।

The International Monetary Fund is calling on Governments to focus on giving support packages to those who need it the most to avoid triggering recession. It is a fact that out of 130 crore people, over 97 crore Indians – or about 71 per cent of the country's population – are unable to afford nutritious food in our country itself. All limits of price rise have been crossed when the Government imposed GST on packaged food items like milk, dahi, lassi, chura,

muri, paneer and other nutritional food items which has seriously affected the intake of the consumers. India has become world's top milk producer with a minimum profit in this sector in the country. But this policy will soon help big players to enter into the sector which will adversely affect small dairy farmers of the country. Milk consumers are price conscious. Milk with muri, chura, sattu and milk products being essential consumables, the Government should rollback their decision.

Due to 12 per cent GST on condensed milk, butter, ghee, and cheese, the wholesale price inflation for milk product rises to 20.33 per cent in June 2022 against 6.96 per cent in June 2021

Rising food prices have become painful to us where 42 per cent of household incomes are spent on food in India. India's wholesale price inflation also runs at 30-year high; 2021-22 has become the year with the highest average yearly wholesale price increase in the past decade with an increase of 13 per cent. All the records have been crossed. हमारे 70 वर्ष और उसके 70 वर्ष को आप छोड़ दीजिए । अभी देश के आदमी का क्या हो रहा है, उसको आप देखिए । Much of this increase is driven by fuel prices, which accounted for 25 per cent of the jump in wholesale prices. Prices of manufactured products are contributing 60 per cent to the Wholesale Price Index (WPI)

Sir, I will give details regarding just a few items or commodities that we all use every day. The inflation rate for primary articles in June 2021 was 8.59 per cent; it has increased to 19.22 per cent in June 2022. The inflation rate for cereals was (-) 2.77 per cent in June 2021; it has increased to 7.99 per cent in June 2022. The inflation rate for wheat in June 2021 was (-)1.77 per cent; it has increased to 10.34 per cent in June 2022.

The inflation rate of vegetables was -0.78 per cent in June 2021. It has now risen to 56.75 per cent. Some hon. Member was talking about tomatoes. You should first look at potato and then we will come to tomato. In June 2021, the inflation rate of potato was -31.09 per cent. It has increased to 39.38 per cent in June 2022. In the month of June 2021, the inflation rate of fruits was 6.96 per cent, and it has now increased to 20.33 per cent in June, 2022. I now come to the most important commodity of fuel and power, in which case the inflation rate in

June 2021 was 29.32 per cent, and it has now increased to 40.38 per cent. The inflation rate in the case of cement, lime, and plaster has increased from 2.13 per cent in June 2021 to 9.16 per cent in June, 2022.

As per NSO, the consumer food price inflation for rural areas was 3.94 per cent in March, 2021. It went up to 8.04 per cent in March, 2022. Similarly, the CPI inflation for rural India has gone up to 7.66 per cent in 2022, from 4.61 per cent in March, 2021. These figures belong to two years of your regime. Please see, within one year how much it has increased.

Poor or rural households, in general, are actually not getting food within their expenditure basket due to high prices, which is a sign of deep distress, particularly among the poor population. Rural inflation was recorded at 7.09 per cent in June, while urban inflation was 6.92 per cent.

The average annual food expenditure per household across India has risen from Rs.24,650 in 2014-15 to Rs.28,870 in 2020-21. वर्ष 2014-15 में आप आए, हममें से कोई नहीं आया । It is now expected to rise to Rs.33,610. This is not due to rise in income, but due to price rise of food items during that period. A report says that rapid increase in economic growth surely trickles down to an average Indian household. Indian economy is facing stagnation, which means the unemployment and inflation at the same time remain continuously high. High inflation has come at the back of higher food and beverage prices. Data analysis shows that food and beverages have contributed 43 per cent to inflation year-on-year and 198 per cent month-on-month.

The wholesale price index based on inflation rose to an eight year high of 7.3 per cent in March and is elevated at 7.8 per cent higher on food, and fuel prices. Food prices, which comprise about half of the inflation basket, accelerated to 7.75 per cent in June, while fuel and electricity prices went up to 10.39 per cent.

Shrimati Supriya Sule ji was correct when she was talking about the bank transactions. When Ravi Shankar ji was the Minister, he thought about the Digital India. Modi ji has also thought about the Digital India. I would like to say that for one bank transaction we are paying money. I would suggest you to just lift the veil and then you can see how the money is being squeezed from the pockets of the general public at large. If you wish to take the Cheque Book now,

you have to pay GST. I am thankful to Madam Sule for pointing it out before the House. This is happening. Everyone is now talking about online banking system. It is for whose benefit! Is it for the benefit of the consumers or the bank itself?

This question has now come up for consideration. … (*Interruptions*) Sir, I will just finish.

In case of subsidised LPG, the direct benefit transfer of domestic LPG was Rs. 22,726 crore in 2019-20, which came to Rs. 3,658 crore in 2020-21.

HON. CHAIRPERSON: Please leave the statistics.

SHRI KALYAN BANERJEE: I do not want to burden with more statistics.

HON. CHAIRPERSON: Leave the statistics.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I am not on statistics now. I have an appeal to each and every one present here. This is an important discussion which is taking place. I have given you the statistics. More statistics will come next month. There will be arguments and some points will be drawn from those arguments. We will also criticise. But ultimately, who are the sufferers in this country? Ultimately, who are suffering? These poor people are suffering. What are you doing for them? सिर्फ रोने से कुछ काम नहीं होता है । देश आगे बढ़ रहा है, देश कहां आगे बढ़ रहा है?

Sir, you are an hon. Member of Parliament. You have seen it yourself. You have gone to the rural places. I have visited extremely rural areas of four Assembly constituencies. You have given gas cylinders. You have given stoves. What are they doing with these? Subsidies are not there. Now, these poor women are not using gas cylinders and the same have been kept in their almirahs. They are now again using coal and wood for cooking.

HON. CHAIRPERSON: Kalyan *Ji*, now please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: Thank you, Sir. I am lucky that whenever I speak, you are in the Chair. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Now, Madam Jothimani *Ji.*

… (*Interruptions*)

***m25 *SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in this discussion on price rise.**

I come from an ordinary farmer's family. My family has 10 acres of land and a house in village. Only rain can bring a difference. If there is rain there will be growth of crops in our farm land. We can rear 20 goats. Only the revenue through these cattle will be for the farmers. If this is the living condition of a farmer, what will be the fate of a farming labourer who is totally dependent on the 100 man days of work under MGNREGA. This MGNREGA is like a boon to them during their hard times. This nation is thanking Annai Sonia Ji for such a visionary scheme. I am thanking Madam Sonia Ji on behalf of the people of my constituency. This is the state of affairs of my village, my Karur constituency, my State Tamil Nadu and this country India under your rule.

Your Government do not support the MSMEs or Small Scale Industries. You support the corporate giants and rich industrialists in a duty-bound manner. You go to the neighbouring country, Sri Lanka and bargain for an agreement with that nation on power sector to be signed in favour of corporate companies who are your friends. We have not seen in Indian history that any Prime Minister of our country has openly bargained with a neighbouring country. There was a cyclone in the political circles of Sri Lanka due to this. You are not ashamed of this. From Airports, Ports, and power sector agreements to 5G Spectrum allocation, everything is given to your corporate friends. After you came to power, in the last 8 years, your friend Adani has become the fourth richest industrialist not only in India or Asia but in the world. Such miracles happen in your Government. We the opposition cannot sing songs in praise of you. But we are opposing you for the common cause as you failed in controlling or containing price rise.

We are protesting against the GST and price rise which are affecting the common man of this country. You are unable to tolerate if we protest for the

common good. You anger takes action against the protesting representatives by making them sent outside the parliament premises.

I would like to state some statistics for your consideration. During Congress Government rice per kg was Rs 26. In BJP Government it is sold at Rs 36 per kg. Wheat was sold at Rs. 20 per kg during Congress Government whereas it is sold for Rs 30 per kg during BJP Government. Toor dal or pigeon pea was Rs 69 per kg during Congress Government and in BJP Government's rule it is sold at Rs 101. Urad dal or de-husked black gram lentils were sold at Rs 65 per kg during Congress Government's rule. Whereas it is sold now at Rs. 103 per kg. Groundnut oil was sold at Rs122 per kg and now in BJP's rule it is Rs.184 per kg. Mustard oil was Rs.95 and now it is Rs.183 per kg. Vanaspathi was sold for Rs.73 per kg and now it is at Rs.160. Sunflower oil was Rs 96 per kg during our rule and it is Rs. 188 per kg in your rule. Palm oil, used by the poor people was sold for Rs. 74 but it has increased to Rs.156 now. Rice, Pulses, Milk, Cooking oil, curd, Rooms in Hospitals, emergency services, and even electric crematorium has seen a 5 per cent of GST. Milk is the supplement for a child. How can a poor mother, who is fully dependent on 100 man days of work through MGNREGA, feed her only child with milk if you charge 5 per cent GST on milk. Have you thought about it?

Our Finance Minister is a woman. I am not asking her to take responsibility for this as she is a woman. She as a woman should have more sensitivity than men. Can she put GST on milk, rice or pulses? How the common people can survive. Education can pave way for a better future for the poor children. Education can save them from atrocities in the society. Education can make them to create history. You have put GST on pencil. How can they afford to pay for their education. Are you not sympathetic? Can all be given treatment in Government hospitals. Can't they go to private hospitals for treatment? You are putting such medical treatments in private hospitals under 5 per cent GST. This Government is so cruel than the British. Electric crematorium. In my Karur parliamentary constituency there is a private electric crematorium. They charge Rs 600 for cremation. There were people who cannot even pay Rs 600 for cremating such dead bodies. Such people with tear filled eyes wait outside these crematoriums with dead bodies and without money to pay. I have tried to help

them. You cannot see such incidents as you are happy serving your corporate friends and obliging them. This Narendra Modi Government is putting tax on people from birth to death. I am condemning you as you have no mercy towards our people but you are putting taxes on people without application of mind.

Gas cylinder cost was Rs 410 during Congress Government's rule. But it is Rs. 1100 during your *Ache Din* rule. You claim to have given cylinders to Crores of people. During the time of Government led by Shri Manmohan Singh, gas cylinders were given free of cost. I should say that 2 Crore people have not even booked one cylinder in last one year. They have gone back to using wood for cooking, the eyesight and health of women are affected. But you are not bothered in anyway. But if we protest holding a placard stating Rs. 1,082 per cylinder, you are terming it as a wrongdoing.

For Petrol and Diesel, during 2014-15 budget Rs.72,160 Crore was the tax amount. It was Rs 29,279 Crore for petrol and Rs. 42,881 crore for diesel. But during your rule, Rs 3,92,000 Crore is the tax amount. And it is Rs 1,21,730 Crore for diesel and Rs. 2,70,270 crore for petrol. Is it not daylight robbery? Oil bonds. You say that you are paying those oil bonds. Oil bonds are brought during Vajpayee's Government. It was to the tune of Rs. 9,000 Crore. When Congress was demitting from power, 1,34,429 Crore worth bonds were purchased. Only two such bonds attained maturity in 2015 during the Government led by Shri Narendra Modi. They are for Rs 1,750 Crore each. Altogether it was only for Rs. 3,500 Crore. That means Rs. 1,30,929 Crore. You have paid only Rs 3,000 Crore and rest was paid as interest. This was stated in your Budget document. But why are telling the untruth. The remaining amount is Rs 3,82,500 Crore. Where this money has gone? Why are you taxing the common man? This money is already collected by you by way of looting the public. Where have you utilized this money?

You have given Rs. 1,45,000 Crore to the corporate giants close to you in the year 2020 as corporate loans. They are termed as tax rebates to Corporates. ...* Common man is struggling hard for rice and other essential commodities. But you are into horse trading of MLAs by giving 100 Crore, 200 Crore or 300 Crore to each of them. You are a Government affecting the common people. Don't forget this.

Unemployment is at its peak. If you see the percentage of unemployment, it is 4.4 percent in Japan; 6.9 percent in Germany; 8.8 percent in Israel; 9.4 percent in Pakistan; 9.5 percent in Nepal; 9.6 percent in USA; 26.1 percent in Sri Lanka and 28.3 percent in India. You should be ashamed of this. If we protest, you will send ED to the leaders of Opposition as well as Congress party. We are not afraid of ED. The Government led by Shri Manmohan Singh lifted 27 Crore people above poverty line but you pushed 23 crore people below the poverty line. Either you control price rise or take back GST or resign and go home. Thank you.

-

<u>17.00 hrs</u>

***m26 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important subject … (*Interruptions*)**

Sir, although this subject is within the purview of the Finance Minister and she will be responding at the end of this discussion, I feel that if the hon. Minister of Consumer Affairs can also intervene in the discussion and apprise the House on what his Price Monitoring Division in particular, and his Ministry in general has done to monitor, control and contain prices of essential commodities, it would definitely add value to this discussion.

Sir, I would like to thank the hon. Speaker for permitting to take up the discussion on price rise which is really hitting the common man. It is a double whammy for the poor and the middle-class. First, they suffered due to the pandemic and now this skyrocketing of essential commodity prices. Running inflation and hike in fuel prices are adding fuel to the fire. I hope that the *manthan* of this debate will give *amrit* in the form of suggestions. I am confident that the hon. Finance Minister and the Minister of Consumer Affairs would take them in good spirit and act on them to rein in the prices of essential commodities which are really pinching everyone.

Sir, I tried to analyse, with my limited knowledge, the main reasons behind the rise in prices of essential commodities and found unabated increase in the prices of petrol and diesel are the main reasons, followed, to some extent, by the Russia – Ukraine armed conflict. It is not just the common man but even small

businesses, like restaurants, food joints, hotels and others are also suffering. There is substantial increase in prices of fuel, vegetable, chicken, edible oil, fruit, gas etc., and small-time restaurants cannot increase the prices of food items. If they do, they lose customers; if they do not, they are incurring losses. Such is the situation. They are in a paradox. So, for all these ills, I feel, the only solution is to bring petrol and diesel under the purview of GST. This is my first suggestion to the hon. Finance Minister.

Sir, inflation is hovering at more than 7 per cent, much more than the RBI's threshold limit of 6 per cent. For many months now, the CPI has been hovering around 8.5 per cent and the WPI registered 16 per cent in the month of May. Inflation is nothing but taxation without legislation.

I agree with the hon. Finance Minister that price rise is a global phenomenon and India cannot be insulated from this. I also agree, to some extent, when the Finance Minister says that the Russia – Ukraine conflict also disrupted supply chains and resulted in increase of prices. This is true. But at the same time, inflation is primarily caused by two reasons. One is demand-pull inflation; and the other one is cost-push inflation. The former can be controlled by reducing money supply, or increasing prices through taxation. But when it comes to the latter, the measures needed are to increase the supply to meet the demand which is not happening. More so, with floods in almost every part of the country, this will further worsen in the coming days. I would like to know from the hon. Finance Minister the details of monetary, fiscal, administrative, and price control measures taken by her and the Reserve Bank of India to control inflation. This is my second point.

My next point is on containing retail prices. As per the existing system, retail prices are fixed by market forces and people think that the Government has a limited role to check spike in an unacceptable price rise. This is not fully true. Look at the Legal Metrology Packaged Commodities Rules. It has a provision to fix the retail price of essential commodities if the prices go up and now the retail prices have shot up abnormally. It is not applicable to just packaged commodities, but also applicable to loose items sold in retail market.

So, I suggest the hon. Finance Minister and also the Minister for Consumer Affairs to take proactive steps and fix retail price for essential commodities for a certain period of time in the interest of the consumers.

Sir, vulnerable sections of the society are suffering due to high prices of commodities right from vegetables, pulses, oil, milk and what not but, to rein in high prices, we have one more mechanism and that is Market Intervention Scheme. The objective of this Scheme is to intervene and stabilize the prices in the market and ensure that shortages do not adversely impact the consumers. So, the House would like to know and the country would like to know about the interventions which the Government of India has made through the Market Intervention Scheme to stabilize the prices and whether such initiatives give good results or not.

Sir, it is not just the Market Intervention Scheme but we also have the Price Stabilisation Fund to tackle inflationary trends. What has the Ministry done to implement this to deter speculative and hoarding of essential commodities? These details may also be explained to the House.

The next point that I wish to make is relating to GST imposed on curd, buttermilk, lassi, atta, rice, etc., from 18th of this month. You know that GST collections are breaking records and giving huge revenue. By imposing five per cent GST on these items, how much extra could you possibly earn? Secondly, look at the message that you are giving to the poor by imposing GST on these items to garner a few crores of rupees. So, I appeal to the hon. Finance Minister and the Government to remove the GST on the above packed or pre-packed items which will give a sigh of relief to the common man.

Oil is also an essential item in the kitchen whose prices have also gone up and to address this, the Government of India has allowed duty-free import of 20 lakh tonnes of crude soyabeans and crude sunflower. I feel that this quantity is not enough. Hence, I request for increasing the quantity of 20 lakh tonnes more on duty free terms which will further soften prices of edible oil in the country.

Sir, my last point is this. I have seen in some reports which say that India has zero per cent chance for recession. With global recession already underway in some regions and quickly spreading to other parts of the world, how will India be

immune to such a global recession? This may kindly be explained to the House. And if we are not immune, what is the financial impact on India, what are we going to do to prepare for this and how will this global recession impact the inflation in India further?

Thank you, Sir, for giving me the time to participate and I look forward for a response from the Finance Minister.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it has been decided to conclude the debate by 6.30 p.m. to 6.45 p.m. and then the hon. Minister has to reply to it. So, all the Members are requested to confine themselves to their time limit. This is the direction from the hon. Speaker. Adv. Ariff may speak now.

***m27 ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I take this opportunity to thank this Government for their magnanimity to allow a discussion on price rise on the floor of this House after two weeks of constant protests by the Opposition Parties both inside and outside the Parliament.**

In the discussion on price rise, currency depreciation and inflation, and unemployment, you cannot escape just terming these issues as global phenomena.

Sir, every now and then, the BJP Members remind us about worshipping the *gomata* and they are trying to scientifically prove the medicinal benefits of products like *panchagavya* made of cow milk, curd, urine and cow dung.

Sir, I would like to get an answer from my colleagues belonging to BJP on why they are dishonouring the *gomata* by levying a five per cent GST on products like milk and curd. No doubt, *gomata* will curse this Government definitely. I thank this Government that cow dung and urine are exempted from GST. I have only a humble request to this Government not to bring them also under the purview of GST in the next round.

This Government has been arguing for the past few days that the decision to levy five per cent GST on products like packed rice was taken unanimously in the GST Council. In the GST Council, it was informed that it would be applicable only for sales in big shopping malls. But this Government has tried to make it applicable for all kinds of shops through the back door.

Rice is the staple food of Kerala and, on behalf of the people and Government of Kerala, I express my strong protest on charge of five per cent GST on rice and rice products.

Sir, the price of domestic LPG cylinder has become Rs1,083 now from just Rs.263 in 2014. You started giving subsidy amount to bank accounts saying that subsidy will reach the real beneficiary. But for the past one year, you have not been paying even a single paisa as subsidy. Now the real beneficiary is none other than the Central Government.

Sir, this Government introduced the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide free gas connection to poor households and large hoardings of the Prime Minister were kept in almost all the petrol pumps praising him. What is the current status of this Scheme? Since 2021-22, not even a single penny has been spent by this Government for the Ujjwala Yojana. This answer has been given to the question of hon. Member, Com. A.A. Rahim in the Rajya Sabha. The answer is with me. Not a single rupee has been given to the Ujjwala Yojana. So, I request the Government to remove such hoardings kept to deceive the people of the country. In modern India, thousands of households have switched to traditional fuels because they are not able to bear the price of LPG.

Sir, this Government has come to power by giving a false promise to the people of the country that it will reduce the price of all petroleum products including petrol, diesel, kerosene, and LPG by half. India's LPG cost per litre is the highest in the world, third in petrol. May I read one speech of hon. Modi Ji on 23rd May, 2012? It says: "Massive hike in petrol prices is a prime example of the failure of the Congress-led UPA Government."

Regarding the value of rupee, Sir, the then hon. Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi had made a spectacular speech long time back and I quote him. "When the currency of a country is depreciated, it means that the country has become weak." In that speech, our Prime Minister exhorted that the value of Indian rupee against US dollar went down the most during the UPA regime. What is the situation now? If the exchange rate against US dollar was Rs.63.33 in 2014, now it is Rs.80. So, I request the hon. Prime Minister to rewind that news clip

available in social media and publicly offer an apology to the people of this country for his remarks.

If you wish to control the price rise whole-heartedly, there are so many alternatives. Please look at the State of Kerala. If Kerala can become a model, why not the whole India? It just needs Government's sensitiveness to the wishes of the people and political will power.

Sir, I am proud of the decision taken by our LDF Government not to increase the price of 13 essential food items sold through the Maveli store in every nook and corner of the State and that it has kept its words for the past six years.

Let me just read out the prices of some essential items with no change in prices for the past six years for the information of hon. Members. The price of sugar in open market is Rs.40 per kg and we are giving it at Rs.22. The price of red chilli in open market is Rs.116 and we are giving it at Rs.37 only. The price of coriander in open market is Rs.72.50 and we are giving it at Rs.39.50 only. Now we have decided to give 14 essential items free of cost to eighty lakh ration cardholders. Sir, this is the real model of India. They can use this model to keep the price rise under control.

Thank you.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं बराबर सुन रही हूँ कि महंगाई को लेकर जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के भाई सांसद और बहनों ने अपने विचारों को रखा है, चूँकि ये विगत 75 वर्षों के अपने पिछले इतिहास पर ध्यान देते तो मैं समझती हूँ कि इनको सोचने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लाइन्स मिल जाती ।

हमारी पार्टी के माननीय सांसद भाई श्री उदय प्रताप जी ने इन सबकी बातों को सुनकर जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मांग और पूर्ति के समन्वय, मांग और पूर्ति के सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से हमारे देश में कुछ वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ी और उस महंगाई का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया, फिर भी हमारे माननीय सांसदों ने, बहनों ने कुछ भावनात्मक बातें कही हैं । भावनात्मक बात मैंने सुप्रिया जी की सुनी । माननीय सुप्रिया जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, कनिमोझी जी भी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं । मैं सोचती हूं:

"जिनके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जानें पीर पराई ।"

मैं एक बात कहना चाहूंगी । यहां 60 साल और 8 साल की बात की गई॥ माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में जो 8 साल का शासन रहा, गांव-गरीब का, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का, हमारे देश के सम्मान का, हमारे देश के सम्मान को जिस तरह से आज विश्व पहचान रहा है, आप सभी यदि यह एहसास करते या अपने मन में झांककर देखते तो शायद यह पता चल जाता कि वह भी एक जमाना था, जब देश आज़ाद हुआ था, 33 करोड़ आबादी थी, लेकिन उस समय भी माननीय दिनकर जी ने एक बात कही थी :

"श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,

मां की हड्डी से चिपट निठुर जाड़े की रात बिताते हैं ।"

वह बात याद नहीं रही । यदि वह बात याद रहती तो 60 साल और 8 साल, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के 8 साल हमें बेमिसाल प्रगति की झलक देते हैं और हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे गरीबों का सम्मान बढ़ा है । मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि आज कोविड महामारी के बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने संभाला, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मई, 2014 के बाद पहली बार अप्रैल, 2022 में महंगाई की दर 8 फीसदी रही । इस 8 फीसदी दर को यदि हम निगेटिव मानते हैं तो मैं उनको यह याद दिलाना चाहती हूं कि वर्ष 2009 में महंगाई दर 12 फीसदी से ऊपर चली गई थी । उसके बाद जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब महंगाई दर 13.50 फीसदी पर थी । ऐसी स्थिति में, यदि हम बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों का संतुलन देखें तो इस कोरोना काल में भी जिस तरह से इस राष्ट्र को संभाला गया, सारी दुनिया उसके लिए दांतों तले उंगली दबाती है । आज हम सब बिना मास्क के बैठे हैं, 200 करोड़ लोगों के लिए टीकाकरण की समुचित व्यवस्था करने के बाद, विदेशों में भी इस टीके को पहुंचाकर उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को भी चरितार्थ किया है । गरीब किसान की चिन्ता की है ।

आप यदि महंगाई को देखें तो मैं सोचती हूं कि सब केवल डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के नाम पर ही महंगाई के लिए चिल्ला रहे थे । अभी इतने दिनों तक हमारा सत्र प्रभावित हुआ । जो लोग गैस सिलेंडर का लेबल लगाकर, रेट लिखकर तख्तियां लेकर बैठे हुए थे और संसद की व्यवस्था को प्रभावित किया, उनको झांकना तो चाहिए कि जिस समय आपने सरकार छोड़ी थी, उस समय गैस सिलेंडर 1241 रुपये का था और उस पर 423 रुपये सब्सिडी थी, जिसके कारण आप हलवा खा रहे थे । जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गैस की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया, उससे गरीबों के लिए 9 करोड़ गैस कनेक्शन्स फ्री मिल सके । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आप किसान की बात करते हैं, यदि किसान का उत्पादन महंगा हो गया तो आप चिल्ला रहे हैं । यह पूरा सदन,

यहां जो भी बैठे हुए हैं, मैं एक गांव की, गरीब और अनपढ़ किसान की बेटी हूं, एक छोटे से किसान परिवार की बहू हूं, मैं जानती हूं कि जब किसान को उसके उत्पादन का अच्छा दाम मिलता है, तो उसके चेहरे पर रौनक आती है । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी की जो वकालत की है, मेरी पार्टी के यशस्वी सांसद श्री उदय प्रताप सिंह जी ने जिस तरह से आपको बताया है, मैं राजस्थान से आती हूं, बाजरे की एमएसपी 2300 रुपये करने के बाद राजस्थान की सरकार ने एक किलोग्राम बाजरा नहीं खरीदा है ।

किसानों को वह 1100 रुपये, 1200 रुपये और 1300 रुपये के रेट से बेचना पड़ा । आज भी उनके घरों में बाजरा सड़ रहा है । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे टीएमसी के भाइयों और बहनों ने बड़ी अच्छी तरह से लच्छेदार बातों में हमारी आलोचना कर दी, लेकिन उस आलोचना के पीछे कुछ सच्चाई भी रखो । अभी मैं वेस्ट बंगाल के करीब 25-30 गांवों के अंदर घूम कर आई हूं । मैंने देखा कि छोटा सा पॉण्ड खुदा हुआ है । उनको शौचालय नहीं मिला है । हमारे मोदी जी ने 12000 रुपये शौचालय के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत दिए, लेकिन वहां शौचालय नहीं बना । उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन पक्का मकान नहीं मिला और उनके लिए किसान कल्याण योजना दी, वह उनको नहीं मिली । वहां वे छोटे से तालाब में सड़े हुए पानी को पी रही हैं, नहा रही हैं और उसी तालाब के अंदर बत्तख और मुर्गी पल रही हैं । उसी एरिया में केवल एक धोती को पहनकर मेरी बहन अपने घर का गुजारा कर रही है । क्या आपके दिल के अंदर उस समय दर्द पैदा नहीं हुआ? आप महानगरों में रहते हैं । आपको 20-25 लाख की आबादी ने चुनकर भेजा है । गरीब कल्याण के लिए, जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या आप वहां तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं? यदि मदद करते तो आज पार्थ जैसे पूर्व मंत्री के घर के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता । बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ियों में भर-भरकर रकम ले जा रहे हैं । यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के काले धन को इधर से उधर करने में होगा? यह पैसा किसका है? यह पैसा उन गरीब शिक्षकों का है, जिन गरीबों ने 20-20, 25-25 लाख रुपये दिए, लेकिन उसमें फर्जी नौकरी मिली । फर्जी नौकरियां लेने वालों के लिए यह आपके कुकृत्य, यह बुरे काम क्या हमारी महंगाई को प्रभावित नहीं करते, क्या हमारी आर्थिक नीति को प्रभावित नहीं करते? मैं आप सबको इतना कहना चाहती हूं कि भारत की यह स्थिति थी कि जब भारत के मुखिया विदेशों में जाते थे तो कोई पहचान नहीं थी, कोई उनको मिलने नहीं आता था ।

आज मोदी जी जाते हैं तो तहलका मच जाता है कि मोदी, मोदी, मोदी । कारपेट बिछाकर उनसे मिलने के लिए आते हैं । क्यों आते हैं? क्या वह करप्ट हैं, क्या वह बेईमान हैं? आज हमारा एक भी मंत्री किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से लांछित नहीं है । यह 8 साल

की बेमिसाल सरकार है । आप इस सरकार के बारे में कुछ सोचेंगे? आप कहते हैं कि 10 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं । गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पक्का घर, शौचालय, किसान कल्याण योजना, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, टौंटी से मिलता हुआ पानी, क्या आप लोगों ने यह कभी सोचा था? आज बढ़ती आबादी, घटते संसाधन का संतुलन करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सारे भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं । वे गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे हैं, वे मेहनत करते हैं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, मेहनत के साथ इस सरकार की नीतियों को, मोदी जी के आदर्श और आप पेट्रोल, डीजल तथा गैस की बात करते हैं । गांव के उस गरीब को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने की जरूरत है । उस किसान को जरूरत है कि उसको बहता हुआ जल मिले और उस बहते हुए जल के साथ अपने उत्पादन को बढ़ाकर महंगे दामों पर बेचे । आप तो खाने वाले हैं । 65 परसेंट काम करने वाला वह अन्नदाता है, 25 परसेंट उसके साथ काम करने वाले कृषि मजदूर हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मीना जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती जसकौर मीना : सर, मैं आपसे एक मिनट चाहूंगी । बंधुओं, मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत की तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति इसके भविष्य की तरफ इशारा है । अभी 8 साल में जो काम हुए हैं, वह बेमिसाल हुए हैं । यह भी सही है कि नेतृत्व किसके हाथ में है, एक ऐसे इंसान के हाथ में है, जो गरीबी को जानता है, जिसने चाय बेचकर गुजारा किया है । वह सोने के महलों में नहीं रहे हैं । जिन लोगों के हाथ में 60 साल तक राज रहा, उनके बाथरूम में सोने की रीप लगी हुई है । यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । उनको इस बात का एहसास नहीं है । मैं कहना चाहूंगी कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश की जनता को उच्च मुद्रास्फीति की दर से निजात दिलाने के लिए... (व्यवधान) । आप यह देखिए कि रिजर्व बैंक के साथ 20 फरवरी, 2015 में एक मौद्रिक नीति ढांचा करार हस्ताक्षर हुआ । इस समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया था कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2016 में 6 प्रतिशत से नीचे रही थी । मैं आपको कहना चाहती हूं कि उक्त समझौता नि:संदेह हमारी वित्तीय व्यवस्था में देश की मुद्रास्फीति और भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है । ... (व्यवधान) आप महंगाई दर के ऊपर केवल डीजल, पेट्रोल और गैस से इस देश को कब तक गुमराह करते रहोगे, कब तक झूठ की दुकान चलाते रहोगे? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, एक मिनट रुकिए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती जसकौर मीना : मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेट्रोल के दाम में, आप हमारे देश की बात करते हो, सैंकड़ो देश ऐसे हैं, उनमें से 15 देश तो ऐसे हैं, जो रो रहे हैं, जहाँ घरों के आगे गाड़ियाँ छोड़ दी गई हैं । आप सोचिए भारत में ऐसा कोई नहीं है, जिसने अपनी गाड़ी को पेट्रोल... (व्यवधान)

***m29 SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity.**

Sir, the whole nation is worried about the rising prices of essential commodities including food items and other things. The only question before us is, what exactly is the reason for all these things and how to address this burning issue of our country.

Sir, the Government is trying to hide in a safe zone by saying that it is an after-effect of the COVID-19 pandemic and also an impact of the Russia-Ukraine war. They even say that it is a global phenomenon. To a certain extent, the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war must have put an impact on this. We are not denying this fact. But at the same time, if we make a meticulous study, we will be able to understand that the Indian Economy was clearly showing a downward trend even much before the outbreak of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. What was the management of financial fundamentals of this Government?

Sir, there are certain yardsticks to measure it. They are, Gross Domestic Product, unemployment rate, inflation rate, fiscal deficit of the Government, domestic currency's relative value against US Dollars, balance of payment, level of poverty and inequality, etc. If we analyse all these things of this Government in the past, we will understand that the performance of this Government was a poor show. They have to admit this thing. Of course, there was wide publicity and false claims regarding this.

Sir, what exactly is the position now? Kitchens are in turmoil because of the pressure of inflation. We had lockdown in the country during the COVID-19 pandemic. I apprehend, we will have lockdown in our kitchens also because of this negative strategy of this Government. Similarly, there is an erosion of people's purchasing power. It is diminishing like anything. It goes without saying that the

family budget is collapsing. Moreover, the devaluation of the Indian Rupee against the Dollar is the most worrisome issue. We can understand this very well.

Sir, a paradoxical situation is also coming up where a large dependability on import and a diminishing trend in export can be seen. That is also a worrisome issue. We can very well understand that that will lead to imported inflation which would also be a burden on the people.

Sir, the GST Council's decision on imposing tariff on the items of mass consumption is also terrible. My learned friends were explaining all these things. It goes without saying that nobody can have any kind of adjustment in this. India's debit obligation is also very high. It will also have a very big impact on our economy. This is making a negative marketing sentiment against India. So, if we analyse all these things, it is amounting to a bad position as far as India is concerned.

Sir, I wish to ask a question from the Government whether it is serious to take up meticulous kind of activities in order to arrest these kinds of bad synergies. I feel, the Government is not at all interested in that. What is the priority of the Government? The Government's priority does not seem to be of economic reforms. They are engaged only in political kind of considerations. They forget all these things when such things happen. So, I do not want to elaborate it further.

Sir, one of my learned friends from the other side was saying that under Modi ji, their Government has done wonders. What is the position of India now? Where does India stand today? They are all saying that they have done wonderful things. I would like to quote the report of the United Nations Development Programme.

The Human Development Index 2020 report was published by UNDP. As per the report, India stands at 131st rank out of 189 counties in the world. Now, I want to ask them where does India stand. They are all making false claims. Similarly, in terms of World Press Rankings, India slipped 8 positions below 142nd rank last year out of 180 countries in the world. ....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: I am concluding. There also you can see that India's position is much lower. In the Global Hunger Index also, India's ranking is at 101st position, which is much below even the African countries. If this is the position of India in international indices, then what is the meaning of their claims?

Sir, in order to have progress in a country, the essential ingredients are a congenial atmosphere, peace and co-existence. Unfortunately, you have spoiled that. There are many things to say. The people are worrying today. .... ***(Interruptions)***

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: I am concluding with only one thing. The Government is purposefully opening the floodgates of trouble. That is why I am saying that unless you ensure peace, and do justice to everybody, we will not be able attain economic growth in the country.

With these words, I conclude. Thank you very much.

डॉ. एस. टी. हसन **(मुरादाबाद) : सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया । यह वह टॉपिक है, जिससे इस देश का हर इंसान इफेक्ट होता है । इसीलिए, पार्लियामेंट में इतना गतिरोध हुआ । जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से गरीब परेशान है, यह मुझसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है । मैं यह समझता हूं कि इसकी मेन वजह है, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए गए हैं । हमें वह दौर याद है, जब 140 और 150 पर-बैरल इंटर्नेशनल मार्केट में तेल बिकता था, तब हम 70 रुपए पर-लीटर तेल खरीदते थे । हमने वह दौर भी देखा, जब 30 डॉलर पर-बैरल तेल मिला, तब हमने 80 रुपए पर-लीटर तेल खरीदा । आखिर यह डिसपैरिटी क्यों? वह पैसा कहां गया? आपने किन चीजों पर खर्च किया? आपने गरीबों का और हम सब लोगों का किस तरह से खून चूसा, यह सबको मालूम है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अचानक एक फैसला आया कि डीमॉनिटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई । नोटबंदी के बाद देश में क्या हालात हुए, यह सबको पता है । हमारी महिलाएं, हमारी बहन-बेटियां, हमारी घरवालियों के पास जितना भी जमा धन था, वह आपने निकालकर बाहर पहुंचा दिया । वे उसे अपनी इमर्जेंसीज के लिए रखा करती थीं । सर, हमारे देश ने बदकिस्मती से वह दौर भी देखा है, जब कोविड की इमरजेंसी आ**

गई, जिसमें हजारों लोग मर गए । तब गरीब के पास अपनों के बदन को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं । तब गरीबों ने नदियों में अपने परिजनों को बहाया था । उस गरीब की आह! कोई क्यों नहीं सुनता? हम अपनी ही बातों में मग्न हैं । कोविड की वजह से तकरीबन 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए । आपने वादा किया था कि दो करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे । आठ साल में सोलह करोड़ लोगों को रोजगार मिलने चाहिए थे । अभी आपने रिपोर्ट देखी कि कुल सात लाख लोगों को रोजगार मिले हैं । आखिर ये लंबी-लंबी बातें करने से क्या फायदा है? जनता को क्यों मिसगाइड किया जाता है? एक डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई थी । एक दौर वह था, जब वह थोड़ा भी बढ़ता था, तो बड़ा शोर मचता था । महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह भी है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कार्पोरेट सेक्टर को आपने कितनी सब्सिडी दी है? आपने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी । आपने खाने-पीने की चीजों पर, दूध, दही जैसी चीजों पर जीएसटी लगा दिया । दाल, आटे पर जीएसटी लग गया । क्या आप चाहते हैं कि गरीब पैक्ड फूड न ले? सभी को पता है कि जो चीजें खुली बिकती हैं, उनमें कितनी ज्यादा मिलावट होती है । खाने की चीजों में मिलावट होने की वजह से देश के लोग बीमार होते जा रहे हैं । किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी का जिगर फेल हो रहा है और किसी को कैंसर हो रहा है । क्या आपका इनडायरेक्टली आबादी को कम करने का यह भी एक तरीका है? आपने उन चीजों पर जीएसटी लगा दिया है, जो गरीब की थाली में था । मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जीएसटी को फौरन वापस लिया जाए । महोदय, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गरीब मरीज कैसे इलाज कराता है । वह अपनी बीवी का जेवर बेचता है, वह मकान गिरवी रख देता है, वह अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने परिजन का इलाज कराता है । आपने एक हजार के कमरे पर भी जीएसटी लगा दिया । गरीब पहले ही मर रहा है और बहुत परेशान होकर अपना इलाज करवा रहा है । यह कौन-सी इंसानियत है कि वह इस तरह का टैक्स दे? इस समय देश में एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ नहीं है, जो टैक्स न दे रहा हो । आप देश में इनफ्लेशन के हालात भी देख रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बढ़ी हुई जीएसटी की दरों को फौरन वापस लिया जाए और डीजल, पेट्रोल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम किया जाए ।

*m31 श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया है । यह एक ऐसा विषय है, जो सबसे जुड़ा हुआ है और सदन का यह दुर्भाग्य है कि बहुत दिनों से हमारे विपक्ष के साथीगण वैल में आकर, प्ले कार्ड उठा-उठाकर इस विषय पर अपनी बातें रखना चाह रहे थे । हमें लगा कि कुछ-न-कुछ बहुत बड़ी बात होगी, जो आज ये लोग हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । हम सभी साथीगण बहुत ध्यान से यहां बैठकर इनकी बातों को सुन रहे थे । उस तरफ के सभी

वक्ताओं की बात को सुनकर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बचपन में स्कूल में संत कबीर जी का एक दोहा हमें सिखाया जाता था और वह दोहा मुझे इस समय याद आ रहा है – 'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई ।' ये लोग महंगाई देखने चले थे, लेकिन इन्हें कहीं महंगाई नहीं मिली । यदि ये अपने अंदर देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि यदि इन्हें महंगाई की कहीं चिंता करनी है तो इन्हें अपने राज्यों में करनी है । आपने महंगाई की बात कही, आपने गरीबों की बात कही, आपने कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए । आपने यह भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है । सुप्रिया सुले जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने बिलकुल सही कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है । मैं बताता हूं कि पेट कैसे भरता है । मैं जाता हूं पेटो पंचायत । मैं रामपुर पंचायत जाता हूं । मैं देहर पंचायत जाता हूं । मैं अपने जिले की सभी पंचायतों में घूमता हूं और जब वहां जाता हूं तो वहीं सभी गांव, देहात के लोग कहते हैं कि हमारा पेट माननीय मोदी जी ने भरा है, हमारा पेट हमारी सरकार ने भरा है । जब से कोविड की आपदा आई है, हमने गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को मुफ्त अनाज दिलवाया और जो-जो उनकी जरूरतें थीं, उन्हें पूरा करने का प्रावधान हमने कराया । आज किसी गरीब की थाली को देखिए, शायद आज आपको वह गरीब की थाली नजर नहीं आती होगी । आप मेरे साथ झारखंड का दौरा करें । झारखंड एक अति गरीब राज्य है । आप किसी गरीब की थाली को देखिए । आप उससे पूछें कि आपको चावल के लिए क्या भाव देना पड़ रहा है, तो वह आपको बताएगा कि आज चावल मुफ्त मिल रहा है । दाल भी बहुत कम दाम में मिल रही है, मुफ्त मिल रही है । आप देखें कि जो सब्जी पहले दस-पन्द्रह रुपये की मिला करती थी, आज भी वह सब्जी आठ साल बाद दस-पन्द्रह रुपये की मिलती है और ज्यादा-से-ज्यादा आज पन्द्रह-बीस रुपये में मिलेगी । आप बताएं कि कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडे के दाम देख लें । आप आटा, दूध का दाम भी देख लें । हर वस्तु पर हमारी सरकार का अतुल्य कंट्रोल रहा है और अकल्पनीय रहा है । आपके समय ऐसा बिलकुल नहीं हो पाया था । आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं, आज गरीब की थाली वस्तुओं से भरी है ।

यह वास्तविकता है, जो आपको पसंद नहीं आयी । आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है, क्योंकि महंगाई है ही नहीं । आप आम जनता के नजरिए से देखें, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दी है और न केवल हमने थाली भरी है, हमने उसे और भी कई सारी चीजें दी हैं ।

सभापति महोदय, अभी बहन मीना जी ने बताया कि अगर आप देखें तो आज गरीब के घर में हमने बैंक खाता पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, शौचालय पहुंचा दिया, हम जल पहुंचा रहे हैं और वे पक्के घर में रह रहे हैं । जहां उनको पीड़ा थी कि अगर कोई अस्वस्थ होकर अस्पताल पहुंच जाए, तो आज उसको 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा 'आयुष्मान

भारत योजना' के माध्यम से हम दे रहे हैं । आखिर कौन-सी महंगाई, जब हमने करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपये का इतना बड़ा वरदान दिया है? आज सैचुरेशन मोड में करोड़ों लोगों को हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं । माननीय अधीर जी मौजूद हैं और उनको मालूम है । यहां सत्यपाल जी मौजूद हैं, वीडी राम जी मौजूद हैं और हम सब लोग लोक लेखा समिति के सदस्य हैं । उसी समिति में सीएजी के द्वारा गंभीरता और बड़ी महीनता के साथ जांच हुई । उन्होंने हमें बताया कि जहां एक समय किसी को एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, वहीं 'उज्ज्वला योजना' के तहत लगभग सभी को गैस सिलेंडर मिल चुके हैं । आम तौर पर 3 या 4 सिलेंडर हर वर्ष लिए जा रहे हैं । जिसके पास कुछ नहीं था, वह आज 3 या 4 गैस सिलेंडर ले रहा है । कल्याण बनर्जी साहब कह रहे थे कि सिलेंडर अलमारी में बंद हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन-सी अलमारी में बंद हैं? जब सीएजी ने जाकर देखा कि आज 3 या 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष खरीदे जा रहे हैं, तो आप ये कैसी बातें बना रहे हैं? आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको महंगाई नहीं मिल रही है । आप इस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई आपको ढूंढे नहीं मिल रही है । आपको वेल में आकर केवल नाटक करना था ।

सर, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज गरीब को महंगाई महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण ऐसा हुआ है । जरा सोचिए कि उन्होंने इस पर कितना ध्यान दिया । जब मैं वित्त मंत्रालय में था, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को यह घोषणा की कि हर घर को हम लोग जनधन खाते से जोड़ देंगे और 15 अगस्त से लेकर गणतंत्र दिवस तक हम लोगों ने सभी को बैंक खाता दे दिया और गरीबी को हम लोग इसके द्वारा मिटा रहे हैं । आपने 27 करोड़ की बात की । जब कोविड का समय आया, तो हम लोगों ने 'जनधन योजना' के द्वारा सभी के खातों में पैसे पहुंचा दिए । आपके ही नेता का ऐतिहासिक वाक्य है कि 85 परसेंट लीकेज होता था, लेकिन आज के समय लीकेज ही नहीं होता है । उनको जो लाभ मिलने चाहिए, वे लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने डीबीटी बना दिया है । जनधन को हम लोगों ने दिलवा दिया है और इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हम लोगों ने महंगाई से जनता को सुरक्षित रखा है और उनके लिए एक कवच बना दिया है । यह हम लोगों की दूरदर्शी सोच थी । मैं विपक्ष के मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जब कोविड आपदा आयी, तो हम लोगों के पास वह इन्फ्रास्ट्रक्चर था, वह फाइनेंशियल सिस्टम था कि हम हर किसी को इस कवच के द्वारा सुरक्षित रख सकें । यही वजह है कि आप जब आम जनता के बीच महंगाई ढूंढेंगे, तो वह नहीं मिलेगी, क्योंकि आज माननीय प्रधान मंत्री जी की साहसिक नीतियों के कारण हम उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं । यह मैं आम जनता के नजरिए से बता रहा हूं । किसी गरीब की थाली के नजरिये से बता रहा हूँ, उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, लेकिन हमारे विपक्ष के कई ऐसे साथी हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आंकड़ों को लाते हैं, आईएमएफ के आंकड़े लाते हैं, अन्य सभी के आंकड़े लाकर हम लोगों को बताते हैं ।

अगर हम इन आंकड़ों को देखें, जो हम लोग नहीं कह रहे हैं, यह आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, दुनिया के सब जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वे कह रहे हैं, वे बता रहे हैं और वे सब यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन आर्थिक संकटों और परिस्थितियों को संभाला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है । दो बड़े-बड़े हम लोगों को शॉक आए हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब लोगों ने स्वीकारा है और इनके बारे में कहा भी है । Once in a Century ये शॉक हैं । इस दरमियान भी हम लोगों ने जनता को सुरक्षित रखा, उनको महंगाई नहीं झेलनी पड़ी और जो कोविड के बाद जो हमारी रिकवरी हुई और यूक्रेन क्राइसिस के होते हुए भी हमारी रिकवरी हुई है, वह विश्व में एकदम टॉप में है । यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहा है । आज ग्रोथ में, जैसा अभी उदासि साहब कह रहे थे, We are the fastest growing major economy in the World despite these economic shocks.

अधीर जी, हमें रोशनी की कीमत तभी मालूम होती है जब हम अंधेरे को जानते हैं और हम सब लोगों ने यूपीए का अंधेरा देखा है । मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ । यूपीए के समय यही हालात हुए कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा, जैसा अभी शॉक आया है कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है । सब लोग बोल रहे थे कि तेल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही यूपीए के समय भी तेल का भाव 60-70 से बढ़ते-बढ़ते 100-110 होने लगा । क्या हुआ, देश में महंगाई की दर बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई । उस समय जो इंफ्लेशन था, जो महंगाई की दर थी, अब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, महंगाई की दर कितनी हुई, 10 परसेंट, 11 परसेंट, 12 परसेंट, लोग सड़कों पर आ गए । लोग सड़कों पर आ गए, तब उन्होंने महंगाई की बात रखी, तब हमें महंगाई मालूम पड़ी । अब इस बार फिर वही हालात आए हैं । आप सबको मालूम होगा । आप सब लोग अखबार पढ़ते हैं । आप सब जानकार लोग हैं । अभी भी, फिर ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा है । यह विश्व के बाजार का मामला है, यह हमारे घरेलू बाजार का मामला नहीं है । अधीर जी, यह विश्व के बाजार का मामला है । आप जानते हैं कि वही हालात हैं, फिर ऑयल का प्राइस 100-110-120 बढ़ रहा है और महंगाई की दर क्या है, 10 परसेंट है, 11 परसेंट है, 12 परसेंट है, बिल्कुल नहीं । आज के समय, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे अच्छे-अच्छे निर्णय लिए हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी रही हैं, तो आज के समय महंगाई की दर सिर्फ 7 परसेंट है । विश्व में आज के समय क्या है, यूएस में क्या है? उस समय, यूपीए के समय अंधेरे में थे, वह हमारे देश में अंधेरे का जमाना था, हमारे यहाँ 12 परसेंट इंफ्लेशन था, अमेरिका और यूरोप में क्या इंफ्लेशन था, वहाँ दो परसेंट इंफ्लेशन था, एक परसेंट, तीन परसेंट इंफ्लेशन था । आज यूरोप में और यूएस में इंफ्लेशन क्या है, आज वहाँ 8 परसेंट और 9 परसेंट इंफ्लेशन है और हमारे यहाँ उनसे कम इंफ्लेशन है, हमारे यहाँ 7 परसेंट इंफ्लेशन है । यह यूपीए के अंधेरे को और एनडीए की रोशनी को साफ दर्शाता है ।

कुशलता क्या है, योग्यता क्या है, ये आंकड़े आपको साफ बता रहे हैं । मैंने थाली की भी बात की, मैंने आंकड़ों की भी बात की, क्योंकि जहाँ भी आप महंगाई खोजेंगे, थाली में खोजेंगे, आंकड़ों में खोजेंगे, आपको कहीं भी महंगाई नहीं मिलेगी । यह सिर्फ आप चाहते हैं । ऐसा क्यों है?

हमारी कई नीतियाँ थीं । हमने ड्यूटी कम की, हमने एडिबल ऑयल पर ड्यूटी कम की, हमने सोयाबीन पर ड्यूटी कम की, हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल का एक्साइज टैक्स घटाया, हम लोगों ने बहुत सारी नीतियाँ अपनायीं । हम लोगों ने बहुत सारे साहसिक कदम लिये, ठोस कदम लिये और तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं । जो आप यूपीए सरकार में नहीं कर पाए, वह हम लोगों ने आपको करके दिखाया है । जो ग्रोथ की बात हो रही है, मैं विपक्ष के सभी साथियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आज ही जीएसटी के आंकड़े आए हैं । आप लोग कह रहे हैं कि जीएसटी में यह सब गलत काम किया गया है, उस जीएसटी के आंकड़े आए हैं । आज जुलाई माह का 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का कलेक्शन है । आज एक अगस्त है और यह जुलाई माह का दिया गया है । इसमें यह मत समझिए कि यह इंफ्लेशन, महंगाई के कारण है । जीएसटी टू जीडीपी रेश्यो, जो बहुत महत्वपूर्ण रेश्यो होता है, क्योंकि हमारी कम्प्लायंस और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है, वह 6.9 परसेंट हो गया है । यह आपको बताता है कि हम लोग किस कुशलता से अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं ।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें महंगाई की चिंता करनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए हम लोग अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि हमें आज के समय महंगाई के बारे में कोई खास चिंता नहीं करनी चाहिए । अधीर जी, अगर चिंता करनी है तो हमें आपकी चिंता करनी है, आप लोगों की चिंता करनी है, क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है, सिखाया है कि रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग हैं । इस देश में बहुत सारे रेवड़ी वाले भी घूम रहे हैं । आपका कोलकाता आना-जाना है । आपको मालूम है कि वहां संदेश भी मिल रहा है, रसगुल्ला भी दिया जा रहा है, मिस्टी दोई भी दी जा रही है । ये रेवड़ी वाले बहुत हैं । हमारे राजस्थान में भी कई सारे मित्र हैं । मीणा जी हैं, आपको मालूम है कि वहां जयपुर में भी चूरमा बनाया जा रहा है, उसमें घी और शक्कर डाली जा रही है । उसको चूर-चूर कर चूरमा खिलाया जा रहा है । दिल्ली वालों को एक ऐसा हलवाई मिला है, जो जलेबी ही तलता रहता है । वह जलेबी की उस कढ़ाई को लेकर पंजाब पहुंच गया है और अमृतसर में भी जलेबी खिलाने वाला है । अब, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, वही कढ़ाई लेकर जलेबी वाला गुजरात घूम रहा है, हिमाचल घूम रहा है जलेबी खिलाने के लिए । साथियो, अगर हमें चिंता करनी है, तो उन संदेश वालों की, उन चूरमा वालों की, उन जलेबी वालों की, उन रेवड़ी वालों की, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं । यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधान

मंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं । वे हमें सुरक्षित रखेंगे । मैं अंत में एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए ।

श्री जयंत सिन्हा : सोशल सिक्योरिटी को माननीय प्रेजीडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट जी ने अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया था । उसके द्वारा मेडिकेयर और मेडिकऐड आया । फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट इतने लोकप्रिय हो गए कि एक चुनाव नहीं, दूसरा चुनाव जीते, तीसरा चुनाव जीते और उनकी इतनी लोकप्रियता थी कि उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर हमें उनको जीतने नहीं देना है तो हमें टर्म लिमिट्स लानी पड़ेगी । अगर हम भारत में भी टर्म लिमिट्स लाएंगे, तभी जाकर कोई माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री पद से हटायेगा । नहीं तो यह देश की जनता उनको हरदम उस पद पर देखना चाहती है और जलेबी वालों से हमें सुरक्षित रखना चाहती है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m32 श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

यह बात समझ से बाहर है कि सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दे पर बड़ी हठधर्मिता से आज तक बहस टाल दी । यही बहस जो आज इस हाउस में हो रही है, वह आज से दो हफ्ते पहले 18 तारीख या 19 तारीख को हो सकती थी । हाउस का जो वक्त जाया हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब महंगाई पर बात हुई तो इससे किसी को इंकार नहीं है कि मुल्क की आवाम को कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है । होना यह चाहिए था कि जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, वे बड़ी साफगोई से यह मानते हैं कि हां, महंगाई का सामना आवाम को है और उसके लिए उपाय क्या है, वे उनकी तजवीज़ देते । लेकिन यहां बड़ी हठधर्मिता से उसको नकारा ही जाता है या उसके लिए ऐसा जवाज़ दिया जा रहा है, जिस जवाज़ की कहीं पर बुनियाद ही नहीं है ।

जनाब, इनके जो आंकड़े हैं, जो एनएसएसओ के फिगर्स हैं, इंफ्लेशन 7.4 परसेंट है, जो सीपीआई इंफ्लेशन है । टोलरेंस लेवल 6 परसेंट है । ये खुद ही मानते हैं कि हां, जो सीपीआई की इंफ्लेशन है, वह इंफ्लेशन जो होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा है । होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कहना चाहता हूं । जो आंकड़े हाउस में दोहराये गए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा । होलसेल प्राइस इंडेक्स की इंफ्लेशन 15.88 परसेंट है । यह इस साल की बढ़ोतरी नहीं है, यह पिछले तीस साल में सबसे ज्यादा है । पिछले दशक से इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, बीते हुए सालों में वह 13.11 परसेंट के करीब थी । इस सारे पसे मंज़र में यह कहना कि इंफ्लेशन या महंगाई कहीं है ही नहीं, वह आपको कहीं मिलेगी नहीं । वह बेसलैस है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है । यह इंफ्लेशन क्यों हुई और कहा जा रहा

है कि जो भी उपाय किए गए, जो भी कदम उठाए गए, सारे विश्व में, सारी दुनिया में और सारे मुल्क में उसकी सराहना की जा रही है । डिमोनेटाइजेशन को मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी एक डिजास्टर माना गया है । यह पहला कदम था, जो मुल्क की मईशत के खिलाफ था । इसके जो असरात थे, उससे आज तक हम जूझ रहे थे । उसके बाद और कदम उठाए गए, जैसे फार्म लॉज़ और जो मिस-एलोकेशन ऑफ प्रिशियस रिसोर्सेस हैं, उनकी बात हुई । जो पैसा लगाना चाहिए था, वह जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर लगाना चाहिए था । वह ऐसे मुद्दों पर लगाया गया और अपनी सिर्फ ego hassles की वजह से लगाया गया ।

जनाब, दूसरी बात जीएसटी की है । जीएसटी की बुनियाद ही इसलिए पड़ी ताकि ये सारे रिसोर्ससेज़ सेंट्रलाइज़ हो जाएं । अब यह सूरत-ए-हाल हो गया है कि जैसे जम्मू-कश्मीर में सन् 1947 से पहले आमरियत का ज़माना था, क्रेडल से ग्रेव तक, जन्म से शमशान तक हर चीज़ पर टैक्स आयद की जाती थी, जो आमरियत थी, उस निज़ाम में बच्चे के पैदा होने से ले कर जब तक वह इंसान रुख़सत नहीं हो जाता था, तब तक हर मरले पर, हर दिन टैक्स लगता था । वही मिसाल आज इस सरकार से मिलती है । अब ये कहते हैं कि कहीं पर मंहगाई नहीं है, कहीं पर टैक्स नहीं है । आपने एक इरेज़र पर टैक्स लगाया है, आपने एक एलईडी बल्ब पर टैक्स लगाया है, आपने पैक्ड फूड पर टैक्स लगाया है । टैक्स की ऐसी रिजीम कहीं आपको मिलती है?

आप इतिहास में देख लीजिए । हम उनसे यह बात सुन रहे हैं, जो बड़े विद्वान माने जाते हैं, जिनकी अपनी एक हैसियत है, अपना एक रुतबा है । वहां तवक्को नहीं थी, ऐसी बातें सुनने का । जनाब, जम्मू-कश्मीर की बात कुछ अलग है । जनाब, कोई 61,000 के करीब फैमलीज़ में ऐसे एम्पलॉइज़ हैं, ऐसे वर्कर, ऐसा वर्कफोर्स है, जो अंडर पेड है, अंडर एम्पलॉइड है । जनाब, उनको कम्पार्टमेंट्स में बांटा गया है । किसी को कहा गया है कि आप कैजुअल वर्कर हो, कोई नीड बेस्ड वर्कर है । ऐसे 61,000 के करीब हैं, जहां मिनिमम वेज़िस भी नहीं मिल रहे हैं । जनाब, जो मंहगाई का असर है, आप उनकी नज़र से देखिए । जनाब, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि वहां पर एक होमगार्ड को 2700 रुपये महीने के मिलते हैं । वही होमगार्ड जिसने अभी अमरनाथ में बचाव कार्यवाही की है, जिसने इंसानी जानें बचाई हैं, जबकि दिल्ली में एक होमगार्ड को 22,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, वहां पर 61,000 के करीब ऐसे लोग हैं, जिनको मिनिमम वेजिस से कम मिलता है । जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के नाम से जाने जाते हैं, कॉलेज डेवल्पमेंट फंड के नाम से जाने जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स, नीडबेस्ड वर्कर्स या बाकी जो वर्कर्स हैं । ... (व्यवधान) जनाब, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी उनको है, जो रैग्युलराइजेशन का वेट कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां मुस्तकिल नहीं हो रही हैं । जनाब, सीआईसी के मुलाज़मीन हैं, रूरल डेवल्पमेंट के मुलाज़मीन हैं, बाकी मुलाज़मीन हैं, जिन पर ज्यादा मंहगाई की और भी

ज्यादा मार है, क्योंकि वे अंडरपेड हैं, उनको वह नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए । जनाब, इसका उपाय क्या है? सरकार को करना क्या चाहिए । हम तवक्को करते हैं कि जब जवाब दिया जाएगा, तब उपाय के बारें में बात की जाएगी । अभी तो यह नकारते हैं, कहते हैं कि महंगाई आपको मिलेगी नहीं । जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो अभी ताज़ा टैक्स हरेक चीज़ पर लगाए हैं, वह सारा डिसीज़न आप रिवर्स कीजिए । आप तो फार्म लॉज़ को इतना डिफेंड करते थे, फिर आपको जब रियलाइज़ हो गया कि यह चलने वाली बात नहीं है, तो फिर कैसे आपने वे अनडू किए? जनाब, महंगाई कम हो जाएगी, पहले आपने जो टैक्स लगाए हैं, उनको खत्म कीजिए । जिससे मुतासिर हैं सबसे निचला तबका, ऊपर वाला तबका नहीं, समाज का सबसे निचला तबका मुतासिर है, जो नए टैक्स आपने लगाए हैं, इस महंगाई से वह मुतासिर है । जब तक आप उसको रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक इस महंगाई का असर जो है, निचले तबके पर है, डिसएम्पावर्ड पर है, सोसाइटी का अनअटैंडिड पर्सन पर है, तब तक वह कम नहीं होगा । जनाब, आम मुल्क में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जो ये 61,000 के करीब फैमलीज़ हैं, वर्कर्स हैं, जिस मुल्क में जो पॉवर्टी लाइन है, ख़ते इफलास है, उससे नीचे 30 फीसदी आबादी रह रही हो, वहां मार्केट फोर्सेज़ पर ये मामले नहीं छोड़े जाते हैं । वहां पर आपको इंटरवीन कर के उनको राहत देनी है । जो हमारा सिस्टम है, जिसकी कल्पना आईन में की गई है, उस सिस्टम में गरीबों के लिए जो अफिरमेटिव एक्शन की बात है, उसकी गुंजाइश मौजूद है । नंबर दो, जब तक फ्यूल और गैस की प्राइस कम नहीं होगी, उस पर कई गुना ड्यूटीज़ लगी हुई हैं । आप उन ड्यूटीज़ के नाम पर खुद अपने लिए रिज़र्व करते हैं और स्टेट्स को उनका हिस्सा देते नहीं हैं । वह अलग बात है, लेकिन जब तक आप वह नहीं करेंगे, तब तक यह जो महंगाई की सतह है, लैवल है, यह लैवल कम नहीं होगा । वह राहत नहीं होगी, जो हमारा डिसएम्पॉवर्ड, अनअटैंडेड और डाउनट्रोडन सैक्शन चाहता है ।

HON. CHAIRPERSON: Now, it is already 6 o'clock. If the House agrees, we will extend the time till the debate or this subject matter is over. Do you want reply today itself?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The House is extended till the conclusion of the debate.

18.00 hrs

***m33 *SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): I thank you, Hon. Sir, for giving me the opportunity to speak on the important issue of price rise. For two weeks, the proceedings of the House remained suspended. Crores of rupees of exchequer were lost in the process. Only then did the Government**

agree to have discussions on the issue of price rise. On 17th of last month, during the all party meeting, it had been decided that price rise must be discussed in the House. But, the Government refused to let the discussion on this issue take place. At least, now we are discussing this important issue and I am happy about this.

<u>18.01 hrs</u> **(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)**

Sir, tall talk from all sides is the order of the day. The treasury benches say that there is no inflation and price rise. They make fun of this fact. The Government is sprinkling salt on the wounds of poor people. Congress makes tall promises regarding waiver of loans of farmers. The present Government makes tall claims regarding doubling the income of farmers. However, the ground reality remains dismal. This is what they said in 2015. 2022 has come and situation is critical. Now, they talk about the tricolor flag. Where are the farmers whose income has been doubled?

The farmers are in a miserable state today. I hail from Punjab. The Central Government had said that ration is being given to the poor. But, why are the poor people suffering. During Covid, we had seen the crumbling of Government infrastructure. The farmers of Punjab continued to fill the Central pool with foodgrains by the dint of their sweat and blood. However, these farmers of Punjab are in a miserable condition. Spurious seeds of pulses and sunflower have wreaked havoc. Paddy crops, wheat crops are being damaged due to various reasons. But, the Central and State Governments do not take any action against the guilty shopkeepers or companies.

We talk about Swaminathan Committee Report that it will be implemented. However, a cruel joke is being played against the farmers. Promises were made regarding constituting a Committee on MSP. An agitation was launched by farmers. 700 hapless farmers lost their lives. They became martyrs. However, when the Committee on MSP was set up in 2021, it failed to deliver justice. Farmers withdrew their agitation. At that time, the agreement said:

'यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एस.के.एम. के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे । कमेटी का एक मैनडेट यह होगा कि देश के किसानों को एम.एस.पी. मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए ।'

My Hindi may not be up to the mark but this is what is written here. When the Gazette was issued in 2022, all 26 Members who had been included in the Committee were those who had supported the black, draconian laws. Farmers have rejected that Committee. Tall claims are made 'to make the MSP more effective and transparent'. But, it is far removed from reality.

The Central Government claims that there is no inflation or price rise. Why doesn't the Government tell what is the price of diesel, seeds, medicines etc.? Prices of all essential commodities are going through the roof. When petrol and diesel prices soar, it has a cascading effect on all items. Input cost of cultivation increases. There is 100% increase in cost of everything in the last eight years. MSP is hardly increased by 2%. What an irony!. Diesel, petrol, seeds, fertilizers, urea etc. – the cost of all these items increased by 100% but MSP is increased by a paltry 2%. This is a cruel joke perpetrated against the farmers.

Government says that things are rosy. There is no problem. However, the poor and farmers are finding it difficult to make both ends meet. Farmers cannot send their children to schools. Poor people cannot get treatment in a good hospital. What a sorry state of affairs that Government is patting its back and has turned a deaf ear and a blind eye towards the plight of poor and farmers. I am pained. I demand that the Swaminathan Commission Report must be implemented. Promises made must be fulfilled. GST is being imposed on items like curd and rice.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Please give me two minutes, Sir, you are imposing GST on everything. The farmers must get their rights. It is very unfortunate that this Government says that there is no inflation and price-rise. The poor people are finding it difficult to make both ends meet. I do hope that the Government will take tangible steps to meet the crisis of inflation and price rise and provide relief and succor to the common man.

Thank you.

*m34 श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूँ, देश की माताएँ आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया । देश का वह ट्रक ड्राइवर, जो नौजवान है, आपसे सवाल कर रहा है कि उसकी आमदनी वर्ष 2014 से नहीं बढ़ी, मगर उसके खर्चें डबल हो गए । देश का वह प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वह दो साल से बेरोजगार है । वह कोविड-19 से कर्ज़ों में डूब चुका और गैस का एक सिलिंडर भी नहीं खरीद सकता । देश की 50 फीसदी आबादी जो नौजवानों की है, वह मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि हम 50 फीसद तो हैं, मगर 28 फीसद बेरोज़गार क्यों हैं? आपने हमारा मुकद्दर बेरोज़गार क्यों बना कर रख दिया ।

सर, आज देश की आंगनवाड़ी वर्कर्स मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं कि हम महीने के साढ़े चार हजार रुपये में कैसे जिंदगी गुजारेंगे । साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स बन कर रहें । देश की माताएँ मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं कि उज्ज्वला योजना की सिलिंडर की कीमत जो वर्ष 2015 में थी, वह आज डबल हो गई । आज वे सिलिंडर की रीफिल नहीं करा पा रही हैं ।

सर, गरीब घरों की महिलाएँ देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रॉसरिज़ थी, उसमें 68 परसेंट का इजाफा क्यों हो गया, क्या मोदी सरकार को उसकी खबर है? आज इस देश का मज़दूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वर्ष 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22 फीसद का इज़ाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ इसेन्शियल और फूड आइटम में 50 फीसद इज़ाफा हुआ है ।

सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहा है कि मेरे बच्चे रात में भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलिनियर्स पैदा हो गए । गरीब का पैसा कब तक बिलिनियर को जाएगा, वह गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है । देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह में इज़ाफा नहीं होता । पीएलएफ सर्वे कहता है कि आज 42 परसेंट से 45.6 परसेंट नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं । क्या मोदी सरकार जानती है कि मनरेगा में फाइनैंशियल ईयर 2022 के इन आठ महीनों में नौ मिलियन लोग काम कर रहे हैं । क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताती है? आपने अब तक 15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपये का बकाया नहीं दिया ।

सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने आठ साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आप अग्निवीर को लायें । आज उस सिपाही का दिल टूटा हुआ है, जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आँखों में आँख डाल कर खड़ा था । आपने

इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और देश के नौजवानों को अग्निवीर का मुकद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है ।

देश के मासूम बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारी किताबों, पेंसिल और पेन पर 18 फीसद जीएसटी क्यों लगा दिया?

सर, देश के इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6 परसेंट के दरम्यान होगा, आखिर वह क्यों 7 परसेंट हो गया और डब्ल्यूपीआई 15 परसेंट हो गया ।

सर, देश के 40 करोड़ गरीब लोग देश के प्रधानमंत्री को खुल कर जवाब दे रहे हैं और पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इन्फ्लैशन करप्शन के बराबर है । वह 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है । इन्फ्लैशन उनकी नज़र में करप्शन है ।

सर, देश का वह गरीब आदमी जो 95 फीसद एफडीज़ में डालता था, वह देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से और 7 परसेंट इन्फ्लैशन की वजह से उनको 3.5 परसेंट पर-एनम लॉस हो रहा है । वहीं पर देश के गरीब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि हम आपकी गलत पॉलिसी की वजह से आटा, बिस्कुट, टूथपेस्ट कम खरीद रहे हैं । देश के वे लोग जो कर्ज़ों पर घर और गाड़ी लिये थे, उनके लोन में एक परसेंट का इज़ाफा हो गया ।

आपकी तरफ से, गलत पॉलिसीज़ की वजह से आरबीआई ने 0.9 पर्सेंट बढ़ाया तो बैंक्स ने 1 पर्सेंट बढ़ा दिया । इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डिफॉल्टर्स के 1,45,240 करोड़ रुपये बैड लोन के लिए राइट ऑफ कर दिए । देश का गरीब देश के प्रधान मंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वह कौन सा बड़ा सरमायदार है, जिसका नाम 'ए' से शुरू होता है, 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाते हैं, 12 हजार करोड़ रुपये दिए जाते हैं, एनपीए होता है । कब तक यह स्कैम होगा, देश को आप ...* बनाते रहेंगे? FD rates have risen by 0.1 per cent, but banks are charging 0.8 per cent. What is this?

मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, "यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है ।" मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया ।

आपने गरीबों के पूरे रास्ते बंद कर दिए । शायर ने देश के प्रधान मंत्री के बारे में सही ही कहा था कि ‘ जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर’ ।

सर, यह इनकी पॉलिसी है । यह मोदी सरकार की पॉलिसी है । देख लीजिए, सिर्फ पचास एमपीज़ बैठे हैं । इनको प्राइस राइज़ से मतलब नहीं है । देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए । आपको समझना पड़ेगा कि आज गरीब इस सरकार से मायूस है ।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ میں مودی سرکار سےجاننا چاہتا ہوں، ملک کی ماتائیں آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے معصوم بچوں کو دودھ اور انڈوں سے کیوں محروم کر دیا ہے۔ ملک کا وہ ٹرک ڈرائیور جو نوجوان ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اس کی آمدنی سال 2014 سے نہیں بڑھی، مگر اس کے خرچے ڈبل ہو گئے ہیں۔ ملک کا وہ پلمبر مودی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ وہ دو سال سے بے روزگار ہے۔ وہ کووِڈ 19 سے قرضوں میں ڈوب چکا ہے اور گیس کا ایک سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا۔ ملک کی 50 فیصد آبادی جو نوجوانوں کی ہے، وہ مودی سرکار سےسوال کر رہی ہے کہ ہم 50 فیصد تو ہیں، مگر 28 فیصد بے روزگار کیوں ہیں؟ آپ نے ہمارا مقدر بے روزگار کیوں بنا کر رکھ دیا ۔

جناب، آج ملک کی آنگن واڑی ملازمیں مودی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم 4500 روپے میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کہ کہا جاتا ہے کہ فرنٹ لائن ورکر بن کر رہیں۔ ۔ ملک کی ماتائیں مودی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ اُججولا یوجنا کی سلینڈر کی قیمت جو سال 2015 میں تھی، وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ آج وہ سلینڈر کی ریفِل نہیں کرا پا رہی ہیں۔

سر، غریب گھروں کی خواتین ملک کے وزیرِ اعظم سے سوال کر رہی ہیں کہ جو کاسٹ آف بیسِک گروسریز تھی، اس میں 68 فیصد کا اضافہ کیوں ہو گیا ہے، کیا مودی سرکار کو اس کی خبر ہے؟ آج ملک کا مزدور مودی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ سال 2015 سے اس کی تنخواہوں میں صرف 22 فیصد کا اضافہ ہوا ہے، مگر پرائس آف ایسینشیل اور فوڈ آئٹم میں 50 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔

سر، ملک کا غریب جو آج بھوکا سو رہا ہے۔ وہ ملک کے وزیرِ اعظم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بچے رات میں بھوکے سوتے ہیں، مگر ملک میں 215 بلینیرس پیدا ہو گئے۔ غریب کا پیسہ کب تک بلینیر ہو جائے گا، وہ غریب مودی سرکار سے سوال کر رہا ہے۔ ملک کا نوجوان مودی سرکار سے سوال کر رہا ہے، کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں لیکن میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پی۔ایل۔ایف۔ سروے کہتا ہے کہ آج 42 فیصد سے 45.6 فیصد نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ کیا مودی سرکار جانتی ہے کہ مودی سرکار منریگا میں فائننیشیل ایر 2022 کےان آٹھ مہینوں میں نو ملین لوگ کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایک ایکونامی اچھی ہے؟ کیا یہ ایکونامی کی بربادی کو بتاتی ہے؟ آپ نے اب تک 15 ریاستوں کو 4700 کروڑ روپئے کا بقایہ نہیں دیا۔

سر، وہی ایک فوجی ٹوٹے دل کے ساتھ ملک کے وزیرِ اعظم سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں ملک کی ایکونامی کو برباد کر دیا، اس لئے آپ نے اگنی ویر کو لایا۔ آج اس سپاہی کا دِل ٹوٹا ہوا ہے، جس نے اپنی جوانی چین اور پاکستان کی فوجوں کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے ایکونامی کو برباد کر دیا اور ملک کے نوجوانوں کو اگنی ویر کا مقدر بنا کر ملک کی حفاظت سے کھلواڑ کیا ہے۔ ملک کے معصوم بچے جو اسکول جاتے ہیں، ملک کے وزیرِ اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ پردھان منتری جی آپ نے ہماری کتابوں، پینسل اور پین پر 18 فیصد جی۔ایس۔ٹی۔ کیوں لگا دیا؟

سر، ملک کی ایکونامی کے ایکسپرٹ وزیرِ اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قانون بنایا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس 2 اور 6 فیصد کے درمیان ہوگا، آخر وہ کیوں 7 فیصد ہو گیا اور ڈبلیو۔پی۔آئی۔ 15

فیصد ہو گیا۔

سر، ملک کے 40 کروڑ غریب لوگ ملک کے وزیرِ اعظم کو کھُل کر جواب دے رہے ہیں اور پیظام پہنچا رہے ہیں کہ انفلیشن کرپشن کے برابر ہے۔ وہ 40 کروڑ غریب ملک کےوزیرِ اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار اور یو۔پی۔اے۔ کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انفلیشن ان کی نظر میں کرپشن ہے۔

سر، ملک کا وہ غریب آدمی جو 95 فیصد ایف۔ڈیز میں ڈالتا تھا۔ وہ ملک کے وزیرِ اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کے غلط فیصلوں سے اور 7 فیصد انفلیشن کی وجہ سے ان کو 3.5 فیصد پر اینم لاس ہو رہا ہے۔ وہی پر ملک کے غریب لوگ وزیرِ اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے آٹا، بسکٹ، ٹوتھ پیسٹ کم خرید رہے ہیں۔ ملک کے وہ لوگ جو قرضوں پر گھر اور گاڑی لئے تھے، ان کے لون میں ایک فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے۔

آپ کی طرف سے، غلط پالیسیز کی وجہ سے آر۔بی۔آئی۔ نے 0.9 فیصد بڑھایا تو بینکس نے 1 فیصد بڑھا دیا۔ اس ملک کا کسان مودی سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ 31 پیسے کے لئے مجھے اسٹیٹ بینک آف اندیا این۔او۔سی۔ نہیں دیتا ہے، مگر آپ کی سرکار نے ایسے ایسے بڑے بڑے ڈیفالٹرس کے 145240 کروڑ روپئےبیڈ لون کے لئے رائٹ آف کر دئے۔ ملک کا غریب ملک کے وزیرِ اعظم سے پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ کونسا بڑا سرمایہ دارہے، جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، 14 ہزار کروڑ روپئے دئے جاتے ہیں، 12 ہزار کروڑ روپئے دئے جاتے ہیں، این۔پی۔اے ہوتا ہے۔ کب تک یہ اسکیم ہوگا، ملک کو آپ (کاروائی میں شامل نہیں) بناتے رہیں گے۔ **FD rates have risen by 0.1 per cent, but banks are charging 0.8 percent. What is this?**

میں ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فائننس منسٹر نے کسی ایک بجٹ اسپیچ میں ایک شعر پڑھا تھا،

یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے۔
ہوا کی اوٹ بھی لیکر چراغ جلتا ہے

میں کہنا چاہوں گا کہ فائننس منسٹر صاحبہ، آپ نے غریب کے چراغ کو گُل کردیا، آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں اضافہ کر دیا، آپ نے غریبوں کے پورے راستے بند کر دئے۔ کسے شاعر نے ملک کے وزیرِ اعظم کے بارے میں سہی کہا تھا کہ

جو کہتا تھا کہ تارے توڑ کر لاؤنگا

اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پر

سر، یہ ان کی پالیسی ہے۔ یہ مودی سرکار کی پالیسی ہے۔ دیکھ لیجئے، صرف 50 ایم پیز بیٹھے ہیں۔ ان کو پرائس رائز سے مطلب نہیں ہے۔ ملک کی عوام کا آکروش سمجھئے، غصّہ سمجھئے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج غریب اس سرکار سے مایوس ہے۔

(ختم شد)]

*m35 श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): सभापति जी, आपने मुझे आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं नया सांसद हूं । मुझे पहली बार संसद में आने का मौका मिला । आज इतना बड़ा मुद्दा, हम सबके घरों में जिसका असर पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं । मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि कौन क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? यहां प्राइस राइज़ के ऊपर सदस्यों द्वारा बोला गया । पूरे सैशन में हमने देखा कि विपक्ष ने प्राइस राइज़ के ऊपर डिस्कशन की मांग की और आज इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है ।

मैं नया सांसद हूं । मुझे ऐसा लगता था कि यहां डिस्कशन होगी । यहां बहुत ही विद्वान लोग हैं और जब यहां डिस्कशन होगी, तो उससे एक निष्कर्ष निकलकर आएगा कि कैसे हम लोग प्राइस राइज़ को कंट्रोल करेंगे, कैसे लोगों को राहत देंगे, यहां पर टेक्निकल या कुछ अच्छे सुझाव के बारे में भी हमें सुनने का मौका मिलेगा । जब हमने सुना तो हमें ऐसा लगा कि यहां पर तो इंटेंशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है । मोदी सरकार की इंटेंशन क्या है? ऐसे प्रधान मंत्री, जिनका कोई परिवार नहीं, देश ही उनका परिवार है । उनकी पर्सनल कोई चीज नहीं है । वे देश के लिए काम करने वाले प्रधान मंत्री हैं । उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है । ऐसे प्रधान मंत्री के ऊपर क्वैश्चन हम लोग देख रहे थे । मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसे देश में हैं, जिस देश में वर्ष 2014 के बाद ही सारी प्रॉब्लम हुई । वर्ष 2014 के पहले देश में इतनी खुशहाली थी, इतना बढ़िया था, पूरा सिस्टम इतना सिस्टमैटिक था, फिर वर्ष 2014 के बाद ही सारा खराब हो गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया, लोगों को बहुत परेशानी हो गई, फ्यूल प्राइस बढ़ गया, पूरे देश में बहुत खराब माहौल बन गया और उससे पहले तो बहुत ही अच्छा था । हम लोग जब कम उम्र में उस टाइम को देख रहे थे, तब देश तो बहुत खुशहाल था । उस टाइम तो प्राइस राइज़ भी नहीं था, इनफ्लेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद ही सारा सिस्टम हो गया । वर्ष 2014 के बाद हम एक कम्परैटिव स्टेटमेंट देखते हैं । फ्यूल प्राइस के ऊपर जयंत सिन्हा जी और निशिकांत दुबे जी ने बहुत बढ़िया तरीके से और जसकौर मीना जी ने बहुत सुंदर तरीके से आंकड़ों को रखा ।

मैं दो-तीन पाइंट ही प्राइस राइज के ऊपर आपके सामने रखना चाहूंगा, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा । मैं यही बोलना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद असेसमेंट करें तो हम पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ लोगों को दे रहे हैं । उससे पहले किसानों को यह पैसा मिलेगा, ऐसा हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, 2.95 करोड़ लोगों को घर दिया जाता है, यह कहां से पैसा लाकर दिया जा रहा है । मनरेगा में हम लोग 100 दिन का काम देने की व्यवस्था कर रहे हैं । स्वच्छ भारत के अंदर हम लोग 377

मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं । वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रप्स को, 28 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 65 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं । जनधन एकाउंट में सभी को पैसा देते हैं ।

एग्रीकल्चर में व्हीट प्रोक्योरमेंट और पैडी प्रोक्योरमेंट देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जब हम लोगों का पैडी प्रोक्योरमेंट 433 लाख मिट्रिक टन हो गया, 5 लाख फार्मर्स को व्हीट प्रोक्योरमेंट में बेनिफिट हुआ है । पैडी प्रोक्योरमेंट में 900 लाख मिट्रिक टन और 1.5 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है । यह पैसा किसके घर में जा रहा है? यह पैसा गरीब के घर में जा रहा है या अमीर के घर में जा रहा है? पीएमएवाई से किसका घर बन रहा है, गरीब का बन रहा है या अमीर का बन रहा है? फार्मर को पैसा दे रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं? जन धन एकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं?

हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, मुफ्त का चावल दे रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं? हम अमीर को दे रहे हैं या गरीब को दे रहे हैं? यह सरकार देश के सभी गरीब नागरिकों के लिए काम कर रही है । जब प्राइस राइज होता है तो सभी को कष्ट होता है । हम भी ऐसा कभी नहीं चाहते हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिन्हें देश ने 304 सांसद देकर सेवा करने का मौका दिया है, उनको परेशानी हो, कष्ट हो, इसके लिए हम लोग काम नहीं करेंगे । कैसे सेवा करेंगे, कैसे अच्छी तरह से काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे ।

हमें उम्मीद हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई आएगा तो उस रिप्लाई में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, देश में प्राइस राइज के मुद्दे पर हम लोग पहले काम करेंगे, उसके ऊपर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर मिलेगा । यही मैं उम्मीद करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m36 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज सदन में बढ़ी हुई महंगाई से आम लोगों के जीवन पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है । 18 तारीख से लेकर आज तक यानी, 10 दिन का समय पक्ष-विपक्ष ने खराब किए, जहां करोड़ों रुपये खर्च लोक सभा को चलाने के लिए हो रहे हैं । देश का नौजवान और किसान लोक सभा की ओर देखता है कि सत्र कब चलेगा, कब सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी । इस बात में 10 दिन गवां दिए, विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष ने भी दो दिन खराब किए कि राष्ट्रपति की बात को लेकर माफी मांगे ।

मैं लोक सभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बीच-बचाव करके सदन को चलाया । आज पूरा देश इस ओर देख रहा है कि महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है ।

सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से सदन में महंगाई पर चर्चा करने की मांग की गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपना पक्ष रखा । सत्ता और विपक्ष के साथियों ने महंगाई को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए । सत्ता पक्ष की तरफ से मैं देख रहा था कि कई लोग बड़ी लंबी तैयारी के साथ आए थे कि मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार होने वाला है, कई लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया । मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, हो सकता है वे मंत्रिमंडल के अंदर आ जाएं । यह चर्चा महंगाई पर तभी सार्थक साबित होगी, जब सरकार देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएगी और सदन के सदस्यों के सुझावों पर अमल करेगी ।

पंजाब से आने वाले पूर्व मंत्री चिंता ने जाहिर की है । किसानों का आंदोलन देश का सबसे बड़ा था, ऐतिहासिक आंदोलन था । 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि के तीनों काले कानून वापस लिए । तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी और तमाम फसलों को एमएसपी दायरे में लेने की बात हुई थी । यह किसानों की बहुत बड़ी मांग थी, जायज मांग थी । इसे लेकर कमेटी बनाई गई और इसे एमएसपी में दायरे में लाने की बात हुई । लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने इस ओर अभी भी ध्यान नहीं दिया । मेरी मांग है कि सरकार स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट लागू करे । किसानों के जितने भी मुद्दे थे, जिसे लेकर किसान आंदोलित थे, तीनों कृषि बिलों को वापस लेने के साथ ही सरकार ने आश्वासन भी दिया था, सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए था । सरकार को किसानों से किए गए वायदे पर खरा उतरना चाहिए ।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने जिस स्तर को छुआ, इससे निर्धन और मध्यम वर्ग के तबकों पर खराब असर पड़ा है, यह चिंताजनक बात है । वर्ष 2009 से कांग्रेस का कार्यकाल था । यूपीए सरकार के कार्यकाल में बहुत ज्यादा महंगाई थी, तब भाजपा ने नारा दिया था – 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ।' देश की जनता ने दो बार भरोसा करके एनडीए सत्ता को काबिज करवाया । पिछली बार तो मैं भी एनडीए में आपके साथ था । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hanuman Beniwal *Ji*, please wind up.

श्री हनुमान बेनीवाल : वर्तमान सरकार ने अभी भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए । मैं एक समचार पत्र में लिखी बात दोहरा रहा हूं - घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है और कर का बोझ उस वर्ग पर डाला जा रहा है, जिसके हाथ में करने के लिए काम नहीं है, जिसकी जेब और पेट खाली है, उस वर्ग को कर में छूट दी जा रही है, जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं । यह बात काफी हद तक सही भी है । ऐसे में आमदनी बगैर अर्थव्यवस्था और पानी बगैर नदी की कल्पना करना बेईमानी है । स्रोत सूख गए तो

समझ लें कि दोनों का अस्तित्व संकट में है । हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इसी दिशा में बढ़ रही है । जाहिर है कि देश की मौजूदा आर्थिक नीतियों आम जन के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के जो हालात हैं, जिस तरह से गरीबी का दायरा बढ़ रहा है, यह चिंताजनक है और साथ ही प्रतिकूल नीतियों के कारण बाजार में मांग नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ रही है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. What is your final point?

श्री हनुमान बेनीवाल: दो मिनट दीजिए ।

महोदय, निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण वास्तव में भारत में सभी वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ा है और जिसका वस्तुओं के आयातकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखने को मिली और यह सही है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा और रूस, यूक्रेन के युद्ध से भी असर पड़ा । कोरोना की बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कब तक देश की जनता को महंगाई की आग में धकेलते रहेंगे? इस बात पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा ।

सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि देश में महंगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है जिससे आम लोगों का जीना दूर्भर हो गया है । पेट्रोल, डीजल से लेकर फल, सब्जियां और गैस सभी के दाम आसमान पर हैं, इनकी दरें बढ़ने से प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ा है । वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनी और आज की बात करें, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा । मेरी मांग है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों को कम किया जाए ताकि किसान को खेत में ट्रैक्टर जोतने के लिए कम कीमत पर डीजल मिल सके । आम आदमी कम किराए में सफर कर सके । आपने मई महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल 9 रुपये 55 पैसे तथा डीजल 7 रुपये सस्ता किया, इसके बावजूद उत्तर भारत के प्रमुख 15 शहरों में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान की राजधानी जयपुर में था ।

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member, Shri N. K. Premachandran.

***m37 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.**

Sir, first of all, I take this opportunity to extend my sincere thanks to the hon. Speaker for having admitted this discussion under Rule 193 regarding price rise.

Sir, I am confining my point to the five per cent GST on food grains. All other issues with respect to price rise have already been discussed in the House

elaborately. There is one famous quote on inflation and I quote:

"Inflation is nothing but taxation without legislation."

This is the thing which has recently happened in our country. There is nothing to explain with regard to inflation. The alarming situation that the country is now facing is because of this five per cent GST rate on food grains. That has adversely affected the common people. The marginalised sections of the society are directly affected. There is still an utter confusion among the consumers, traders, and the people at large. There is also an utter confusion among the State Governments as well as the Central Government.

Sir, the inflation rate is at an all time high since 2014. It has increased to 7.79 per cent in April, 2022 while the market forecasts for the period was just 7.5 per cent. Food inflation accelerated for the seventh straight month to 8.38 per cent, highest since November, 2020. Inflation in cost of transportation and communication is 10.91 per cent, health 7.21 per cent, footwear 12.2 per cent and clothing 9.51 per cent. Inflation is staying above the 2-6 per cent market which is the tolerance limit set by the RBI continuously for the last four months in a row. This is the situation which is prevailing in our country.

Sir, the Reserve Bank of India is taking its own monetary measures so as to address the price rise and also giving and cautioning all the State Governments and the Central Government to address the situation to curb inflation. Yes, I do agree that the Government of India in June has announced an excise duty cut of rupees eight per litre on petrol and rupees six per litre on diesel. Some other measures have already been taken as far as the import duties on raw materials for steel and plastic are concerned. The Centre has also announced a ban on wheat exports.

Some measures have already been taken by the Government of India. I would like to pose a specific question to the hon. Finance Minister whether the measures taken or adopted by the Government are sufficient to curb inflation.

Sir, according to me, it is not sufficient. The Government totally failed in addressing inflation and price rise which is prevailing in our country.

Sir, to fuel the fire, on 18th July, five per cent of GST has been imposed on all the food grains especially on cereals, rice, flour and curd which are pre-packed and labelled.

Sir, since it is a matter of getting additional revenue, I would like to believe our hon. Union Finance Minister and also the State Finance Minister.

Mr. Chairman, Sir, you may be well aware that the State Government of Kerala and the hon. Finance Minister unequivocally stated in the press conference that this is absolutely the responsibility of the Union Government. The State Government has never spelt about an increase of five per cent duty or GST on food grains. This is the situation. The Central Government is blaming the State Government and the State Government is blaming the Central Government. The consumers, the trades, the shopkeepers - all are in big trouble. Who is responsible for that? Utter confusion is there. What are the legalities? I am not going into all those things.

Sir, the turmoil has started. For the first time, GST has moved from commodity-wise taxation to the packaged-wise taxation.

Sir, I may be given two-three minutes. I am confining to a particular point alone. I do not understand the necessity and urgency of imposing five per cent of GST on food grains. It was taken by the GST Council without having any proper preparation and without doing any homework. For example, I will come to the confusion. If the rice is pre-packed and labelled as per the Legal Metrology Act and Rules and kept in a shop, it is going to be five per cent GST. If it is packed in the presence of a consumer, GST rate is zero per cent. If a shopkeeper takes five kilograms rice from a 30 kilogram bag and sells it to the consumer, GST rate is zero per cent. If the same shopkeeper takes five kilograms rice from a 25 kilogram bag, he will have to bear five per cent GST from his own pocket when he cannot collect it from the consumer.

Sir, how do you prove these transactions? Is it based on CCTV footage on petty shops? How are you going to assess these things? This is the same product. Kindly examine and revisit the situation. Paneer butter masala has become the star menu in social media.

Sir, if you examine GST for these things, you will find that GST for butter is 12 per cent, GST on paneer is five per cent, GST on masala is five per cent. What is butter paneer masala? I could give a fine answer. Since it is cooked and ready to serve, it can have five per cent GST. Since different items have different tax rates, it can be considered for 12 per cent. Since it is not included in any schedule, it can be considered for 18 per cent. Since it can also be considered as luxurious item by an officer, then it can be 28 per cent. What would be the fate of the people? Is there any clear clarity for these things?

Who will benefit from these things? It is multinationals, malls, and even online giants have elaborate system to adapt to these changes. But our consumers and small-scale traders are in big trouble.

Nothing is clear about it. The present inflation is a man-made catastrophe because of untimely decisions of the Central Government and is also the reason for price rise … (*Interruptions*)

Thank you.

*m38 डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं पिछली काफी देर से हमारे अपोजिशन के साथियों की बात सुन रहा था और मुझे उनकी बात सुनकर एक इंग्लिश मुहावरा याद आया कि ninety-nine per cent of all statistics tell only 49 per cent of the story. अपोजिशन की तरफ से बहुत-बहुत बड़ी बातें सुनने को मिली हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इंफ्लेशन इत्यादि । कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनॉलिस्ट ने ये बात रखी है । मैं तो डॉक्टर हूं, इसलिए एक डॉक्टर के तौर पर बता पाऊंगा कि मुझे इनमें एक बीमारी जरूर नजर आई, वह है, सेलेक्टिव एमनीसिया । सेलेक्टिवली अपनी यादाश्त भूलने की एक बीमारी है । ये बड़ी ही सहूलियत से वो चीज भूलना चाहते हैं, जो वे भूलेंगे और बड़ी सहूलियत से वही चीज बताएंगे, जो इनको बोलनी है ।

पिछले दो-ढाई घंटे से इनका फेवरेट वर्ड क्राइसिस है । इनको इस क्राइसिस वर्ड से इतना लगाव है, देश क्राइसिस में है, इकोनॉमी क्राइसिस में है, फलाना क्राइसिस में है और ढिमकाना क्राइसिस में है । इस लगाव की वजह से आज इनकी खुद की पॉलिटिकल

पार्टी क्राइसिस में है, लीडरशिप क्राइसिस में है, करप्शन की वजह से क्राइसिस में है । इनकी एक आदत है कि ये अवसर को क्राइसिस में कंवर्ट करते हैं यानी अवसर को आपदा में बदल देते हैं, लेकिन हमारे पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी आपदा को अवसर में कंवर्ट करते हैं । ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत है ।

महोदय, बातें बहुत हो गई हैं, समय भी बहुत कम मिला है । मैं एक आम आदमी के तौर पर समझ सकता हूं कि किसी भी चीज को बाधित करने या इंफ्लेशन होने के लिए डिमांड और सप्लाई चेन को बाधित होना जरूरी है । जब डिमांड और सप्लाई चेन बाधित होगी, तब महंगाई बढ़ती है । उसके बहुत फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे कोविड है, रशियन-यूक्रेन वॉर है, नेशनल क्लाइमिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है । मेरे साथी सांसदों ने इस चीज को बहुत ही विस्तार से बताया है । लेकिन पिछले ढाई सालों में हमारे महाराष्ट्र में जो एमवीए सरकार है, जिसे कुछ लोग शायद महाविकास अघाड़ी सरकार बोलते थे । हम कहते थे – महावसूली अघाड़ी सरकार । महाराष्ट्र में एक अलग ही तरीके का इंफ्लेशन देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से इसको सदन में रखना चाहूंगा ।

महोदय, वहां डिमांड और सप्लाई कैसी थी । डिमांड मंत्री जी करते थे और सप्लाई ब्यूरोक्रेट करते थे । मंत्री जी ने तहसीलदार से 50 लाख रुपये मांगे और सप्लायर तहसीलदार ने 50 लाख रुपये दे दिए । इस डिमांड और सप्लाई चेन की वजह से जो कुछ भार पड़ा, वह आम आदमी पर पड़ा कि जिस अधिकारी ने मंत्री को पैसे ट्रांसफर किए, वह उसको कॉमन आदमी से वसूलता था । इसकी वजह से महावसूली अघाड़ी के पिछले ढाई साल के कार्यकाल में हमें महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इंफ्लेशन देखने को मिला है । मैं एक उदाहरण बताता हूं । महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सिर्फ कोविड पीरियड में अलग-अलग नियमों के माध्यम से जो फाइन कलेक्शन हुआ है, आम आदमी से नियमों के उल्लघंन के लिए 300 करोड़ रुपये लिए गए हैं । हॉस्पिटल बिल्स कंट्रोल में नहीं किए गए, लेकिन हमें महाराष्ट्र में इस तरीके की डिमांड और सप्लाई देखने को मिली है ।

महोदय, आज जो हमारे अपोजिशन के साथी बोल रहे थे, मैं उनको एक फर्क समझाना चाहता हूं कि क्यों ये डिस्कशन होना जरूरी था । पूरे देश या पूरे विश्व में चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में बोला जा रहा है । चाइना के द्वारा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एक ग्लोबल इंफ्रा डेवलेपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई । इस चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में आज करीबन 165 देश बर्बाद हुए हैं और इन देशों पर 385 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हुआ है । आज हमारी सरकार है, इसलिए हम कैसे बचें, मैं एक आर्टिकल के माध्यम से आपको बताता हूं । जब वर्ष 2008 में यूपीए सरकार थी और उस यूपीए सरकार में कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी थी, उन्होंने वर्ष 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया । उसी से लगकर कांग्रेस पार्टी के अलाइड इंस्टीट्यूट

राजीव गांधी फाउंडनेशन ने उस दौरान चाइनीज सरकार से ग्रांट लिया । मैं यह दावे के साथ कहना चाह रहा हूं । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज कन्क्लूड कीजिए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. सुजय विखे पाटील : महोदय, अगर आज यूपीए सरकार होती, तो हमारा देश चाइना के पास गिरवी होता । ये पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए हम आत्मनिर्भर बने हैं और आज हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं । मैं अंत में दो पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । ...(व्यवधान)

सर, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा ।

"नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीं पर चांद-सितारों की बात करते हैं,
वे हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं ।"

***m39 DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, before the DMK Government first came to power in Tamil Nadu in 1967, the situation in Tamil Nadu and throughout India, was that, in a village, the agricultural land was owned by ten per cent of the landlords in that village and 90 per cent of the people were labourers for those landlords. So, for getting work, they had to work with the landlords. In a year, they got around 110 days of work. They got their ration, food and money but for the remaining 255 days, they did not have any food. They had to rely on those ten per cent of the landlords. This was the situation throughout India. What happened when Dr. Kalaignar, the great visionary leader, came to power? He thought that, for the rest of the 255 days also, these labourers should not go without food. So, he introduced the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and gave food and subsidized pulses for 255 days. This brought a self-respect movement. They did not have to rely upon their landlords for food. This movement, along with the public distribution system, was brought throughout Tamil Nadu and this was later followed throughout India. So, this was the care taken by the Dravidian model and it was achieved through Dravidian principles and thus, equality and self-respect have been established.**

But now what do we see? We see that the Narendra Modi Government has been favouring only the corporates. You keep increasing the price of milk, potatoes and curd. How do you expect the common man to live? You say that for packed milk or curd, the GST is high but for unpacked items, you do not have it. Children and others need milk or curd only as packed items as they are safe. We do not have any objection when the Government increases the GST on any product. Let them increase it even to 50 per cent. That can be done for gomuthra which they can handle with bare hands. Let them increase the GST for it but why should they put the common man into problems? When the election comes, what do we see? We see that the prices of fuel items like LPG get frozen and once they win the election, they again increase it steadily. We are against such a practice. We want the Dravidian model to be implemented throughout India and it is for the benefit of the marginalised, the downtrodden and the people who are discriminated whereas we see that the Narendra Modi Government is favouring only the corporates. Thank you, Sir.

***m40 SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I convey my thanks to my leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy for giving me this opportunity.**

Sir, I would like to speak in Telugu.

HON. CHAIRPERSON: Okay but be brief.

***SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir after Corona pandemic in our country, people are still facing so many difficulties. Many people lost their employment. Price rise is affecting all sections of our society especially unemployed, poor and backward classes. Due to price rise in all essential commodities like salt, pulses, milk etc they are expecting all MPs to plead with Honorable Prime Minister and Union Finance Minister to reduce the prices of these essential commodities. Until unless prices of essential commodities are not reduced people cannot benefit from the welfare schemes that are being implemented by the Government. In this context, I request Honorable Prime Minister and Honourable Finance Minister to look at the issue of price rise.**

Our Finance Minister is a role model for the women of this generation. I heartily request honorable Nirmala Sitharaman to look at this issue, because

though in general, men are the earning members of a family, it's women, who manage, the day to day expenditure of a household. All costs have increased including transportation cost. We have inflation and there are reasons for this on behalf of the government. We suffered from Corona pandemic for 2 years and on the other hand we have a war between Ukraine and Russia, people may not understand these reasons. What people want is that they need to meet the basic requirements of their life. We have a saying in Telugu which means that punishing someone who is already suffering, by increasing GST on essential commodities this is adding to the price rise. Poor people of this country are not in a position to take this additional burden.

I would like to bring to your notice one important point. In our state Andhra Pradesh, our honorable Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy is providing financial assistance to the poor people. Even during corona pandemic the financial assistance provided by our State Government has helped many poor families to sustain the hardships. Now when we are going to every household to explain our welfare schemes, though they are happy with our welfare SS schemes, they are requesting us to bring to the notice of the Union Government about the price rise and they want us to plead with the Union Government to reduce these prices. Once again I request the Union Government to take care of poor people, by reducing prices of essential commodities and also by reducing GST that is being imposed on these commodities.

Thank you Sir.

***m41 SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, hon. Chairperson for giving me an opportunity to participate in the discussion on the price rise. Sir, the entire country is facing a heavy blow because of price rise. The blow is more on the common man and the economically weaker sections of the society.**

This is mainly because the consumer products are being affected by the price rise. The Consumer Price Index is a basic tool for considering the rate of inflation. The rate of inflation in 2019 was 3.7 per cent and now it is 7.75 per cent.

This is basically because of the rise in the price of petroleum products. The cost of petrol was Rs.70 in 2014, when the Modi Government came into power and now, it is Rs.105. The price of diesel was only Rs.55 and now it is Rs.95. The crude oil price, which is the basis of the petroleum price, was 105 US dollars in 2014 and now it is only 97 US dollars.

Sir, earlier the price of LPG was just about Rs.260 and now it is Rs.1050. This is the basic reason why the prices of essential commodities are going up. It has already been discussed in detail. The Government has imposed GST on all essential commodities, especially on the food grains, milk, curd, pulses, cereals, life-saving medicines and even on rooms in hospital also.

This is the basic reason why the people are suffering now. It is good that the Government has agreed to have a detailed discussion in the House on price rise. But what action is being taken by the Government on this issue is very important. I hope that the Government will open their eyes and take note of the points being discussed here and also take appropriate action. Thank you.

***m42 श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): सर, आपने मुझे इस संवेदनशील विषय के ऊपर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।**

सर, मैं बंगाल से आता हूं, इसलिए मैं बांग्ला भाषा में बोल रहा हूं ।

***One who loves man, serves God – He prayeth best who loveth best. This we had heard from Swami Vivekananda and today we get to hear 'Sabka Saath, Sabka Vikas', Development for all, with all. We saw, that since 2014 India has been treading a new path, during the covid times. When polio was prevalent, it took almost 100 years to vaccinate all the Indian against this disease. But we have witnessed how corona vaccination target has been achieved within just 6 months. This is India. People want this India. During covid times, 80 crore people could avail free ration while sitting at home in the last 2 years. But even after doing such yeoman service, the opposition members raised so many issues. We have seen the Hon. Member from West Bengal Smt. Kakoli Ghosh Dastidar speaking. She resorted to a drama. She ate a piece of brinjal and said that should we eat only raw vegetables? Yes, the farmers of Bengal are in such a poor condition that they are not getting Rs. 6000 meant for them. We are witness that the teachers of Bengal are sitting on dharna for the last 522 days, but are not getting jobs. Once,**

Bengal used to provide officers to the Centre, now we have become workers. The Minister of Bengal has embezzled Rs. 50 crores. We can recall that the present Chief Minister had thrown papers to the chair in this very House. That was the drama she enacted. In Bengal, today, only dramas are being staged. Because in Bengal, the farmers are not happy, teachers are not happy, no one is happy. There is only rampant corruption and black money. The benefits of Pradhan Mantri Health Insurance Scheme are not available to the people of West Bengal today. Why? Because the State Government has stalled the project as it bears the name of Prime Minister. The name of 'Pradhan Mantri Awas Yojna' has been changed by Chief Minister into 'Bangla Awas Yojana'. This is shameful. Names of all the central projects have been changed. Shri Narendra Modi is following the ideology of Swami Vivekananda, whereas no ideology is being followed by the State Government.

Modiji has launched 'House for all' Programme. And in West Bengal, there is corruption in the co-operative banks as well. Trinamool Congress has finished everything. The Party has taken the form of a family group. On the other hand, our BJP runs with the motto of 'will not be corrupt, will not let anyone become corrupt'. Today, you can see crores of rupees stashed inside cars or houses of their associates or friends. This is extremely shameful. Bengal's face is hanging in shame. I would like to thank Hon. Modiji for his continuous efforts to improve the lives of the common people, somewhere through start-ups, somewhere through other means. People are getting bank loans today.

I will conclude by saying that as Ramkrishna had said, 'Money is of little worth, as worthless as dust'. But today money is free-flowing. On the other hand Modiji is leading the country boldly towards development. When he is there, everything is possible. With these few words, I conclude my speech.

Thank you Sir.

***m43 श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, महंगाई के मुद्दे पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । आज पूरा देश महंगाई से परेशान है । मैं आज दो-तीन बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा । हमारे देश में गरीब, मजदूर, किसान आज अपना आवास बनाता है, लेकिन सीमेंट का दाम बढ़ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा जीएसटी**

लगाया गया है । इसके साथ ही ईंट भट्ठों, जिससे मकान बनता है, आज उन ईंट के भट्ठों पर भी 6 से 12 परसेंट जीएसटी लगाया गया है, जिससे हमारे देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की रीढ़ टूट रही है ।

माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम ईंट भट्ठों पर जो जीएसटी लगाया गया है, उसको कम किया जाए । उसी तरीके से खाने वाले पदार्थों पर लगाया गया है । आज जो हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी है, वह किसान, गरीब और मजदूर की है । आज दूध, दही, पनीर पर जिस तरीके से जीएसटी लगाकर दामों में बढ़ोत्तरी की गई है, उससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वह गरीबों का हो रहा है । इसी के साथ हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उससे भी हमारे देश के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, गरीब मजदूर हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उन लोगों का हो रहा है ।

आज हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री रामशिरोमणि वर्मा : महोदय, अस्पताल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दवाएं हों, उन सभी पर जीएसटी घटाई जाए ।...(व्यवधान) मैं इन्हीं थोड़े-से शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***m44 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the inception, I am goaded to refute the charges made against us by the Treasury Benches that in spite of the indisposition of health of our hon. Finance Minister, we had been persisting for the discussion on price rise.**

<u>18.51 hrs</u> **(Hon. Speaker *in the Chiar*)**

With all humility at my command, I refute the charges because these charges are based upon unmitigated falsehood and *calumnies*. Since the day it was heard that our Finance Minister has been infected by COVID, we have been praying for her immediate recovery and recuperation. We have suggested to the Government that we can initiate the discussion once our Finance Minister recovers so that the reply could easily be given to us. But now, without any rhyme

or reason, allegations have been hurled against us which is a disrespect to the Opposition. It is simply based on falsehood. Madam, again, we all are wishing you for your recovery and sound health. It is because being the Finance Minister of our country, you need to sustain a safe and sound health. सर, यह चर्चा बहुत समय से हो रही है । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चर्चा में विपक्ष-पक्ष बहुत सारी बातें जरूर करते हैं । सर, मैं इस सदन में आया हूं, only to express our concern for the common people of our country. एक तरफ हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर को खत्म करना चाहिए और दूसरी तरफ ट्रेजरी बेंचेज की ओर से जितने भाषण यहां दिए गए हैं, उसमें रेवड़ी कल्चर को ही बढ़ावा दिया गया है । मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि यह रेवड़ी कल्चर, जो माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं और आज प्रधान मंत्री जी और एनडीए सरकार की जिस तरह से सराहना करते हुए बयान पेश किए गए हैं, इसमें, what is the distinction between 'revdi culture' and other culture? I am really confused about it. I would like to ask very curtly and succinctly to our hon. Finance Minister, as many economists have already expressed their apprehensions, whether the country has been heading towards stagflation. Is it true or not? The stagflation suggests high inflation, high unemployment and stagnant growth. I do not know the view of the Government. So, I would like to request the hon. Finance Minister to dispel the apprehensions expressed by the renowned economists of our country.

सर, हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं मोटे-मोटे तौर पर दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूं । एक यह है कि 'Impact of inflation on nutrition'. हमारे साथी कल्याण बाबू ने इस विषय पर बोलने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन समय अभाव के कारण वह नहीं बोल पाए ।

Sir, according to the State of India's Environment Report, 2022, around 71 per cent of Indians cannot afford a healthy meal. जयंत सिंहा जी, थोड़ा सुन लीजिए । The Report further said that over 17 lakh individuals die in the nation every year due to diseases that can be attributed to poor diet. According to the Government's own figures, anaemia in children and women have increased significantly between 2015-16 and 2019-21. Over 67 per cent children are anaemic in the country. PM Modi's home State of Gujarat has the highest number of anaemic children at 79.7 per cent and 57 per cent of women in Gujarat are anaemic. I am simply referring to these statistics for your convenience.

Sir, India is already suffering from a malnutrition and hunger crisis. About 20 crore people do not have sufficient access to food. One-fourth of the world's hungry population belongs to India, and India was ranked 101 out of 116 countries on the Global Hunger Index for 2021, a score that has been worsening for a few consecutive years. Now, you can easily assume how the country has been progressing towards prosperity. The statistics simply suggest that we are really in great trouble.

Sir, so far as medical inflation is concerned, I would like to highlight that in 2021, India reported the highest medical inflation of 14 per cent in Asia. According to the Report prepared by Motilal Oswal Financial Services Limited, the out-of-pocket medical expenditure per hospitalisation in 2021 in rural areas and urban areas reached as high as Rs. 15,937 and Rs. 22,031 respectively, as per the latest National Health Profile. यह मेरी नहीं, सरकार की रिपोर्ट है ।

In March 2022, the National Pharmaceutical Pricing Authority of India announced a 10.7 per cent hike in the prices of over 800 essential medicines, including Paracetamol and Azithromycin among others. आज यहाँ 'आयुष्मान भारत' की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं । श्री जयंत सिन्हा जी, मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिन्दुस्तान में कोविड के कारण 52,06,258 लोगों की मौत हुई । आप पता कर लीजिए । आप इंटरनैशनल एरिना में घूमते हैं, आप अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं । मैं जानता हूँ, आपके पास बहुत जानकारियाँ हैं, फिर भी आप पता कर लीजिए ।

Now, I come to the impact of high inflation on income. Between 2013 and 2019, income from agriculture in real terms decreased by 8.9 per cent, according to the analysis of SAS survey conducted by the National Statistical Office. This is opposite to BJP's promise of doubling farmers' income by 2022.

In 2019, on an average, the Indian farmer earned more through wages than through cultivation. But for the last 33 months, the rural wage growth has been declining much to the concern of the agriculture sector.

So far as burden of inflation is concerned, you are pleading for Atmanirbhar Bharat. But where are we existing now? That needs to be clarified. The Ruling Government's anti-people and pro-corporate policies have had concurrently increasing fuel taxes, while decreasing corporate taxes. In 2019-20,

the corporate tax collection stood at Rs. 5.5 lakh crore while fuel excise duty stood at Rs. 2.4 lakh crore. The Modi Government has shifted a massive part of the corporate tax burden on to consumers in 2020-21, which is shown in the revised Budget Estimates where corporate tax collections are estimated to be under Rs. 4.5 lakh crore, a decrease of Rs. 1 lakh crore, while the fuel excise duties are estimated at Rs. 3.6 lakh crore, an increase of Rs. 1.2 lakh crore. This is not an isolated incident. The trend of the BJP over the years has been to cut corporate tax rates, enriching their allies, while hurting the poor and the middle-class ordinary citizens. The net result of this pro-corporate policy is to increase fuel prices, and as described before, to cause economy-wide inflation that especially hurts the poor through increased food prices.

सर, मैं दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूँ । इस सदन के अन्दर 18.07.2020 को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि **the Government has constantly boasted up about Ease of Doing Business. But the Finance Minister herself said that in 2022 alone, 14 billion dollars have been withdrawn from Indian equity markets by foreign portfolio investors.**

<u>19.00 hrs</u>

I would like to have a reaction from the hon. Finance Minister. The trade deficit for the period between April 2021 and March 2022 has also been estimated to widen to 192 billion dollars, despite the Government chest thumping over 400 billion export figures. It should be remembered that widening trade deficit has caused depreciation of the value of rupee. In turn, the same has made import costlier making it a vicious cycle for the citizens of the country unable to afford basic commodities. इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स पीआईबी रिलीज है । मैं पीआईबी रिलीज के सोर्स से बता रहा हूं । लोक सभा में दिनांक 18.07.2022 को क्वेश्चन हुआ था । **The value of the Indian rupee has depreciated by almost 25 per cent till the end of December.**

पहले मनमोहन सिंह जी के जमाने में जब मुद्रा का भाव गिरने लगा था, तब प्रधान मंत्री मोदी जी कहते थे कि हिन्दुस्तान की मुद्रा आईसीयू में जा रही है । अभी मुद्रा कहां जा रही है? शतक लगने में बहुत देरी नहीं है । अगर शतक भी लग जाए, तो अचरज होने का कोई सवाल नहीं है । ये यूक्रेन-रशिया वॉर का बहाना बनाते हैं । एक बहाना कोविड का है और एक बहाना है कि इंडिया के अलावा भी काफी देशों में इन्फ्लेशन हुआ है । देखिए,

यहां अमेरिका की बात कही गई है । अमेरिका में कोविड के चलते पांच ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा किया गया है । क्या हम लोग अपने देश में पांच ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा कर सकते हैं? आप तुलना कीजिए, लेकिन सोच-समझकर कीजिए । हमारे हिन्दुस्तान में अभी 7.01 सीपीआई इन्फ्लेशन है । श्री जयंत सिन्हा जी, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 5.09 परसेंट, चाइना में 2.44 परसेंट, जापान में 1.97 परसेंट और मलेशिया में 2.84 परसेंट इन्फ्लेशन है । आप खुद तय कर लीजिए । आप कोविड और यूक्रेन-रशिया जंग का बहाना बनाते हुए लोगों को गुमराह न करें, तो बेहतर होगा । आपकी सुविधा के लिए मैं और दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूं । मान लीजिए कि ग्राम दाल में यूपीए के जमाने से अब इसकी कीमत में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, अरहर दाल की कीमत में 48 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है, उड़द दाल की कीमत में 59 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है, पोटैटो की कीमत में 11 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई, ओनियन की कीमत में 30 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है और टोमैटो की कीमत में 56 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है । सर, हम लोग इसलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, ताकि कोई रास्ता कैसे निकाला जाए? हम सबको इस पर सोचना पड़ेगा । लेकिन अगर सरकार इस पर अड़ी रही कि उसकी कोई गलती नहीं है, यह सिर्फ प्रचार है, तो यह ठीक नहीं है । आप एक रिस्पॉन्सिबिल सरकार के नुमाइंदे होने के नाते सच को सच बताइए । आप हां को हां और न को न बताइए । इससे इस चर्चा की गरिमा और बढ़ेगी ।

सर, आप देखिए, यह मैं नहीं कह रहा हूं । **The former noted economist of the World Bank and the former Chief Economic Advisor, Kaushik Basu has slammed the current Government's economic management alleging that not enough is being done for the welfare of the poor. The renowned economist also added that with India's population growing at 1.2 per cent annually, real GDP per capita has sunk -0.1 per cent over the past two years. Sir, according to the World Inequality Report, India stands out as a poor and very unequal country with an affluent elite.** इसलिए, हमारे नेता कहते हैं कि मोदी जी की सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है । यहां दो-तीन कंपनियों द्वारा सब लूट लिया जा रहा है और बाकी हम गरीब लोग, इस अंधेरे में रह गए हैं । **Sir, the top 10 per cent of Indian population holds 57 per cent of the total national income, including 22 per cent held by the top one per cent, while the bottom 50 per cent holds just 13 per cent in 2021. It further stated that the top 10 per cent of Indians had about 96 times more income on average than the bottom 50 per cent. Similarly, Oxfam International claims that in 2021 India's top one per cent holds about 77 per cent of the country's wealth. How is this possible without the support of this Government?**

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि आप झूठ बोलने के आदी मत बनिए । झूठ बोलने की आदत न बनाओ, क्योंकि झूठ बोलते-बोलते आपकी आदत इस तरह की हो जाएगी कि आप हर किसी को झूठ बोलने लगोगे । इसलिए आप झूठ मत बोलो । आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखो और लोगों को गुमराह मत करो । यही निवेदन करते हुए मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को इस हालत से उभारने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

*m45 वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): धन्यवाद स्पीकर सर । करीब 30 माननीय सदस्यों ने महंगाई के विषय पर चर्चा में भाग लिया है । मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि बहुत विस्तार से उन्होंने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है । **Let me, without undermining some of the points that many Members have said, say that I find that it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actual data-driven concerns about price rise.** इसीलिए मैं अपना जवाब भी थोड़ा पॉलिटिकली देने की कोशिश कर रही हूं, किसी सदस्य को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा जवाब नहीं दे रही हूं । जवाब सुनते समय 'यह क्या है', 'आप राजनीतिक भाषण दे रही हो', यह राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा ।... (व्यवधान) ऐसे ही बीच में कुछ इंट्रप्शन आने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है । मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ती हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सदन में व्यवधान पैदा नहीं होने दूंगा ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, आप हैं, इसलिए मैं चिंता नहीं कर रही हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें परमिशन मत दीजिए कि वे व्यवधान पैदा करें ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, let us please be, in this House, looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just two or three highlights will tell you where India is compared to the rest of the world. Why should we have to compare with the rest of the world? It is because whether it was in 2008 or before that, we have never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind. Coming out of the pandemic, all of us, each at his own level, were trying to make sure that people in our constituencies, people in our States, people in our areas are given that extra help. I recognise that everybody – Members of Parliament and also State Governments – has played his role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So, I fully credit the people of India for, even against this kind of an adversity,

being able to stand up and be recognised as the fastest growing economy. This is not my assessment. Repeatedly, in the last two years, the World Bank, the IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of global GDP is going to be like and also recasting their assessments about what the world's growth is going to be and by country, what the assessment is going to be. Each time when they have reviewed, when they have downgraded the global growth, when they have reassessed saying that 'no, it is not as we thought six months ago; it is getting worse', in each of these times, India also has been reduced in terms of growth it is expected to achieve, but even after that we remain as the fastest growing economy.

If it was 8.2 per cent, now it may be 7.4 per cent. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, and re-estimated, each time we remain at the highest. So, first of all, it is important for us as Indians to appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that, the way in which the global value chains have hit us. But in spite of that because of the various steps taken by the Government and also by the Reserve Bank of India, we are still at a much better position than most countries. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, please accept the truth. You should acknowledge the facts. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रूकिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी ने अपनी-अपनी बात रखी । मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, कोई बीच में इन्टरप्ट नहीं किया । मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी उनके जवाब को पूरा सुनें ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सबको बता दिया है ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Globally, when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation country-wise, and repeatedly in their assessment India has remained at the highest, I think this House irrespective of the party differences will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State Governments have helped. … (*Interruptions*)

***m46 SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): People are dying. Farmers are committing suicide. How can we be proud? … (*Interruptions*)**

***m47 SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it is exactly this which I am trying to address. It is not that the country does not have problems. We have to work together to do it and we are trying to do it.**

But even as we are trying to do it and even as the global agencies are saying this country is suffering like that, that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this, it is a moment that all of us will have to be true to ourselves. … (*Interruptions*)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Wow!

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Excuse me, Madam. Do you have a problem if I speak? There is nothing about wowing here. I am sorry. I take objection to that, hon. Speaker, Sir. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Why are you getting so excited, Madam?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Because you are there in front of me. Before I complete one sentence… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You are a highly respected person. Do not get excited. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh, thank you, very much. The person who is mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point.

Mercurial!

Sir, through you, I would like to say I am quite convinced of every input given and I think it is my duty to respond. But even before hearing me if there is mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear.

So, I would seek your indulgence on that. … (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Is the Minister threatening us? क्या हमको धमकी दी जा रही है?… (व्यवधान) क्या आप हमें धमकी दे रही हैं?… (व्यवधान) हमें धमकी दे रही हैं ।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आप उनका मजाक उड़ाओगे क्या?… (व्यवधान) हम आपको मजाक उड़ाने नहीं देंगे ।… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is why I want to say this to you when there can be interruptions which are serious and when there is mocking tone coming from there, I reserve my right as a Member of this House to reply to those.

And if that is treated as *dhamki,* what should be the first one which comes treated as mocking or *dhamki*. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, she is not a Member of this House. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh! Thank you, otherwise I would not be allowed … (*Interruptions*) All right, in that House or this House … (*Interruptions*). Dada, you are always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, रुकिये । मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि आप बैठे-बैठे टिप्पणी न करें । माननीय मंत्री जी, आप इनकी टिप्पणी को नहीं सुनें, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है । मैं यह अपेक्षा करूंगा कि कोई बैठे-बैठे टिप्पणी न करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not a Member of this House, but with your permission, I am here because I have to reply. … (*Interruptions*) So, the

senior Member, Shri Sougata Ray should probably take that into his system. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, she is not a Member of this House. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh! Thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions! … (*Interruptions*). Recall those days because you always had that approach towards women in the House. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिये । आप इनकी कोई भी टिप्पणी मत सुनिये ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the GDP of the US fell 0.9 per cent in the second quarter following a 1.6 per cent decline in the first quarter, marking a start of what they call an unofficial recession. There were some Members who were saying, even Adhir Ji mentioned it, are we going into a stagflation, and will the Finance Minister reply? I will, first of all, start with the last speaker, but the Leader of the Opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adhir Ji, you please be assured, there is no question of us getting into either stagflation like the US. They may call it technical recession or whatever. … (*Interruptions*).

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सराहना करता हूं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it is not just me, a Bloomberg survey which was done by an economist, has said that there is zero probably of India slipping into a recession. … (*Interruptions*) So, it is not just me saying it. There is zero probably of India slipping into a recession, even though there are several major economies which are at substantially risky position of getting into recession.

Again, as we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Banks and banks' health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compare globally, 4,000 banks in China are reportedly on

the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the hon. Members. In India, the gross Non-Performing Assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a six-year low of 5.9 per cent in Financial Year 2022. So, in China, 4,000-odd banks are on the verge of going bankrupt, and our NPAs are improving. … (*Interruptions*).

Sir, on Government debt, Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits, and that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka and Canada, whereas the Central Government very consciously has controlled its debt. It is at 56.29 per cent of the GDP at the end of 2021-22 compared to 59.9 per cent pegged in the Revised Estimates for that year.

So, even from the Revised Estimates, we have brought it further down. Even when comparing the general Government debt, which means the Centre and the States, India is in a far better position than its peers according to the IMF data -- it is not me saying it -- with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both Centre and States.

I just want to draw the attention of Members. So, globally if in each country the situation is pandemic, waves -- second wave, third wave, the Russia-Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, then I have just given you some few comparisons of India's position.

This morning, we have announced the GST collection for the entire month of July, 2022. In July, 2022, we have garnered the second-highest level ever since the introduction of GST, which is Rs. 1.49 lakh crore. It is the second-highest, and compared to the last year this is one of the highest. You may be aware and I would like to gently remind that in April, 2022 it was Rs. 1.67 lakh crore, which was the highest reached. Now, we have got in July, 2022 the second-highest, which is Rs. 1.49 lakh crore. This is the fifth consecutive month that the GST collections have been above Rs. 1.4 lakh crore. The manufacturing, Purchasing Managers' Index, which has also come out in the morning, I think, and it is at eight-months highest number of 56.4 for July. So, the trend for output and new orders are strengthening, and the economy is really getting even more robust. The PMI rose

from 53.9 in June -- I have said that it is 56.4 in July -- which is well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level separating growth from contraction for the thirteenth month in a sequence. So, all of India's eight infrastructure sectors grew in double digits for the second consecutive month in June. The data released for the month of June showed the core sector grew at 12.7 per cent in June year on year. So, strictly speaking, the Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs.

I remind myself about the line hon. Member, Shrimati Supriya Sule, said: "It is enough, you cannot be going on talking about earlier days. Now, you had enough amount of time." She also compared very untypically to a married woman who enters the house; she gets to be a part of that house; and you do not anymore say: "We are new whereas what has been there and all that." But in these kinds of situations where constantly questions are based not so much on facts -- I am not talking about Shrimati Supriya ji alone, but in general -- facts will have to be reminded because of the way in which questions are being asked as though they did not exist earlier. Even now, the Leader of the Congress Party said that: "Please accept that inflation existed before the pandemic also." Inflation exists, Sir, but at what level is the question. So, I have no difficulty conceding to that point. Inflation exists, but at what level, and that is why if you will pardon me, hon. Member, I would like to go back to recalling that let us not forget for a small paper tantrum -- I am saying 'small' today -- of the flood of 2008, the problem continued till 2013 that the Indian economy became a 'fragile five' country. But what are we today in -- pandemic, second-wave, Omicron.

Today, we are in the midst of the Russia-Ukraine war, disruption of supply chain. Today, the largest component suppliers in China are still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held inflation well within seven per cent or even below. That has got to be recognised. … (*Interruptions*) Sure, I will speak. So, gently, some bullets have to be remembered.

हमें याद करना आवश्यक है । हम बार-बार आठ साल पहले के यू.पी.ए. की क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने की आवश्यकता नहीं है । हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं । शायद हम और बेहतर भी कर सकते हैं, मगर हमें क्यों बार-बार उसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या थी? पैनडेमिक भी

नहीं था, फेड की प्रॉब्लम थी । यू.एस.ए. ने रेट बढ़ा दिया । उन्होंने लिक्विडिटी को कम्प्रेस करने की कोशिश की । वह सिर्फ एक प्रॉब्लम थी । उसका असर इतना पड़ा कि भारत देश 'फ्रैज़ाइल-5' देशों में एक देश हो गया था । यह वर्ष 2013 में हुआ । मगर, अभी तो हम पैनडेमिक, सेकेन्ड वेव, ओमिक्रॉन झेल रहे हैं । चाइना में जगह-जगह पर लॉकडाउन्स हो रहे हैं । आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मैल्सी तक नहीं पहुंचा है, फिर भी हम अपने इंफ्लेशन को 7 प्रतिशत और 7 से नीचे रखने के लिए मैनेज कर रहे हैं । इसलिए, मैं उदाहरण क्वोट करना चाह रही हूं । Retail inflation was more than nine per cent. अभी 7 प्रतिशत है । 7 प्रतिशत से कम रखने का ही प्रयत्न हर बार हुआ है । दो बार उसके अच्छे नतीजे भी पहुँचे हैं । लेकिन, अगर आप अपने 28 महीने को इकट्ठा करके देखेंगे तो उसमें से 22 महीने में यू.पी.ए. के कार्यकाल में यह 9 फीसदी से ज्यादा था । अभी जब हम 7 प्रतिशत में हैं और उससे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया कि इंफ्लेशन है, आप क्या कर रहे हैं इंफ्लेशन के लिए । आपने 22 महीने इंफ्लेशन को 9 प्रतिशत से ज्यादा रखा । प्लीज़, उसे एक बार याद कीजिए । फिर उसी समय इंफ्लेशन डबल डिजिट्स में गया, 10 प्रतिशत से ज्यादा में गया ।... (व्यवधान) यू.पी.ए. सरकार के समय 9 बार इंफ्लेशन डबल डिजिट में था । उसे भी याद करना चाहिए, जब आप यह मांग कर रहे हैं कि यह 7 प्रतिशत से कम क्यों नहीं हो रहा है, आप इसे करो । हम इसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे । मोदी जी उन सबके ऊपर ध्यान रख रहे हैं । इसे जरूर करेंगे ।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): देश की जनता ने इसलिए आपको चुना है ।... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : दानिश जी, आप उठ कर सही प्रश्न पूछिए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य दोबारा उठेंगे तो उनका 'नाम' लिया जाएगा ।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, उनका नाम रिकॉर्ड से डिलीट कर दीजिए ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हमें इसलिए चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला । वोट मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिली, इसलिए हम इंफ्लेशन को 7 प्रतिशत से नीचे ही रख रहे हैं । जनता की जो एक्सपेक्टेशन्स थीं, जिनके अनुसार उन्होंने वोट दिया, उसी के अनुसार ही हमारे द्वारा डिलीवरी भी हो रही है । इसलिए, इसे याद रखना चाहिए ।

यहां आकर इतनी तेजी से कहना कि क्या चल रहा है, 7 प्रतिशत है । 22 महीने तक 9 प्रतिशत से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इंफ्लेशन, यह करने वाली सरकार को थोड़ा सोच-समझ कर हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहिए ।... (व्यवधान)

सर, मैं इंफ्लेशन के ऊपर इससे ज्यादा बोल सकती हूं, मगर समय भी हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ती हूं ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महँगाई को कम कैसे करेंगे, इसे बताइए ।... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : 7 प्रतिशत से कम हो रही है ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: बाज़ार में आग लग रही है ।... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय स्पीकर सर, हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन अधीर रंजन जी ने बोला । उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर बोला कि देखिए, इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की ।

सर, इनकी आदत है, वह एक-आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकि दुनिया के और इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे । ... (व्यवधान) यह उनकी आदत है । ये लोग उन्हीं इकोनॉमिस्ट और उनकी टिप्पणी के बारे में जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिया । इन्होंने कौशिक बसु जी का नाम लिया ।... (व्यवधान) इसमें रघुराम राजन जी भी हैं । क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया । मैंने सोचा कि रघुराम राजन जी के बयान की तरफ एक बार ध्यान दिलाएं ।... (व्यवधान) यह भी सही बात है, अधीर रंजन जी खुद एक इकोनॉमिस्ट है ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हम सिर्फ महँगाई घटाना चाहते है, और कुछ नहीं चाहते हैं ।... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ने यह बात बोली कि आरबीआई ने अच्छा काम किया । **RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserves in India insulating India from problems being faced by neighbouring countries such as Pakistan and Sri Lanka.** पाकिस्तान और श्रीलंका की जो प्रॉब्लम्स हैं, वे प्रॉब्लम्स हमें नहीं होने देना चाहिए । ऐसा करके आरबीआई ने अच्छा काम किया है, यह उनका टिप्पणी है ।... (व्यवधान) **Differentiating India from its vulnerable neighbours, Shri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted calling it a good sign.** मैंने अभी डेट टू जीडीपी फीगर्स पढ़ा, आपके सामने नंबर्स भी पढ़ा । उसका भी रघुराम राजन जी जिक्र कर रहे हैं कि नई दिल्ली की सरकार डेट को कम रखने के लिए अच्छा काम की है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं । आपका हर सेंकेंड उठना उचित नहीं है । आपका यह तरीका ठीक नहीं है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, न्यू दिल्ली का सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार हुआ ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका तरीका गलत है ।

माननीय मंत्री जी ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, रघुराम राजन जी ने यह भी कहा है कि we have sufficient foreign exchange reserves. RBI has done a good job in increasing the reserves. We are not having problems like Sri Lanka and Pakistan. Our foreign debts are also less. उन्होंने इतना स्पष्ट बोला । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उनकी बात पर मत जाइए । मैं सब चीजों को देख रहा हूँ ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, ठीक है । अधीर रंजन जी इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत चिंता कर रहे हैं । इस विषय में रघुराम राजन जी दोबारा क्या बोलें – at present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rates which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also.

सर, यह आरबीआई की तरफ से असेसमेंट है, जिसके बारे में रघुराम राजन जी ने बोला । उससे यह भी समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर है और इन्फ्लेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है । Of course, he did not say about measures that we have taken from the Government, the Ministry of Finance, to reduce the cost of imports on say edible oils and masoor dal and so on. मैं उसका भी जिक्र करना चाह रही हूँ । The Central Government has reduced Customs Duty on crude palm oil from 35.75 per cent to first 8.25 and now to 5.5 per cent only.

So, the Government drastically brought down the duty and made it possible for edible oil prices, in this case palm oil prices, come down for the common people. On sunflower and soybean oil - both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced from other countries – the Customs Duty has been reduced drastically from 38.5 per cent to 5.5. per cent. We have taken out the

Customs Duty so that कम दर पर एडिबल ऑयल भारत देश में पहुंचे । जनता को सस्ते में एडिबल ऑयल मिले ।

Secondly, TRQ (tariff rate and quota restrictions) on nearly 20 lakh metric tonnes of sunflower and soybean oil has been made nil. आप जितना चाहे इंपोर्ट करिए, बिल्कुल जीरो ड्यूटी में इंपोर्ट करिए, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा और सनफ्लॉवर ऑयल भी आएगा । आपने प्राइसेज़ कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए, उसे एक-एक करके मैं बोल रही हूं । ... (व्यवधान) The prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May with maximum decline of 18.1 per cent coming in palm oil prices. The other categories like sunflower oil, soybean, groundnut, mustard and vanaspati have also seen correction in the range of one per cent to seven per cent in the last one month. ... (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, ...(व्यवधान) इसका असर नहीं है ।...(व्यवधान) हम वॉकआउट करते हैं । ... (व्यवधान)

19.37 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मुझे दुख हो रहा है कि बाहर जाकर प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है, कहने वाली कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है । वे बाहर भाग रहे हैं ।...(व्यवधान) उनमें जवाब सुनने की क्षमता तक नहीं है ।... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): तुम्हारा यही चरित्र है । ... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस, करो बहस कह रहे थे । ...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : अध्यक्ष जी, यह गलत है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको इजाजत नहीं है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What have I done? They can go out, should I not say?… (*Interruptions*) Sir, Customs Duty on masoor has been reduced. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैडम, प्लीज बैठिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: पिछले एक सप्ताह और उससे पहले भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले, कांग्रेस, हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बार-बार बोल रहे थे, जब तक कोविड से वापस आउंगी तब तक प्लीज सह जाइए । अब आपकी अनुमति से चर्चा हो रही है । मुझे शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी आप स्वस्थ रहो । वह जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं और निकल गए, पूरी कांग्रेस निकल गयी । एक विषय अंदर और बाहर जाकर दूसरा विषय । जब चर्चा होती है तो इधर नहीं रहते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है । सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा करने का मन नहीं है । अभी चर्चा हो रही है, इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र स्पष्ट हो रहा है । इनफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमने और कदम उठाए हैं, मसूर दल पर कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट करने पर 30 परसेंट तक था । हम दलहन को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे देश में किसान दलहन का उत्पादन अच्छा करें । पहले 30 परसेंट ड्यूटी थी । हमें दलहन चाहिए, मसूर दाल चाहिए, इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी 30 परसेंट से कम होकर जीरो आ गयी है । मसूर दाल को सस्ते में इम्पोर्ट कर सकते हैं, वह मिलेगी । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सीनियर मेंबर हैं, ऐसे बीच में नहीं बोलिए ।

… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): … (*Interruptions*) For how long are we going to import edible oils and pulses? … (*Interruptions*) I myself being the Chairman of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I fully recognise; I understand your question. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: So, I want to know this. … (*Interruptions*) When and in what manner are we going to be self-sufficient so far as edible oils and pulses are concerned ?. … (*Interruptions*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, आज इस परिस्थिति में इनफ्लेशन को तुरंत कम करना है । पिछले दो-तीन सालों से दलहन और तिलहन के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं । हर स्टेट में हर मंत्री के साथ बात करके इसके उत्पादन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं । आज हम प्राइस राइज के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तुरंत हमें जनता को सस्ते में पहुंचाना चाहिए, इसीलिए इम्पोर्ट को अलग कर रहे हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसान के खिलाफ जा रहे हैं । किसान को जितना भी प्रोत्साहन देना है, जितना भी दलहन और तिलहन के लिए बोनस वगैरह देना है, उसे जरूर देंगे । **Similarly, customs duty on steel was rationalised significantly. I know that Pinaki *ji* raised an issue; I will address that. Further, customs duty was exempted on iron and steel scrap, while customs duty was also rationalised on copper scrap.** यह क्यों इम्पोर्टेन्ट है?

एमएसएमई का रॉ मेटेरियल में प्राइसेस हाई होने से उनको बिजनेस करने में बहुत दिक्कत थी, उनका बहुत सारा रिप्रजेन्टेशन मिला, इसीलिए उनको रॉ मेटेरियल सस्ता मिले, इसके लिए कस्टम ड्यूटी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर से हटाया गया । **Customs duty has also been exempted on coal, met coke, coking coal and ferronickel.** ये सब भी स्टील इंडस्ट्री को चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्री को भी चाहिए, उनकी सुविधा के लिए उन विषयों में भी हमने कस्टम ड्यूटी को कम करवाया, फिर स्टील प्राइसेज, डोमेस्टिक मार्केट में अभी गिरावट है, क्योंकि उसमें वन टेंथ की कमी हुई है । **We have reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot-rolled coil steel at the traders' end have slipped by about eight per cent or about Rs.5,500 per tonne since May 18.**

So, top steel makers have also quoted prices for June that are lower by Rs.4,500 or Rs. 5,500 a tonne. इसका सरासर बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा और उनके कारोबार के अच्छा चलने से इकोनामी भी बेनिफिट उठा सकेगी ।

In textile, Customs Duty on key raw products, like nylon chips, nylon yarn, and caprolactam, has been rationalised. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fibre, PTA, and other fibres and yarns so that the raw material for textile industry will also be available.

Customs Duty on raw cotton has also been fully exempted. रॉ कॉटन की बहुत डिमांड है । आजकल टैक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत चर्चा है । मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूं, जिससे इन्फलेशन कंट्रोल हो और सस्ता रॉ मैटीरियल हमारे लोगों को मिले, इसके लिए हमने बहुत कदम उठाए हैं । 38 lakh MT of free foodgrains were provided every month, for eight months, to 75.8 crore beneficiaries. यह हम सबको मालूम है । इस साल दिसंबर 2022 तक हमने एनाउंस कर दिया है ।

एक विषय के बारे में माननीय अधीर जी ने पूछा था, लेकिन वह निकल गए । सीपीआई के बारे में बात करें, डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें । सर, वर्ष 2012-13 में सीपीआई बेस्ड इन्फलेशन 10.5 था, वर्ष 2013-14 में 9.38 परसेंट था । वर्ष 2014-15 में 5.83 परसेंट, वर्ष 2015-16 में 4.91 परसेंट था । इसी तरह से हमारे कार्यकाल में 6.16 परसेंट वर्ष 2020-21 में पहुंचा लेकिन 10 फीसदी की तुलना में कुछ भी नहीं था । 10 फीसदी वर्ष 2012-13 में था, यह याद रखना चाहिए ।

मैं एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में बोलना चाहती हूं । वर्ष 2011-12, 2012-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 परसेंट था, अभी वर्ष 2019-20 में 7.35 परसेंट है । हर लिस्ट में अभी जो रेट है, चाहे फूड ग्रुप हो, पान-सुपारी, टोबेको, फ्यूल लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोदिंग हो, फुटवियर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है । वह डबल डिजिट में है और अभी हम सिंगल डिजिट में हैं । मैं यह सब याद दिलाने के लिए बोल रही हूं ।

एक और विषय है । माननीय सदस्यगण हमें विदेश से बार-बार कम्पेयर कर रहे हैं और रघुराम राजन जी के बयान के बारे में बोला गया कि भारत देश के हालात श्रीलंका से बैटर है, बांग्लादेश से बैटर है । यह रघुराम राजन जी का बयान है । लोग बहुत बार बोलते हैं कि बांग्लादेश को देखो, हमसे अच्छा चल रहा है, हम रुक गए हैं । ... (व्यवधान)

मैं सिर्फ एक-आध सच्चाई हाउस के सामने रखना चाहती हूं । आज बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन डॉलर के लोन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्राब्लम है । बांग्लादेश को कम्पेयर करने वाले यह भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ से 4.5 बिलियन मांग रहा है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपको ज्यादा समस्या है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: जब जवाब मिल रहा है और उस जवाब से यह पता चल रहा है कि भारत देश के हालात बहुत बेहतर हैं तो कहा जा रहा है कि आप बांग्लादेश के साथ क्यों कंपेयर कर रही हैं? बांग्लादेश से कंपेयर करने वाले कई लोग हमारे सामने नहीं हैं,

जो हमें बोलते थे कि बांग्लादेश को देखो, पीपीटी (परचेजिंग पावर पैरिटी) की इंकम देखो, जीडीपी पर-कैपिटा देखो और जीडीपी कितना है देखो, बोलने वाले आज मेरे सामने दिख रहे हैं । मैं उनके लिए जवाब दे रही हूं ।... (व्यवधान) आज श्रीलंका 3.5 बिलियन डॉलर आईएमएफ के सामने मांग रहा है । पाकिस्तान के बारे में, आईएमएफ के उनके अपने ही प्रेस रिपोर्ट में से टोटली एक-एक स्टेज पर एक-एक अमाउंट कुल मिलाकर पाकिस्तान 7 बिलयन डॉलर आईएमएफ के सामने मांग रहा है । भारत देश के हालात ऐसे नहीं हैं । हमारे पास पूरे रिसोर्सेज हैं । इसीलिए, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स परफेक्ट है ।

मैं दोबारा कोट करना चाहती हूं । रघुराम राजन जी ने भी आरबीआई को क्रेडिट करते हुए बोला था । ... (व्यवधान) यह सिर्फ इधर नहीं है । पार्लियामेंट में भी क्वैश्चयन्स में पूछा गया है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीधा बैठिए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको कह रहा हूं । आप सदन में कैसे बैठते हैं, उसकी गरिमा बनाकर रखें । पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठा जाता कभी ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैं नाम से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा । इसलिए, इशारों में समझ जाइए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हैं? इसी विषय के ऊपर सदन में ऑपोजिशन के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है । क्या नहीं बोला है? जब मैं जवाब दे रही हूं, तो कह रहे हैं कि आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हैं?

सर, सभी देश अच्छे रहने चाहिए । मैं किसी देश का बुरा नहीं चाह रही हूं । श्रीलंका हो या बांग्लोदश, सभी देश अच्छे रहने चाहिए । लेकिन, हमें टोक-टोक कर बोला गया हमारा देश भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा । शर्म है, ऐसे बात करने वाले नेतागण पर ... (व्यवधान) What happened? ... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The main concern is with regard to GST on foodgrains. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will answer all that. ... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Now, already one hour is over. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको मैंने एलाऊ नहीं किया है । माननीय मंत्री जी आप क्यों बैठ गईं? मैंने उनको एलाऊ नहीं किया है । ऐसे तो सभी प्रश्न पूछने लगेंगे ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, please allow me to speak. She took my name. … (*Interruptions*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मुझे दु:ख है कि पांच घंटे विवाद और डिस्कशन्स चल सकते हैं, लेकिन जवाब थोड़ा लंबा हो गया, तो एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि एक घंटा हो गया । Come on, Premachandran *Ji.* मैं हरेक प्वाइंट के लिए जवाब दे रही हूं । जवाब लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाये गए हैं, उनके जवाब देने हैं या नहीं देने हैं?

सर, यह भी कहा गया कि आप आज के हालात में डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए देखें तो अभी भी लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज्यादा है । हमें कहा गया कि आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया । मैं बोलना चाह रही हूं कि लॉकडाउन के समय और उसके बाद 'आत्मनिर्भर भारत' के एनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत लोगों ने सुझाव दिए कि करेंसी प्रिंट करो और प्रिंट करके सबको बांटो! जनता के साथ न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो! यह सब आया । … (व्यवधान) मुझे बोला गया कि डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गया? आपने प्रिंट किया इसलिए हुआ । सॉरी, आप डेटा लीजिए और फैक्ट्स हाथ में रखकर बात कीजिए ।… (व्यवधान) वर्ष 2018-19 में इंडिया में एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी 22 परसेंट था । यह मैं सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूं, जिससे समझ में आता है कि कितना प्रिंटेड है ।

वर्ष 2019-20 में 27 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 29 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 26 प्रतिशत है, ये हमारे रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के बारे में है । यूएस से कंपेयर करिए । बांग्लादेश और श्रीलंका क्या चीज है, यूएस से कंपेयर कीजिए । ऐसा बोलने वाले प्लीज गौर से सुनिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो मुझे बता दीजिए । उनको मत सुनाइए ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, वर्ष 2018-19 में यूएस के सेन्ट्रल बैंक की बैलेंस शीट की जीडीपी का प्रतिशत 20 था । वर्ष 2019-20 में 19 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 35 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 37 प्रतिशत है, जबकि हमारा 26 प्रतिशत है ।

यूरोजोन वर्ष 2018-19 में 39 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 39 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 42 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 67 प्रतिशत है । प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर देखिए । यह

उनके सेन्ट्रल बैंक की बैलेंस शीट है, हमारी नहीं है । हम अच्छे प्लान्स टारगेट करते हैं, जिनके हाथ में मदद पहुंचनी चाहिए, उन तक मदद पहुंचाई है, इसीलिए इकोनॉमी बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है । ...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदय, इश्यू तो प्राइस राइस का है ।...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाए हैं । उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा किसी को भी अलाऊ नहीं किया है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, शायद अभी यहां पर मनीष तिवारी जी नहीं हैं, मगर उन्होंने जीएसटी के बारे में बोलते हुए कहा कि जीएसटी एकदम फेल्योर है । मैं उनका जवाब देना चाहती हूं । जीएसटी के ऊपर एक कंपनी (Deloittes) ने losZ किया और उन्होंने कहा कि ninety per cent of Indian industry leaders feel that the GST has made doing business easier by bringing down barriers across the country.

उन्होंने यह भी कहा कि the GST regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end-consumers and along with helping companies, they optimised their supply chains. जीएसटी के बारे में स्टडीज़ के द्वारा जो जानकारी आ रही है, मैं उसको आपके सामने रख रही हूं ।

उनका एमएसएमई के बारे में बहुत कंसर्न था ।...(व्यवधान) मैंने एमएसएमई के बारे में बता दिया है कि किन-किन तरीकों से रॉ मैटेरियल सस्ते करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह भी बोलना चाहती हूं कि उनको पैनडेमिक के समय इमरजेन्सी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम दी गई । That has saved. यह एसबीआई के रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स हैं । 13.5 lakh MSMEs worth Rs. 1.8 lakh crore have been saved from slipping to be NPAs. 13.5 लाख एमएसएमईज़ को 1.8 लाख करोड़ रुपये पहुंचाकर उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया । This is equivalent to 14 per cent of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA.

महोदय, मेरे पास आरबीआई डेटा भी है, जो उनके लिए उपयोगी है । ये बात बार-बार उठाई गई कि आप पेट्रोल-डीजल में सेस के द्वारा बहुत कमा रहे हैं । इतना कमा लिया, वह कहां चला गया, यह मालूम नहीं चल रहा है, स्टेट्स को कम मिल रहा है । मैं आप सबके सामने आरबीआई का डेटा क्वोट करना चाहती हूं ।

The RBI data says total developmental expenditure incurred by the Modi Government between 2014-2022 is Rs. 90.9 lakh crore far higher than what is being alleged by some sections of the Opposition. In contrast, Rs. 49.2 lakh crore was spent between 2004-2014.

-

-

20.00 hrs

वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच में डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर 49.2 लाख करोड़ रुपये था । Whereas during the period from 2014-22, a sum of Rs. 90.9 lakh crore have been spent on development expenditure. जो पैसा एक्साइज तथा सेस के रूप में कलेक्ट किया जाता है, वह सारा पैसा डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर के लिए जाता है । केन्द्र सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन जमीन राज्य सरकारों के पास है इसलिए वहां पर डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर होता है और वह पूरा पैसा वहीं पर जाता है । ये बोलते हैं कि केन्द्र सरकार ने पैसा कमाया, वह पैसा किसकी जेब में गया । वह पैसा किसी की जेब में नहीं गया । वह पैसा हर राज्य के डेवलपमेंट में गया है ।... (व्यवधान)

सर, ये फूड एंड फ्यूल के ऊपर कहते हैं । ये कहते हैं कि यह ठीक है कि डेवलपमेंट रोड बना दी, लेकिन गरीब का ध्यान नहीं रखा गया है । हम कहते हैं कि गरीब का ध्यान बिल्कुल रखा गया है । मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ । Expenditure incurred by our Government includes Rs. 24.85 lakh crore spent on food, fertilizer and fuel and a sum of Rs. 26.3 lakh crore on capital creation. Over the 10 years of UPA, only Rs. 13.9 lakh crore were spent on subsidies. ये हमें बार-बार बोलते हैं कि मनरेगा में यह कर दिया, किसी और में यह कर दिया, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया । आपने आपके 10 सालों में सिर्फ 13.9 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए थे । हमने 24.85 लाख करोड़ रुपये ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर पर खर्च किए और 26.3 लाख करोड़ रुपये कैपिटल क्रिएशन पर खर्च किए । ... (व्यवधान)

सर, एक्सट्रीम पावर्टी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है । ये कहते हैं कि एक्सट्रीम पावर्टी के कारण लोग पेंडेमिक में मर गए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया । यह सच नहीं है । अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है । While soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP Report said that chances are that those in India, particularly those who are earning 1.9 dollars per day slipping into poverty due to this upturn would be zero. भारत में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या जीरो होगी । यह यूएनडीपी

की रिपोर्ट है । उसमें यह भी बोला गया है कि **recent comparative assessment of price and income support measures show that targeted transfers not only helped poorer households cope with price spikes, but also have significantly lowered the impact of carbon emission.**

हमारी सब्सिडी देने वाली उस स्कीम की सराहना करते हुए यूएनडीपी रिपोर्ट बोल रही है कि गरीबी रेखा के नीचे भारत के जीरो परसेंट लोग होंगे । हमें यह रिस्क नहीं है ।... (व्यवधान)

सर, आईएमएफ का भी इश्यू है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही हूँ । **Specifically on GST, item by item.** इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ । **First, GST on pencil.** माननीय सांसद कनिमोझी जी ने एक विषय रेज़ किया कि यूपी से एक लड़की ने प्रधान मंत्री जी को पेन्सिल के ऊपर एक चिट्ठी लिखी ।

First of all, I want to say कि पेन्सिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया है । बच्ची ने लिखा है, वह ठीक है, लेकिन बच्ची ने माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि उन तक लेटर पहुंचेगा, वे सुनेंगे और उनको जो करना है, उसे वे करने के लिए तैयार रहेंगे । उस बच्ची के मन में किसी और को लेटर लिखने का विचार तो नहीं आया । हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए । मैं यह बात बोलना चाहती हूँ ।... (व्यवधान) मैं इसका जवाब तमिल में भी दूंगी ।... (व्यवधान) कनिमोझी जी ने बहुत पैशनेटली तरीके से विषयों को उठाया है ।

बाकी पेन के ऊपर, पेंसिल शॉर्पनर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर जीएसटी लगाने की बात पर मैं आती हूं । ... (व्यवधान) हाँ, क्रेमेटोरियम के ऊपर भी आती हूं । ... (व्यवधान)

***On 3rd November 2021, Hon Prime Minister Modi reduced the Cess on Petrol by Rs. 5 and the Cess on Diesel was reduced by Rs.10. In May 2022, The Union Government reduced the Cess on Petrol by Rs. 9.50 and the Cess on Diesel was reduced by Rs. 7 per litre. On the same day, it was announced by the Union Government that Rs 200 will be given as subsidy to LPG Ujjwala customers.* ... (*Interruptions*)**

I do not know if you are getting the translation.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: *At the time of election, that's before coming to power in Tamil Nadu, the DMK stated in their election manifesto that they will be reducing the Price of Petrol by Rs 5 per litre. They also promised to reduce Rs 4 per litre for Diesel.*

Sir, I am continuing. … (*Interruptions*) Sir, I am not allowed to talk. I do not want interruptions.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Where is the black money coming from? … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: *The State Government also said that they will be giving an amount of Rs 100 as subsidy per LPG cylinder. It was promised to give Rs 100 as subsidy. These two have happened.*

Sir, I cannot shout. I am very weak. … (*Interruptions*) Sir, this is outrageous. Sir, if I am like before, I can shout but I am not able to shout now. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, केवल आपकी ही बात रिकॉर्ड में जा रही है, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

… (व्यवधान) …*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is purposely trying to disrupt me because I am telling the truth. If they have objection, they should speak afterwards. … (*Interruptions*) Thank you.

****I should listen to all those things which they said. You should not disturb my speech. This is not good politics. You should listen to what I say. I was listening to what all you said.****

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): You do not know how to talk. You fight. You do not know how to talk. … (*Interruptions*) You are arrogant.… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you. … (*Interruptions*)

20.09 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members left the House.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह क्या है, सर? ... (व्यवधान) सर, क्योंकि तमिल में इतना स्पष्ट बोला है कि हमारी सरकार बच्चों की पेंसिल के ऊपर, दूध के ऊपर तो मैं जरूर इसको भी तमिल में कहना चाह रही हूं । चाहे वे इधर नहीं हैं तो बाहर जाकर सुन लें । वह गलत बोलने वाले विषय हैं । उनके मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया गया, वह उन्होंने नहीं किया, ऊपर से हमसे पूछ रहे हैं । एक दुख का विषय मैं यह भी बोलना चाह रही हूं कि जब पत्रकार लोगों ने उनसे जाकर पूछा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में बोला है तो आपने कम क्यों नहीं किया? केन्द्र सरकार यह दो बार कर चुकी है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया?

When the Journalists asked the State Government of Tamil Nadu, that even after the Union Government had reduced the Cess on Petrol twice, why have they not reduced the price? A Minister from Tamil Nadu Government said that no date was mentioned for this price reduction. Just that was stated by them.

उस समय क्या हमने कुछ डेट दी है? They said it, that is all. तारीख नहीं बोली है कि तब तक करेंगे, लेकिन आपने मैनिफेस्टो में बोला था । केन्द्र सरकार ने दो बार काटा, लेकिन आप कम नहीं कर रहे हो । जब मीडिया पूछ रही है तो आप जवाब यही दे रहे हैं कि हमने डेट थोड़े ही न दी है, लेकिन करेंगे । सर, यह जवाब है ।

वे लोग मुझे ऐरोगेंट बोल रहे हैं । I do not mind if you call me arrogant. मगर जवाब जनता के लिए जो आज मैं बोलने वाली थी कि क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर शायद वह अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स मानकर निकाला गया, लेकिन वही हो रहा है ।

This is like shedding crocodile tears. Union Government shall reduce but I won't reduce. Whether I have stated any date. This was their statement.

यह भी बोला गया और उनके हाउस में बोला गया कि डीजल के लिए तो हमने करने के लिए बोला है, मगर हम नहीं कर पा रहे हैं । कितने लोग डीजल का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पास वह नंबर्स नहीं है । हमने कम करने के लिए जो वायदा किया, वह कर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं । आखिर में कुछ भी कटौती नहीं हुई । केन्द्र सरकार के द्वारा दो बार कटौती होने के बाद भी उन्होंने कम नहीं किया । आज खड़े होकर हमसे बार-बार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बारे में पूछ रहे हैं । एलपीजी के लिए भी सब्सिडी देने के लिए बोला गया, लेकिन कहा गया कि हम नहीं देंगे ।

Before putting the blame on the Union Government you should state as to why you have not fulfilled your promises. We have reduced twice. But you have not reduced at least once.

आपने दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया, यह कहने वाले डीएमके के नेतागण को मैं पूछ रही हूं कि हमने क्लीयर्ली बोला है कि ब्रांडेड दूध के ऊपर लगेगा । अगर आप लूज में दूध खरीदिए तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है । केन्द्र सरकार के ऊपर इतनी टिप्पणी करने वाली डीएमके सरकार ने क्या किया है? मैं ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर बोल रही हूं । लूज आइटम्स के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं है । मान लीजिए कि एक केजी दही खरीदना है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर डीएमके को बताना है तो उनकी भाषा में बताइए ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: *They say today that the price of milk has been raised due to increase in GST.

DMK Government is blaming the Union Government for increasing the GST. GST Council has decided this in which your State's Finance Minister is also a part of it. Modi Ji has not decided this. Five percent GST is to be levied only on branded items. It has come in Newpapers. If you buy one Kg of Curd. Rs 100 is the earlier price. If you put 5 per cent tax on it, then the price will be Rs 105. But you are selling at Rs 120. GST Council only asked you to put 5 percent. But you are putting more.

Lassi should be sold at Rs 27. As a branded item if you add 5 per cent GST, it should be sold at Rs 28.35. But you are selling it at Rs, 30. You are just putting the blame of GST council. Whereas you are indirectly putting the burden on common people.

Butter milk was sold at Rs 10. If you add 5 per cent GST then it should be sold at Rs 10.50. But you are selling at Rs 12. Whether this is justified.? You are just putting the blame on GST Council and selling it at a high price. Union Government is not responsible. Your Finance Minister is also part of this GST Council. This was an unanimous decision. There is nothing new to add burden to poor people. In every branded, if the GST Council stated to add 5 per cent, you add more than 5 per cent to each item. This is wrongdoing. *

Sir, now, I come to the general issues of GST. I want to tell you the recent decision taken in the GST Council on milk or any other item. All these items have been discussed by the GST Council in full detail. I just want to highlight the fact that any GST Council decision is a decision of the GST Council in which all the Ministers are present. टू-थर्ड उनकी वोटिंग होती है, वन-थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है । वोटिंग नहीं हुई, कंसेन्सस से डिसिजन हुआ । मैं सिर्फ यह बात रखना चाह रही हूं । ...(व्यवधान) राज्य वित्त मंत्रीगण बैठते हैं । इसको एंटी पुअर कहने वाले, मैं एक मिनट में, I want to explain it. Levy is only on pre-packaged items, labelled goods, and not on loosely sold items. So poor people पर इसका कुछ असर नही होगा । Similarly, 25 किलोग्राम पैकेट्स के ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होलसेल व्यापारी से व्यापारी बिना टैक्स उसे लाकर, अपने किराना शॉप्स में रख कर, छोटी-छोटी क्वांटिटिज में गरीबों को बेचने के लिए, जब वे 25 किलोग्राम लेते हैं, उसके ऊपर भी होलसेलर्स को टैक्स नहीं है । वे उधर से लाकर अपनी दुकान में रखेंगे । इसीलिए 25 के.जी. के पैकैट्स के ऊपर भी, लूज में बेचने के लिए, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है । इसीलिए मैं यह बात जरूर कहना चाह रही हूं कि लूज में दूध हो, चावल हो, पफ्ड राइस हो, बार्ली हो, इन सभी के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है । गरीबों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया । सिर्फ पहले से पैक्ड हो कर, उसमें ब्रांड का कुछ नाम है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, उनके ऊपर ही टैक्स है । आप सामान एक बोरी में ले आइए, उसे बेचें, उस पर कुछ टैक्स नहीं है । यह याद रखना चाहिए ।...(व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI: There should not be any discrepancy ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: There is no discrepancy, and every Minister has sat through it.

Sir, I want to tell you that हम इस डिसिजन पर कैसे पहुंचे । इस में तीन लेवल पर डिसकशन हुआ । फिटमेंट कमेटी में अधिकारीगण बैठते हैं, उसमें राजस्थान से भी अधिकारी हैं, वेस्ट बंगाल से भी अधिकारी हैं, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात, सभी अधिकारीगण बैठते हैं । उसके बाद यह इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती है । ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के, मिनिस्टर्स बैठते हैं, वे इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, फिर इसको काउंसिल में ले आते हैं ।

फिर इसको काउंसिल में लाते हैं । जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा इसके ऊपर भी है, जिसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम

बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल इन सारे राज्यों की भागीदारी है । इतने लेयर्स पर चर्चा के बाद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, दूसरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जब निर्णय लिये जाते हैं, सभी मंत्रिगण साथ बैठकर निर्णय लेते हैं, तो एक भी आवाज़ 'नहीं' की नहीं आई । सभी ने माना कि यह करेक्शन करना चाहिए । ठीक है । इसलिए एक भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था ।

अभी सुप्रिया जी यहाँ पर नहीं हैं । वे बोलीं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए । किसने इंकार किया और किसने क्या कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा । हर लेवल पर हम आगे बढ़कर आए और लीकेज कम करने के लिए हमने निर्णय लिया । मगर लीकेज कम करने के बहाने से गरीबों के ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डाला गया, उनको पहले जैसा ही मिलेगा । सिर्फ ब्रैंडेड आइटम्स के ऊपर ही हमने टैक्स लगाए ।

सर, ये लोग क्रिमेटोरियम के ऊपर बात कहते हैं और व्यंग्य से यह भी बोलते हैं कि क्या शव के ऊपर टैक्स डालोगे? मुझे ऐसी बयानबाजी करने वाले के लिए बहुत दुख होता है । उनके मंत्रिगण भी जीएसटी काउंसिल में बैठे हुए हैं । सिर्फ मैं बैठकर निर्णय नहीं करती हूँ । जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होते हैं, वे केन्द्र सरकार के निर्णय नहीं हैं, वे जीएसटी काउंसिल के निर्णय हैं । जब बात क्रिटिसिज्म करने की होती है, तो केन्द्र सरकार और मोदी जी को कह दो कि उसने जीएसटी में ऐसे कर दिया, जीएसटी में वैसे कर दिया । जीएसटी काउंसिल में सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के मंत्रिगण बैठते हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठकर निर्णय लेते हैं । वह उनका भी निर्णय है । उनको भी जाकर अपने स्टेट में बोलना चाहिए कि मैं भी उसमें बैठा था, इसमें मैंने भी सहमति दी है । वे क्यों नहीं बोलते हैं? अन्दर एक सहमति दे दो और बाहर जाकर केन्द्र सरकार के ऊपर डाल दो । यह गलत है । अन्दर तो दो-तीन लेवल पर आपने 'हाँ' करवाया और आज आप ऐसे पलट रहे हो, जैसे यह निर्णय मोदी जी ने लिया हो । जीएसटी काउंसलि में आप सब बैठे हैं । इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस विषय पर ये गलतफहमियाँ हैं, जिसे जरूर दूर करना चाहिए । **There is no GST on crematorium, funeral, mortuary, burial, or mortuary services.**

क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, मॉरचरी, बरिअल आदि सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है । फिर भी गोल-मोल करके वे कहेंगे कि अरे, शव के ऊपर भी टैक्स लगाओगे क्या? ऐसी बात कहने से कैसे होगा? **They are fully exempted from GST.**

ठीक है । ... (व्यवधान) आप रुकिए न, आपको क्या जल्दबाजी है? ... (व्यवधान) मैं क्रिमेटोरियम के संबंध में, यह बात रखना चाह रही हूँ कि **construction that may be carried out for a crematorium,** एक नया क्रिमेटोरियम बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इक्विप्मेंट्स ले आ रहे हो, स्टैंडर्ड रेट बढ़ाने वाले जो आइटम्स आते हैं, उनके ऊपर लगाते

हैं क्योंकि उनके रॉ-मटिरियल के ऊपर टैक्स बढ़कर ही आ रहा है । अगर इस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, तो बनाने वाले को नुकसान होगा, वह टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं ।

इसलिए क्रिमेटोरियम के लिए जब इक्विप्मेंट्स ले आते हो, तो उसके ऊपर टैक्स है क्योंकि बनाने वाले ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, नहीं तो वे नुकसान में आ जाएंगे । इसलिए समझना चाहिए कि इस पर पलटवार करके, गोल-मोल करके बेरहमी से बात करना, ऐसा कहना कि क्या शव के ऊपर टैक्स डालोगे, मैं कहना चाहूंगी कि आपके मंत्री लोग भी उधर बैठे हैं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, आप बैठ जाइए ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, ये चावल के ऊपर बोलते हैं, दूध के ऊपर बोलते हैं और लस्सी के ऊपर बोलते हैं कि क्या हम टैक्स लगा रहे हैं? ... (व्यवधान) नहीं, हमने इन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया है । इनको लूज में खरीदिए, इन पर टैक्स नहीं है । ... (व्यवधान) यह जरूर सुनने लायक विषय है, इसलिए आप सुनिए । ... (व्यवधान) क्या जीएसटी काउंसिल इस बार दूध के ऊपर, लस्सी के ऊपर, चावल के ऊपर मुरमुरा आलू, जिसे puffed rice या चिवड़ा बोलते हैं, क्या उसके ऊपर अभी टैक्स लगाया है? हम तो बोल रहे हैं कि इसे लूज में खरीदिए, इस पर टैक्स नहीं है । अगर प्री-पैक्ड, ब्रांडेड है, तो टैक्स है । ... (व्यवधान)

सर, जीएसटी आने से पहले हालात क्या थे? मैं एक बार इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं । मैं आइटम-वाइज बोल रही हूं । अभी बहुत सारे सदस्यगण यहां नहीं हैं । दाल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, मैदा-आटा के ऊपर, सूजी-रवा के ऊपर, बेसन के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही-लस्सी के ऊपर जीएसटी आने से पहले पंजाब में दाल के ऊपर 1.5 परसेंट वैट था, गेहूं के ऊपर परचेज टैक्स था, जो कि 5.5 परसेंट था, चावल के ऊपर 5.5 परसेंट टैक्स था, मैदा के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था, सूजी-रवा के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था, बेसन के ऊपर 1.5 परसेंट टैक्स था और पनीर के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था । यह पंजाब में प्री जीएसटी वैट की स्थिति थी और अब ये बात करते हैं । ... (व्यवधान)

तमिलनाडु में पल्सिस के ऊपर पांच परसेंट, आटा-मैदा के ऊपर पांच परसेंट, सूजी-रवा के ऊपर पांच परसेंट, बेसन के ऊपर पांच परसेंट और पनीर के ऊपर पांच परसेंट टैक्स था । वेस्ट बंगाल में भी पनीर के ऊपर पांच परसेंट टैक्स था । ... (व्यवधान)

महंगाई इसीलिए कम हो रही है, ये सब प्री-जीएसटी वाले विषय हैं । ... (व्यवधान) इनको थोड़ा सुनिए तो सही! ... (व्यवधान) तेलंगाना में पल्सिस के ऊपर पांच परसेंट, गेहूं

के ऊपर पांच परसेंट ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, आपस में बात न करें ।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : स्पीकर सर, तेलंगाना में दाल के ऊपर पांच परसेंट, गेहूं के ऊपर पांच परसेंट, चावल के ऊपर पांच परसेंट, आटा-मैदा के ऊपर पांच परसेंट, सूजी-रवा के ऊपर पांच परसेंट, बेसन के ऊपर पांच परसेंट और पनीर के ऊपर पांच परसेंट वैट था । जरा ये सभी स्टेट्स सोच लें कि आज वहां क्या हो रहा है । ... (व्यवधान)

सर, आंध्र प्रदेश में प्री-जीएसटी वैट पांच परसेंट हर आइटम के ऊपर था, चाहे वह दाल हो, गेहूं हो, चावल हो या मैदा-आटा हो । महाराष्ट्र में पनीर के ऊपर छ: परसेंट वैट था । ... (व्यवधान) हमारे मसूदी साहब के राज्य जेएंडके में दही के ऊपर 14.5 परसेंट वैट था । ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : आप सारे राज्यों में वैट के आंकड़े दे रही हैं । ... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : ऐसा ही हर स्टेट में हुआ करता था । ... (व्यवधान) मुख्य रूप से हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर बहुत ही चिंता व्यक्त की गई । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, मैंने आपको कई बार मौका दिया है । मैं अंतिम बार आपको चेतावनी दे रहा हूं । सदन व्यवस्था से चलता है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

कुंवर दानिश अली : सर, आप व्यवस्था देना चाहते हैं । Thank you very much, मैं यहां से चला जाता हूं ।

<u>18.29 hrs</u>

At this stage, Kunwar Danish Ali, left the House.

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, हॉस्पिटल बेड्स के बारे में कहा गया । यह कहा गया कि आईसीयू के ऊपर, हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया ।

अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जीएसटी काउंसिल ने हास्पिटल रूम रेंट, मगर आईसीयू का नहीं, उसका पांच परसेंट टैक्स, वह भी यदि पांच हजार रुपये से ज्यादा रूम रेंट रोज का आप दे रहे हैं, तो उस पर ही जीएसटी है । इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं है, आईसीयू पर भी जीएसटी नहीं है । ऐसी गलतफहमियां स्प्रेड न करें ।

महोदय, बहुत समय हो गया है, फिर भी जीएसटी कम्पेंसेशन के ऊपर भी बोलना चाहती हूं । कम्पेंसेशन सेस वर्ष 2026 तक एक्सटेंडेड है । सभी सेस जो राज्यों को देना है, वह मई, 2022 तक दे दिया । इस बार बजटरी प्रोविजन भी 1.2 लाख करोड़ रुपये कम्पेंसेशन का हमने किया हुआ है और 87 हजार करोड़ उसमें से ऑलरेडी राज्यों को दे दिया है ।

14 हजार करोड़ रुपये इंटरेस्ट ऑन बैक टू बैक लोन जो वर्ष 2020 में लिया, उसके इंटरेस्ट रेट के लिए हम दे रहे हैं । सिर्फ एक महीने जून का जीएसटी कम्पेंसेशन पेंडिंग है । वह हमने अभी तक इसीलिए क्लीयर नहीं किया क्योंकि बहुत सारे राज्यों के ए.जी. से सर्टिफाई हो कर सर्टिफिकेट हमें नहीं पहुंचा है । जब सर्टिफिकेट पहुंचेगा, तब हम क्लीयर कर देंगे इसीलिए जीएसटी के ऊपर पर्टिकुलर्ली तमिलनाडु के लोग बोले कि इतने सारे बाकी हैं, दे दो ।

GST payment to be released for Tamil Nadu is due only for June 2022. That too only Rs 2493 Crore. There is nothing due other than this amount. जून का कम्पेंसेशन ए.जी. का सर्टिफिकेट आने के बाद दे देंगे । महोदय, बहुत सारे अन्य विषय जैसे एटीएम के बारे में भी लोगों ने कहा कि हमारा पैसा निकालने पर ही टैक्स लग रहा है । ऐसा बिलकुल नहीं है । आपके अपने बैंक के एटीएम से आप महीने में पांच बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से आप पांच बार पैसा निकाल सकते हैं । कुल दस बार एक महीने में आप पैसा निकालो, आपके ऊपर कुछ भी पाबंदी नहीं है इसलिए गलतफहमी स्प्रेड मत करें । ऑयल बांड्स के विषय में जरूर कहना चाहती हूं क्योंकि पिनाकी जी ने यह बात निशिकांत जी को करेक्ट करते हुए कही कि आप तो गलत बोल रहे हैं । मैं सच्चाई रिकार्ड में रखना चाहती हूं । इनप्रिंसिपल ऑयल बांड गलत था क्योंकि तब लोगों को यह बोला गया कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए आपके तेल का प्राइस कम होगा लेकिन सब्सिडी नहीं दी । ऑयल मार्केट कम्पनी के ऊपर बोझ बनाकर लोन पर, बांड्स पर, ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज के ऊपर डाल दिया । उस समय लगा कि वह पैसा ऑयल मार्केटिंग कम्पनी उन्हें दे रही है जिसे सरकार को बजट द्वारा देना था । वह पैसा उनकी सब्सिडी नहीं है, अब मोदी जी उसकी भरपाई कर रहे हैं । तब का सब्सिडी अब मोदी जी की सब्सिडी बन रही है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कम्पनी का बांड है, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, न कि वे । वे छोड़कर चले गए । वर्ष 2005-06 में ऑयल बांड्स कितने इश्यू किए मतलब कितना खर्च या लोन उठाया । वर्ष 2005-06 में 17262, वर्ष 2006-07 में 24121, 2007-08 में 20 हजार के करीब, 2008-09 में 75 हजार के करीब, 2009-10 में 10 हजार के करीब । कुल मिलाकर 848186 टोटल बर्डन ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज के ऊपर था । उसकी रिपेमेंट वर्ष 2014 से मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई । अभी तक सिर्फ प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ ऑयल बांड्स 3500 करोड़ वर्ष

2014-15 में, इस बीच प्रिंसिपल नहीं दिया इसीलिए पिनाकी जी को गलतफहमी है कि कुछ नहीं दिया ।

अभी वर्ष 2021-22 में 38,723 करोड़ रुपये प्रिंसिपल दे रहे हैं । हम उसको पे कर रहे हैं । वर्ष 2022-23, इस साल में कुछ प्रिंसिपल पे नहीं करना है, इंटरेस्ट पे करेंगे । अगले साल 15,586 करोड़ रुपये हमें पे करना है । वर्ष 2024-25 में 39,000 करोड़ रुपये हमें पे करना है । वर्ष 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये हमें पे करना है । कुल मिलाकर 92,200 करोड़ रुपये मोदी सरकार ऑयल बांड के ऊपर दे रही है । पिनाकी मिश्रा जी, आप करेक्ट कर लीजिए । इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है, यह तो प्रिंसिपल का हो गया । वर्ष 2014-15 से 10,255 करोड़ रुपये, 9,989 करोड़ रुपये, एक-एक करके इस साल तक 79,958 करोड़ रुपये सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट उसमें गया । यह किसका पैसा है? उस समय कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं । मोदी जी उसका पेमेंट कर रहे हैं ।

क्या ऑयल बांड की वजह से हमारे ऊपर बर्डन नहीं है? ऐसा नहीं होता तो यह पैसा गरीब के पास जाने के लिए हमारे हाथ में रहता । यह प्रिंसिपली रांग है । ऑयल बांड फ्यूचर की जेनरेशन के ऊपर बर्डन लगाकर, मगर आप श्रेय लेकर चले गए । हमने तो आपके ऑयल प्राइस के लिए सब्सिडी दी है । यह गलत है । यह टोटली गलत है ।

अब मैं अंत में आती हूं । अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ । मैंने जरूर कोशिश की है कि सब लोगों के प्रश्न का जवाब दूं । सिर्फ एक विषय बार-बार हमारे ऊपर डालते हैं, इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूँ । ये कहते हैं कि मोदी सरकार अंबानी, अडाणी के लिए काम करती है । आप लोग यही करते हो । मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहती हूं ।

सर, आप राजस्थान से हैं । सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में इस साल 11 जून, 2022 में और इसके पहले 15 दिसंबर, 2021 में अशोक गहलोत जी, क्षमा कीजिए मैं नाम ले रही हूं, वे राजस्थान के सीएम साहब हैं, यह गलत नहीं है, उनकी कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लेकर 2,397 हेक्टेअर्स लैंड गवर्नमेंट ने अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग के लिए दी है । राजस्थान सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, अडाणी जी को लैंड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए दे दिया । अडाणी, अंबानी के चक्कर में हम नहीं आए । आप अडाणी जी को बुला-बुलाकर दे रहे हैं और दूसरा 15 दिसंबर, 2021 में एक अडाणी जी के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के साथ एमओयू साइन भी हुआ । 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क के लिए, यह जॉइंट पार्टनरशिप में है । यह सब बहुत महत्वपूर्ण है । ये दो विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि सिर्फ एक दिन पहले, इस एग्रीमेंट के एक दिन पहले माननीय लोक सभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अभी के नहीं, पूर्व अध्यक्ष ने जयपुर में जाकर कहा कि मोदी गवर्नमेंट अडाणी और अंबानी को फेवर करती है । ऐसा वे पब्लिक मीटिंग में कहकर निकल गए । अगले दिन गहलोत जी

अडाणी साहब के साथ एग्री कर रहे हैं । उनके अपने ही चीफ मिनिस्टर अंबानी, अडाणी को फेवर करते हुए इतने काम कर रहे हैं, जबकि माननीय पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में जाकर स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए अगले दिन अडाणी के साथ दो एग्रीमेंट हुए हैं और कांग्रेस वाले बार-बार इधर हमें टोकते हैं कि अंबानी, अडाणी का फेवर सरकार करती है । अरे, आपने बुलाकर दिया । ऐसे ही डीएमके, जो कांग्रेस के अलायंस में है ।

You are doing everything to Adani and Ambani. In Tamil Nadu, 59 MoUs worth 35000 Crore have been signed with Adani for setting a data centre.

तमिलनाडु में 59 एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 35,208 करोड़ रुपये का डेटा सेंटर सैटअप करने के लिए अडाणी के साथ वे भी हाथ मिला रहे हैं ।

तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार है । उधर भी वह कर रहे हैं, मगर बार-बार हमें बोलते हैं । दूसरा, एक और तमिलनाडु में है । सैकेंड फेज़ का डेटा सेंटर भी तमिलनाडु में अदानी ग्रुप ही कर रहा है । जब कांग्रेस वाले हमें अदानी-अदानी करके याद दिलाते हैं, ये सब उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए कि ये कौन हैं? सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपने मुझे बहुत टाइम दिया है । इलैक्ट्रिसिटी ड्यूज के ऊपर माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद बात बोली कि यह freebies की कल्चर से हमें निकलना चाहिए । स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोलने वाले जो जनरेटिंग कम्पनीज (जेनकोज़) और डिस्कॉम्स (डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज़) का बकाया है, वे क्लियर कर दें, नहीं तो वे लोग भी आपको पावर जनरेट करके कैसे देंगे? जनता को पावर चाहिए, इलैक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए । क्या रोक सकेंगे? तमिलनाडु में 20990 करोड़ रुपये जेनकोज़ का बाकी है, तेलंगाना में 7388 करोड़ रुपये बाकी है, राजस्थान 5043 करोड़ रुपये, झारखंड 3698 करोड़ रुपये जेनकोज़ के बाकी हैं । तेलंगाना में 11935 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 3677 करोड़ रुपये, पंजाब 2612 करोड़ रुपये, राजस्थान 1791 करोड़ रुपये, केरल 1278 करोड़ रुपये, ये सब बकाया उनका है । स्टेट्स को डिस्कॉम्स और जेनकोज़ को देना है ।

ऐसे ही सब्सिडी भी देते हैं । वह सब्सिडी भी वापस नहीं दे रहे हैं । वह रिसीऐबल के नाते डिस्कॉम्स के पास पंजाब से 9000 करोड़, राजस्थान से 15597 करोड़ और छत्तीसगढ़ 2699 करोड़ रुपया बकाया है । ये सब बकाया कौन देगा?

अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं, इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी, ग्लोबल दिक्कत, देश के अंदर दिक्कतों के बावजूद भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है । जीएसटी के बारे में बात करने वालों से मैं बार-बार हाथ जोड़कर पूछती हूं और समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टीट्यूशनली गिवन बॉडी है, जिसमें सभी स्टेट्स और केन्द्र सरकार बैठती है ।

उसमें निर्णय मोदी जी नहीं करते हैं । स्टेट्स के सभी फाइनेंस मिनिस्टर बैठ कर करते हैं । उनको अपने राज्य में जाकर वह सच्चाई बोलनी चाहिए, मगर वे नहीं बोलते हैं । अंदर एक विषय बोलते हैं लेकिन बाहर दूसरी बात करते हैं । इसके लिए भी मेरी विनम्र रिक्वैस्ट है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

20.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, August 2, 2022/Sravana 11, 1944 (Saka).

-

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

*** The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.**

*** Available in Master copy of Debate, placed in Library.**

*** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7283/17/22**

**** Introduced with the recommendation of the President.**

*** English translation of the Speech originally delivered in Tamil.**

*** Not recorded**

*** Not recorded**

*** Not recorded**

*** English translation of the Speech originally delivered in Tamil.**

*** Expunged as ordered by the Chair.**

*** English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.**

*** Not recorded**

*** English translation of the Speech originally delivered in Telugu.**

*** English translation of the Speech originally delivered in Bengali.**

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded

** English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

* English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

* English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

* Englsih translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

* Englsih translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.